राष्ट्रीय संस्करण

तुष्टीकरण की मिठाई खिलाती रही कांग्रेस सरकार, पाकिस्तान बरसाता रहा बम

>> 3

वर्ष 9 अंक 50

दैनिक जागरण

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, गुरुवार, 31 जुलाई, 2025

www.jagran.com

पृष्ठ 14

'मित्र' भारत पर ट्रंप का टैरिफ हमला

दिया झटका ▶ कहा, एक अगस्त से 25 प्रतिशत शुल्क के साथ ही पेनाल्टी भी देनी होगी

जयप्रकाश रंजन ● जागरण

- रूस से ईंधन और हथियारों की खरीद पर भी की टिप्पणी, कहा-यह सब सही नहीं
- पिछले साल दोनों देशों के बीच 132 अरब डालर का रहा था आपसी कारोबार

व्हाइट हाउस में दो अप्रैल 2025 को पारस्परिक टैरिफ की जानकारी देते डोनाल्ड ट्रंप। फाइल/रायटर

नई दिल्ली : एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयात पर 20-25 प्रतिशत शुल्क लगाने की बात कही थी और बुधवार को उन्होंने इस पर अमल करने की घोषणा भी कर दी। भारत को मित्र बताते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय आयात पर एक अगस्त से 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का एलान किया और यह धमकी भी दी कि इसके अतिरिक्त उस पर पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। उनका यह एलान अप्रत्याशित तो नहीं है, लेकिन यह ऐसे समय किया गया है, जब दोनों देशों की सरकारों के बीच शुल्क ढांचे पर वार्ता चल रही है। एकतरफा इस तरह की घोषणा भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी मुद्दों को लेकर तनावपूर्ण स्थिति को रेखांकित करती है। वहीं यह संकेत भी मिल रहा है कि भारत अमेरिका के दबाव में आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जिसका उल्लेख ट्रंप ने कई अवसरों पर किया है।

इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म 'ट्रुथ सोशल' पर की गई घोषणा में ट्रंप ने भारत की तरफ से अमेरिकी उत्पादों पर लगाए जाने वाले शुल्क की उच्च दरों, रूस से रक्षा उपकरणों और ईंधन की खरीद को लेकर भी आरोप लगाए हैं। ट्रंप ने बुधवार को कहा-भले ही भारत हमारा दोस्त है, लेकिन हमने पिछले कई वर्षों में उसके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा शुल्क लगाता है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा शुल्क लगाने वाले देशों में एक है। साथ ही भारत किसी भी देश की तुलना में सबसे कठिन और आपत्तिजनक गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाएं भी खड़ी करता है। भारत हमेशा से अपनी सैन्य उपकरणों की सबसे ज्यादा खरीद रूस से करता है। ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं रोके-ये सभी चीजें अच्छी नहीं हैं। इसलिए भारत को एक अगस्त से 25 प्रतिशत टैरिफ देना होगा। इसके अलावा आर्थिक जुर्माना भी देना होगा। बताते चलें, दोनों देशों के अधिकारियों के बीच पिछले तीन महीनों से लगातार बातचीत जारी है, लेकिन कृषि संबंधी क्षेत्र को खोलने के अमेरिकी दबाव के आगे भारत झुकने को तैयार नहीं है। भारत सरकार फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप की इस घोषणा की व्यापक समीक्षा कर रही है। लेकिन, जो तस्वीर सामने आ रही है, उससे यह संकेत मिल रहा है कि 25 प्रतिशत शुल्क और पेनाल्टी भारतीय कारोबारी हितों के लिए ठीक नहीं है। अमेरिका भारत का अहम रणनीतिक साझेदार देश होने के साथ ही सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार देश भी है। दोनों देशों के बीच वर्ष 2024 में द्विपक्षीय कारोबार 132 अरब डालर का रहा था। अमेरिकी आयात के मुकाबले भारत ने 41 अरब डालर का ज्यादा निर्यात अमेरिका को किया था।

ट्रंप ने संकेत दिया कि यदि एक अगस्त तक भारत के साथ व्यापार समझौता अंतिम रूप नहीं लेता तो टैरिफ के साथ-साथ अतिरिक्त पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। यह पेनाल्टी क्या होगी, स्पष्ट नहीं है। कुछ दिन पहले ब्राजील में जब ब्रिक्स शिखर सम्मलेन चल रहा था, तब ट्रंप ने इस संगठन के सभी सदस्य देशों (भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका) पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने की बात कही थी।

(पेज-10 भी देखें)

भारत ने कहा, किसान और राष्ट्रहित से कोई समझौता नहीं

भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के निर्यात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के फैसले पर ध्यान दिया है और वह इसके प्रभावों का अध्ययन कर रहा है। भारत किसान, एमएसएमई, उद्यमी और राष्ट्रहित के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) पर अमेरिका से वार्ता जारी है। सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी, जैसा कि अन्य व्यापार समझौतों में किया गया है। इसमें ब्रिटेन के साथ नवीनतम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता भी शामिल है।

निठारी कांड मामले में पंधेर व कोली के खिलाफ दायर सभी 14 अपीलें खारिज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सुप्रीम कोर्ट ने पंधेर और कोली को बरी करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया
- शीर्ष अदालत का फैसला सीबीआइ और पीड़ित परिवारों के लिए माना जा रहा बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट से सीबीआइ और निठारी कांड के पीड़ितों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इस मामले में अभियुक्त मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोली को बरी करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए सीबीआइ और शिकायतकर्ताओं की ओर से दाखिल सभी 14 अपीलें बुधवार को खारिज कर दीं। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद निठारी कांड लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि सिर्फ एक मामले में सुरेंद्र कोली को उम्रकैद की सजा मिली है, जो वह काट रहा है। सभी मामलों में दोनों आरोपित बरी हो चुके हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कोली जेल से बाहर नहीं आएगा।

29 दिसंबर, 2006 में नोएडा के निठारी में मोनिंदर सिंह पंधेर के घर के पीछे के एक नाले से आठ बच्चों के कंकाल मिलने के बाद यह हत्याकांड प्रकाश में आया था। इसके बाद पंधेर के घर के पीछे के नाले में और ज्यादा तलाशी और खोदाई के बाद और कंकाल मिले। इनमें से ज्यादातर अवशेष उस इलाके से लापता हुए गरीब बच्चों और युवतियों के थे। इस मामले को 10 दिन के भीतर ही सीबीआइ को सौंप दिया गया था। सीबीआइ ने जांच की तो और अधिक अवशेष मिले। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा पंधेर और कोली को बरी करने के फैसले के खिलाफ कुल 14 अपीलें सुनवाई पर लगी थीं। इनमें से 12 अपीलें सीबीआइ की थीं और दो अपीलें पीड़ित परिजनों पप्पू लाल और अनिल हलदर की ओर से दाखिल की गई थीं।

प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई में सभी अपीलें खारिज करते हुए कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कोई खामी नहीं है। इससे पहले कोर्ट ने सीबीआइ की ओर से पेश वकील राजा बी ठाकरे और पीड़ित परिवारों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गीता लूथरा से पूछा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में दिए गए निष्कर्षों में क्या गलत है?

जब सीबीआइ के वकील ठाकरे और गीता लूथरा ने अपहृत बच्चों की खोपड़ियों, अवशेषों और सामान की बरामदगी का जिक्र किया तो सीजेआइ ने कहा, एक भी ऐसा फैसला दिखाइए, जिसमें कहा गया हो कि पुलिस के सामने किसी आरोपित का बयान दर्ज किए बगैर की गई कोई भी बरामदगी कानूनन जायज है। कोर्ट ने कहा कि बरामद की गई वस्तुएं अभियुक्तों की हो सकती हैं, बशर्ते बरामदगी की जगह पहुंच केवल अभियुक्तों के लिए ही हो। जब लूथरा ने कहा कि 16 गरीब बच्चे लापता हो गए और ये खोपड़ियां और सामान नाले से बरामद किए गए हैं तो पीठ ने कहा, आप यहां हाई कोर्ट से अभियुक्तों को बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील में आई हैं। ऐसे में आपको साबित करना होगा कि हाई कोर्ट का फैसला गलत था।

साक्ष्य अधिनियम पर चीफ जस्टिस ने स्पष्ट की स्थिति पेज>>4

संपादकीय

धार्मिक विरासत के नाम पर राजनीतिक लड़ाई: थाइलैंड और कंबोडिया में भले ही संघर्ष विराम हो गया हो, लेकिन कहना कठिन है कि विवादित मामले का हमेशा के लिए पटाक्षेप हो जाएगा। **विवेक काटजू** का आलेख।

मजाक बनता एक गंभीर अपराध : तमाम महिलाएं वर्षों तक सहमति से संबंधों के बाद पुरुषों पर फर्जी आरोप लगाकर दुष्कर्म के मामले दर्ज करा रही हैं। **दीपिका नारायण भारद्वाज** का दृष्टिकोण। ● पेज-8

विमर्श

बच्चों की सुरक्षा को दी जाए प्राथमिकता : राजस्थान के झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरने से सात मासूमों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। **कैलाश बिश्नोई** का आलेख।

राहुल के जाते ही कांग्रेस 'सरेंडर' : बीते माह भोपाल आए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए एक विवादित बयान दिया था, लेकिन उनके लौटते ही कांग्रेस अपने पुराने ढर्रे पर आ गई। **धनंजय प्रताप सिंह** की मध्य प्रदेश डायरी। ● पेज-9

इंग्लिश चुनौती

आज का मैच (पांचवां टेस्ट)

भारत vs इंग्लैंड	स्थान
दोपहर 3:30 बजे	ओवल, लंदन

प्रसारण : सोनी नेटवर्क/जियो हाटस्टार

दैनिक जागरण सप्तरंग

तकनीक की दुनिया का

इंटेलिजेंस की फेक दुनिया

सेफ्टी या साउंड कैसे चुनें ईयरबड्स ● पेज-13

भाजपा सरकार ही वापस लाएगी गुलाम जम्मू-कश्मीर : शाह

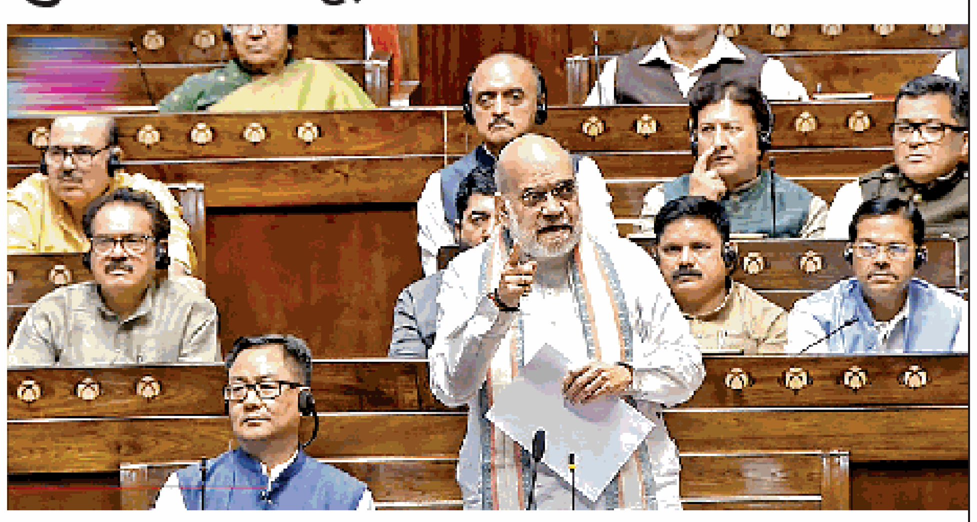

राज्यसभा में बुधवार को आपरेशन सिंदूर पर चर्चा में बोलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रेट्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- राज्यसभा में आपरेशन सिंदूर पर चर्चा का दिया जवाब
- कहा, अगले 30 वर्ष भाजपा की ही रहने वाली है सरकार
- कश्मीर में आतंकवाद समाप्ति की कगार पर, पूरा खत्म करके रहेंगे

आपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेसी सदस्यों द्वारा गुलाम जम्मू-कश्मीर वापस कब लाओगे के तंज का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को साफ किया कि गुलाम जम्मू-कश्मीर को वापस लाने का काम भाजपा सरकार ही करेगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि अगले 30 वर्ष तक भाजपा की ही सरकार रहने वाली है। आतंकवाद के पीछे कांग्रेस के तुष्टीकरण को जिम्मेदार ठहराते हुए शाह ने हिंदुओं को आतंकी साबित करने के लिए फर्जी केस बनाने का आरोप लगाते हुए शाह ने कहा, 'मैं गर्व से घोषणा करता हूं कि हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता।'

चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नहीं देने को लेकर विपक्ष के हंगामे और बहिर्गमन के बीच शाह ने गुलाम जम्मू-कश्मीर के लिए सीधे तौर पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि यदि नेहरू ने युद्धविराम नहीं किया होता और सेना को खुली छूट दी होती तो गुलाम जम्मू-कश्मीर भी भारत का हिस्सा होता। गुलाम जम्मू-कश्मीर आपने (कांग्रेस) दिया था, लेकिन इसे वापस लेने का काम भाजपा सरकार ही करेगी। गुलाम जम्मू-कश्मीर लिए बिना आपरेशन सिंदूर रोकने के विपक्षी दलों के आरोपों पर हैरानी जताते हुए उन्होंने कहा कि जब युद्ध शुरू ही नहीं हुआ तो युद्धविराम कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि आपरेशन सिंदूर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुरूप आत्मरक्षा के अधिकार के तहत शुरू किया गया। यह आपरेशन अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल रहा।

शाह ने पहलगाम हमले के आतंकियों के विरुद्ध आपरेशन का नाम महादेव रखने को लेकर आपत्ति जताने पर महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चह्वाण को भी आड़े हाथों लिया। चह्वाण ने आरोप लगाया था कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के उद्देश्य से आपरेशन का नाम महादेव रखा गया। शाह ने कहा, 'हर हर महादेव' शिवाजी महाराज का युद्धघोष था। यही नहीं, सेना की विभिन्न टुकड़ियों के अलग-अलग युद्धघोष धार्मिक प्रतीकों से जुड़े हैं, जिन्हें भाजपा ने नहीं बनाया है।

गृह मंत्री बोले, कांग्रेस की प्राथमिकता सुरक्षा नहीं, राजनीति है पेज>>3

बुलंदशहर उन्मादी भीड़ की हिंसा में भाजपा नेता समेत 38 दोषी

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर

- गोवंशियों के अवशेष मिलने पर भड़की भीड़ ने की थी हिंसा और आगजनी

38 दोषियों में जिला पंचायत सदस्य, भाजपा मंडल अध्यक्ष भी शामिल

- इंस्पेक्टर की हत्या में पांच दोषी, सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया

बुलंदशहर हिंसा कांड में फैसले के बाद दोषी योगेश राज को जेल ले जाती पुलिस। जागरण

<< बुलंदशहर के स्याना में हिंसा के दौरान पुलिस चौकी पर जलते वाहन। फाइल/जागरण आर्काइव

^ सुबोध कुमार की फाइल फोटो।

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में उन्मादी भीड़ की हिंसा के मामले में करीब साढ़े छह वर्ष बाद कोर्ट ने भाजपा नेता समेत 38 लोगों को दोषी करार दिया है। सजा के लिए कोर्ट ने एक अगस्त की तिथि नियत की है। जिले के स्याना कोतवाली के महाव गांव में गोवंशियों के अवशेष मिलने पर तीन दिसंबर, 2018 को उन्मादी भीड़ ने हिंसा और आगजनी की थी। इसमें स्याना कोतवाली के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार समेत दो लोगों की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने भाजपा नेता व मौजूदा जिला पंचायत सदस्य योगेश राज समेत 44 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इनमें से पांच की मौत हो चुकी है। एक बाल अपचारी रिहा हो चुका है। एडीजे-12 गोपाल जी ने दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। अदालत ने पांच लोगों को इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या का दोषी करार दिया है।

सरकारी अधिवक्ता यशपाल सिंह राघव ने बताया कि तीन दिसंबर, 2018 को जंगल में गोवंशियों के अवशेष मिले थे। इसी दौरान बुलंदशहर में आयोजित इज्तमा में गोवंशियों का मांस ले जाने की अफवाह उड़ गई। उसके बाद कई गांवों के ग्रामीण एवं हिंदू संगठनों के लोगों ने हंगामा करते हुए बुलंदशहर-स्याना मार्ग पर जाम लगा दिया। चिंगरावठी पुलिस चौकी पर पथराव करते हुए पुलिस के सरकारी व निजी वाहनों को जला दिया। हिंसा में स्याना कोतवाली प्रभारी सुबोध कुमार की उन्हीं की सरकारी पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी गई। हिंसा में चिंगरावठी निवासी सुमित की भी मौत हो गई। पुलिस ने 27 नामजद और 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

सुनवाई के दौरान आरोपित आशीष उर्फ छोटू, चंद्रपाल, अजय कुमार, ओमिंदर और कुलदीप की मृत्यु हो गई। बुधवार को कोर्ट ने आरोपित प्रशांत नट, राहुल, डेविड, लोकेंद्र और जोनी को तत्कालीन कोतवाल सुबोध कुमार की हत्या का दोषी करार दिया। 33 आरोपितों को जानलेवा हमले और हिंसा का दोषी करार दिया। 33 दोषियों में योगेश राज भाजपा का जिला पंचायत सदस्य, सतेन्द्र गांव लौंगा का प्रधान, सचिन अहलावत भाजपा बीबीनगर मंडल अध्यक्ष, पवन राजपूत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्याना नगर कार्यवाह है।

हर 12 दिन में धरती का नक्शा बनाएगा उपग्रह निसार

श्रीहरिकोटा : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के बीच साझेदारी के तहत बुधवार को जीएसएलवी राकेट की सफल उड़ान के साथ निसार उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया। यह उपग्रह 240 किमी चौड़े रडार क्षेत्र का उपयोग करके हर 12 दिन में धरती का मानचित्र बनाएगा। (पेज-5)

जागरण विशेष

अब जैविक पट्टी से जोड़ी जा सकेंगी टूटी हड्डियां

प्रयागराज : अंडे की सफेदी और मछली की हड्डियों से निकला जिलेटिन और धान की भूसी का उपयोग करके मनुष्य की हड्डियों को जोड़ा जा सकेगा। ● पेज-14

हादसे में लेफ्टि. कर्नल समेत दो सैन्यकर्मी बलिदान

राज्य ब्यूरो, जागरण ● जम्मू

- सैन्य काफिले में शामिल स्कार्पियो वाहन पर पहाड़ी से गिरी चट्टान
- पूर्वी लद्दाख में हुए हादसे में दो मेजर और कैप्टन भी घायल हो गए
- बलिदानी लेफ्टि. कर्नल भानु पठानकोट व दलजीत सिंह गुरदासपुर के निवासी

लेफ्टिनेंट कर्नल मनकोटिया। फाइल

लांस दफादार नायक दलजीत सिंह। फाइल

लद्दाख में बुधवार को सैन्य वाहन पर पहाड़ी से चट्टान गिरने से लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सैन्यकर्मी बलिदान हो गया तथा दो मेजर व कैप्टन सहित तीन अधिकारी घायल हो गए। ये सभी अधिकारी एक वाहन में सवार थे। घायल अधिकारियों को लेह के सैन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

बलिदान हुए सैन्य अधिकारियों की पहचान 14 सिंध हार्स बटालियन के लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह मनकोटिया निवासी पठानकोट (पंजाब) व लांस दफादार नायक दलजीत सिंह निवासी गुरदासपुर (पंजाब) के रूप में हुई है। हार्स बटालियन में लांस दफादार नायक का पद होता है। वहीं, घायलों में मेजर मयंक शुभम, मेजर अमित दीक्षित व कैप्टन गौरव शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार, पूर्वी लद्दाख के दुरबुक में सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे सेना का एक काफिला चोंगताश क्षेत्र की ओर जा रहा था। काफिले में शामिल सेना के एक स्कार्पियो वाहन पर पहाड़ी से चट्टान का बड़ा हिस्सा आ गिरा। इससे वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह दब गया। वाहन में पांच सैन्य अधिकारी सवार थे। अन्य वाहनों ने सवार जवानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पत्थर व मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला। हादसे में लेफ्टिनेंट कर्नल तथा लांस दफादार नायक बलिदान हो गए।

सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा व लद्दाख की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने देशसेवा करते हुए बलिदान देने वाले सैन्य अधिकारी व कर्मी की वीरता को सलाम किया है।

सुप्रीम फैसला

सड़क दुर्घटना से जुड़े एक मामले में शीर्ष अदालत ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला, कोयंबटूर में 2017 में सड़क दुर्घटना के लिए कार चालक को करार दिया दोषी

आपात स्थिति में भी हाईवे पर बिना चेतावनी ब्रेक लगाना लापरवाही

- अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रहे बाइक सवार का काटना पड़ा था एक पैर

दूरगामी असर वाला फैसला। प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर कोई कार चालक बिना किसी चेतावनी के राजमार्ग पर अचानक ब्रेक लगाता है तो उसे सड़क दुर्घटना की स्थिति में लापरवाही माना जा सकता है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने मंगलवार को कहा कि किसी चालक द्वारा राजमार्ग के बीच में अचानक वाहन रोकना, चाहे वह व्यक्तिगत आपातस्थिति के कारण ही क्यों न हुआ हो, उचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए खतरा हो सकता है। पीठ के लिए फैसला लिखने वाले जस्टिस धूलिया ने कहा, 'राजमार्ग पर वाहनों की तेज गति अपेक्षित है और यदि कोई चालक अपना वाहन रोकना चाहता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वह सड़क पर पीछे चल रहे अन्य वाहनों को चेतावनी या संकेत दे।'

यह फैसला इंजीनियरिंग के छात्र एस. मोहम्मद हकीम की याचिका पर आया है। सात जनवरी, 2017 को कोयंबटूर में एक सड़क दुर्घटना के बाद उसका बायां पैर काटना पड़ा था। यह घटना तब हुई, जब हकीम की मोटरसाइकिल एक कार के पिछले हिस्से से टकरा गई जो अचानक रुक गई थी। इस कारण हकीम सड़क पर गिर गया और पीछे से आ रही एक बस ने उसे टक्कर मार दी। कार चालक ने दावा किया था कि उसकी गर्भवती पत्नी को उल्टी जैसा महसूस हो रहा था इसलिए उसने अचानक ब्रेक लगाए थे। शीर्ष अदालत ने इस स्पष्टीकरण को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कार चालक द्वारा राजमार्ग के बीच में अचानक कार रोकने के लिए दिया गया स्पष्टीकरण किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। मुआवजा बढ़ाने की हकीम की याचिका स्वीकार करते हुए पीठ ने कहा, 'हमारे विचार में यह निष्कर्ष सही है कि अपीलकर्ता ने आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखने में निश्चित रूप से लापरवाही बरती और बिना वैध लाइसेंस के मोटरसाइकिल चलाई। लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि दुर्घटना का मूल कारण कार चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाना है।'

अदालत ने अपीलकर्ता को केवल 20 प्रतिशत की सीमा तक ही लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया, जबकि कार चालक और बस चालक को क्रमशः 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की सीमा तक लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया। अदालत ने मुआवजे की कुल राशि 1.14 करोड़ रुपये आंकी, लेकिन अपीलकर्ता की सहभागी लापरवाही के कारण इसे 20 प्रतिशत कम कर दिया। शेष राशि दोनों वाहनों की बीमा कंपनियों द्वारा चार सप्ताह के भीतर उसे भुगतान किया जाना है।

लापरवाही का आनुपातिक हिसाब

इस मामले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने कार चालक को दोषमुक्त करार दिया था और अपीलकर्ता व बस चालक की लापरवाही को 20:80 के अनुपात में निर्धारित किया। न्यायाधिकरण ने कार से पर्याप्त दूरी नहीं बनाए रखने के लिए अपीलकर्ता को 20 प्रतिशत लापरवाही का जिम्मेदार ठहराया। हालांकि, मद्रास हाई कोर्ट ने कार चालक व बस चालक को क्रमशः 40 व 30 प्रतिशत की सीमा तक और अपीलकर्ता को 30 प्रतिशत सहभागी लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया था।

****

बिल्डरों-बैंकों की साठगांठ मामले में सीबीआइ ने दर्ज की 22 प्राथमिकी

- घर खरीदारों से धोखाधड़ी की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

केस दर्ज करने के बाद एजेंसी ने एनसीआर में 47 स्थानों पर की थी छापेमारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीबीआइ ने एनसीआर में घर खरीदारों से धोखाधड़ी के लिए बिल्डरों और बैंकों के बीच साठगांठ से संबंधित मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 22 एफआइआर दर्ज की है। सीबीआइ प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद एनसीआर में 47 स्थानों पर छापेमारी की थी। सीबीआइ ने अलग-अलग एफआइआर में जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, अजनारा इंडिया लिमिटेड, वाटिका लिमिटेड, जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड, सुपरटेक व आइडिया बिल्डर्स समेत अन्य को नामजद किया है।

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआइ की आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में भारतीय स्टेट बैंक, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पीरामल फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जैसे बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के नाम भी शामिल हैं। सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ के निर्देशों के बाद यह कार्रवाई की है।

घर खरीदारों ने राहत पाने को खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा पेज>>10

33 योजनाओं पर किया जाएगा केंद्र सरकार से मिली 800 करोड़ से ज्यादा रुपये की विशेष सहायता का उपयोग जो स्वास्थ्य समेत अन्य जन सेवाओं से जुड़ी होंगी।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 31 जुलाई, 2025

आज का मौसम

बादल छाए रहेंगे। गर्जन वाले बादल बनने व बिजली चमकने की संभावना है। हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने के आसार हैं।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
31 जुलाई	31.0	24.0
1 अगस्त	31.0	24.0
नोएडा		
31 जुलाई	30.0	26.0
1 अगस्त	32.0	25.0
गुरुग्राम		
31 जुलाई	30.0	28.0
1 अगस्त	31.0	28.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

नाबालिग से कुकर्म मामले में दोषी को 10 साल की सजा

नई दिल्ली: तीस हजारी स्थित पाक्सो अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म करने के दोषी सूरज उर्फ शाहिद को 10 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि पीड़ित को दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए ताकि उसका पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिव्यांग ठाकुर ने कहा कि यह अपराध गंभीर प्रकृति का है और इसका गहरा मानसिक असर पीड़ित की पढ़ाई व सामान्य जीवन पर पड़ा है। (जासं)

'गिरफ्तारी की प्रक्रिया में चूक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन'

नई दिल्ली: अदालत ने सीबीआइ की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) द्वारा रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कस्टम विभाग के अधिकारी संदीप दलाल को जमानत दे दी है। अदालत ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए यह राहत दी। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा ने कहा कि गिरफ्तारी प्रक्रिया में की गई चूक आरोपित के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले में अब कोई नई रिकवरी शेष नहीं है। आरोपित सरकारी कर्मचारी है और फरार होने की संभावना नहीं है। (जासं)

'शादी के बाद बेटी के लिए अजनबी नहीं हो जाते स्वजन'

नई दिल्ली: दहेज के लिए प्रताड़ित करने के कारण महिला द्वारा आत्महत्या करने के मामले में आरोपित व्यक्ति को जमानत देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया। दहेज के लिए प्रताड़ित करने के बारे में मृतका के स्वजन की गवाही पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि शादी के बाद बेटी के स्वजन अजनबी नहीं हो जाते। अभियोजन पक्ष के अनुसार 18 वर्षीय मृतका हरदोई की रहने वाली थी। (जासं)

पीडब्ल्यूडी में नहीं चलेगा अब सस्ते में टेंडर व घटिया काम

नई व्यवस्था ▸ विभाग ने टेंडर प्रक्रिया में लाई पारदर्शिता और सख्ती, लागू की अतिरिक्त परफार्मेंस गारंटी व्यवस्था

परियोजनाओं को समय पर पूरा करना और गुणवत्ता बनाए रखना है उद्देश्य

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने राजधानी में ढांचागत परियोजनाओं को समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के उद्देश्य से नया कदम उठाया है। मंत्री प्रवेश वर्मा के निर्देश पर विभाग ने अब टेंडर प्रक्रिया में सख्ती लाने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है जिससे काम को लेकर गंभीर नहीं रहने वाले व घटिया काम करने वाले ठेकेदारों पर रोक लगाई जा सकेगी।

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित परियोजनाओं को तय समय और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के लिए एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। उन्होंने कहा किपिछले कुछ महीनों में विभाग ने यह पाया कि कुछ ठेकेदार मात्र टेंडर हासिल करने के लिए कम दरें कोट करते हैं। ऐसी बोली कागजों पर भले ही प्रतिस्पर्धी दिखें लेकिन वास्तविकता में ये परियोजनाओं में देरी, घटिया निर्माण कार्य या कई बार परियोजना के बीच में ही रुक जाने का कारण बनती हैं। इससे न सिर्फ आम जनता को असुविधा होती है बल्कि सरकारी खजाने पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ता है। ऐसी समस्याओं पर लगाम लगाने के लिए ही पीडब्ल्यूडी मंत्री ने सभी आगामी टेंडरों में एडिशनल परफार्मेंस गारंटी (एपीजी) की अनिवार्यता लागू करने का निर्णय लिया है जो असामान्य रूप से कम बोली लगाने वालों पर लागू होगा।

पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा। फाइल

यह निर्णय सिर्फ आर्थिक सुरक्षा के लिए नहीं है बल्कि यह जवाबदेही और जनधन के प्रति सम्मान का प्रतीक है। जब कोई ठेकेदार अव्यवहारिक रूप से कम राशि पर टेंडर लेता है और फिर काम अधूरा छोड़ देता है या घटिया गुणवत्ता का काम करता है तो नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है। हमारा लक्ष्य यह है कि जनता का एक-एक रुपया गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक कार्यों में बदले। - प्रवेश वर्मा, पीडब्ल्यूडी मंत्री, दिल्ली सरकार

जानिए क्या हैं नई शर्तें

एडिशनल परफार्मेंस गारंटी: ऐसे सभी टेंडर जिनमें सबसे कम बोली तय अनुमानित लागत से एक निश्चित प्रतिशत से अधिक नीचे होगी, उन्हें काम करने योग्य नहीं माना जाएगा। ऐसे ठेकेदारों को अतिरिक्त परफार्मेंस गारंटी देनी होगी जो उस अंतर के बराबर होगी जितना प्रतिशत उन्होंने निर्धारित सीमा से नीचे बोली लगाई है। यह गारंटी पहले से लागू सिक्योरिटी डिपाजिट और परफार्मेंस गारंटी के अतिरिक्त होगी। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य केवल सक्षम और वास्तविक ठेकेदारों को ही कार्य देना और सार्वजनिक कार्यों की गुणवत्ता व समयसीमा को सुनिश्चित करना है।

सशर्त कार्य आवंटन: ऐसे बोलीदाताओं को तब तक कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा जब तक वे निर्धारित समयसीमा के भीतर एपीजी जमा नहीं कर देते। समयसीमा का पालन न करने पर कार्य आदेश रद कर दिया जाएगा और विभागीय नियमों के तहत ठेकेदार को प्रतिबंधित किया जा सकता है यानी आगे उसे प्रोजेक्ट न देने की व्यवस्था होगी।

आइजीआइ पर टी-1 से टी-3/2 पर आसानी से पहुंच सकेंगे यात्री

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

ढांचागत विकास के मामले में आगे बढ़ रही दिल्ली सरकार जल्द ही इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 से टर्मिनल-3/2 के बीच आवागमन की समस्या को खत्म करेगी। यहां वाई आकार के फ्लाईओवर के निर्माण के साथ रनवे के नीचे सुरंग सड़क को दो गुना चौड़ा करने की योजना है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त करने को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को निर्देश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी जल्द ही इस कार्य के लिए टेंडर जारी करेगा।

पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए अभी माना जा रहा है कि रनवे के नीचे सुरंग-सड़क को मौजूदा छह लेन से दोगुना की जा सकती है जो टी-1 से टी-3/2 तक होगी। इन दोनों टर्मिनल के बीच की दूरी लगभग सात किमी है। इस तरह दोनों टर्मिनल के बीच के यात्रियों को आने-जाने में परेशानी कम होगी। इसके अलावा डायल भी प्रस्तावित हवाई ट्रेन की योजना पर काम शुरू नहीं कर सका है। योजना के अनुसार हवाई ट्रेन तैयार होने तक टर्मिनल-3 और टर्मिनल-1 के बीच यातायात की व्यवस्था संभालने के लिए डायल ने कुछ साल पहले एक वाई-आकार का फ्लाईओवर प्रस्तावित किया था। प्रस्तावित फ्लाईओवर, टर्मिनल-1 और इंदिरा गांधी रोड पर वर्तमान में जाम वाले एनएसजी चौराहे से लेकर टर्मिनल-1 और टर्मिनल-3 के बीच आवागमन को सिग्नल-मुक्त तो बनाएगा लेकिन वाहनों की बढ़ती आवाजाही से निपटने के लिए दोनों टर्मिनलों को जोड़ने वाली उत्तरी पहुंच मार्ग को चौड़ा करना होगा। इसमें मौजूदा सुरंग मार्ग को छह-लेन से 12 लेन का करना होगा।

खर्च हो सकते हैं 400 करोड़

सूत्रों के अनुसार पूरी परियोजना पर 400 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह सड़क लोक निर्माण विभाग की है इसलिए डायल ने दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों से संपर्क किया है। सूत्रों ने बताया कि इस परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा 20 प्रतिशत और केंद्र सरकार द्वारा शहरी विकास निधि से 80 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

'नमो भारत चैंपियंस' से यात्रियों को मिलेगा बेहतर यात्रा अनुभव

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों के अनुभव को और अधिक सहज, सुरक्षित और सहभागी बनाने की दिशा में एनसीआरटीसी ने एक नई पहल की शुरुआत की है। 'नमो भारत चैंपियंस' नामक इस कार्यक्रम का उद्देश्य यात्रियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना व सेवाओं में निरंतर सुधार लाना है।

एनसीआरटीसी के अनुसार यह कार्यक्रम 'यात्रियों के लिए, यात्रियों के द्वारा' की अवधारणा पर आधारित है। इसके तहत एक विशेष नेटवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें ऐसे यात्री शामिल होंगे जो नमो भारत ट्रेन सेवा का जिम्मेदारी से उपयोग करते हैं और सार्वजनिक परिवहन के सतत विकास में योगदान देना चाहते हैं। 'नमो भारत चैंपियंस' यात्री सुविधाओं को लेकर फीडबैक देंगे, ट्रेनों और स्टेशनों पर अनुसरण किए जाने वाले नियमों के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। जरूरत पड़ने पर अन्य यात्रियों की मदद करेंगे। एनसीआरटीसी इन्हें एक आधिकारिक पहचान प्रदान करेगा और सेवा अपडेट्स व कार्यक्रमों की प्राथमिक जानकारी भी देगा। इच्छुक यात्री स्टेशन पर लगाए गए क्यूआर कोड या एनसीआरटीसी की वेबसाइट और इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं। उनका उल्लेख 'नमो भारत टाइम्स' न्यूजलेटर में भी किया जाएगा।

केंद्र से दिल्ली को मिली 821.26 करोड़ रुपये की विशेष सहायता

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को बड़ी राहत के रूप में 821.26 करोड़ की विशेष सहायता राशि की मंजूरी दे दी है। बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने इसमें से 66 प्रतिशत राशि जारी भी कर दी है। केंद्र सरकार से मिली इस विशेष सहायता राशि से दिल्ली के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राजधानी को सही मायनों में 'विकसित दिल्ली' बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 'राज्यों के लिए पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना (एसएएससीआइ) 2025-26 के अंतर्गत दिल्ली के विकास के लिए यह राशि मंजूर की है। इसका उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, परिवहन, जल संसाधन और बिजली आदि जन सेवाओं से जुड़ी 33 योजनाओं पर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इसमें से 716 करोड़ रुपये की राशि पार्ट-एक के अंतर्गत 33 लंबे समय से अटकी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए मंजूर की गई है। इसके अलावा 105.26 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि (पार्ट-तीन के अंतर्गत) एमआरटीएस फेज-4 के प्रियारिटी कारिडोर से संबंधित परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई है। आगे कहा कि दिल्ली सरकार ने भेजे गए प्रस्तावों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल के माध्यम से समयबद्ध एवं विधिपूर्वक प्रस्तुत किया और वित्त मंत्रालय के साथ सक्रिय समन्वय के चलते यह मंजूरी बिना किसी विलंब के प्राप्त हुई। सरकार ने केंद्र के इस कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। फाइल

अवैध रूप से शराब परोसने वाले बार व पब पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : अवैध रूप से संचालित और बिना उचित लाइसेंस के शराब परोसने वाले बार, पब, क्लब और रेस्टोरेंट के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को जवाब मांगा है। एक याचिका पर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर ऐसे आउटलेट्स का विवरण पेश करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि रिपोर्ट में बताएं कि ऐसे पब, बार, क्लब और रेस्टोरेंट के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई। अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।

याचिकाकर्ता महताब खान ने याचिका में दावा किया कि कई रेस्टोरेंट, क्लब, पब और बार बिना एल-16 लाइसेंस के अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने दलील दी कि एक आवेदन के माध्यम से इस अवैधता का मामला उठाया गया था लेकिन आबकारी अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।

कुत्तों के टीकाकरण के लिए एमसीडी का पांच अगस्त से विशेष अभियान

जासं, नई दिल्ली

एमसीडी पांच अगस्त से आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण का महाभियान शुरू करने जा रहा है। इसके पूर्व 12 निर्वाचन क्षेत्रों में माहभर पायलट परियोजना चलेगी जिसमें कोशिश होगी कि करीब 70 से 80 प्रतिशत तक आवारा कुत्तों की नसबंदी कर दी जाए। शहर में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए एमसीडी की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा के निर्देशों के तहत गठित समिति की बुधवार को हुई पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया।

समिति के प्रमुख सुंदर सिंह तंवर ने बताया कि विभाग को आरडब्ल्यूए, कुत्ता प्रेमियों, गैर सरकारी संगठनों समेत मामले से जुड़े लोगों से परामर्श कर कार्य योजना तैयार करने को एक माह का वक्त दिया गया है। इसे लेकर सोमवार को अगली बैठक भी होगी जिसमें एनजीओ के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है जबकि पशु चिकित्सा विभाग के उप निदेशकों को 12 निर्वाचन क्षेत्रों के नाम प्रस्तुत करने को कहा गया है।

समिति के सदस्य और श्रीनिवासपुरी से पार्षद राजपाल सिंह ने बताया कि 20 नसबंदी केंद्रों में से प्रत्येक में एक कुत्ता आश्रय स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि जहां गुस्सैल और आदतन काटने वाले कुत्तों को रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि मौजूदा पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023, कुत्तों को 10 दिनों से अधिक समय तक रखने की अनुमति नहीं देता है इसलिए हम मानदंडों में संशोधन के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे। इस बीच, गैर सरकारी संगठनों को पालतू कुत्तों को रखने के लिए जगह देने की अनुमति दी जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा समय में एमसीडी में 20 नसबंदी केंद्र हैं और उनका संचालन 13 गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है।

▸ आवारा कुत्तों की समस्या से निजात दिलाने को लेकर गठित उप समिति का निर्णय

▸ चार अगस्त को पशु प्रेमियों व एमसीडी से जुड़े एनजीओ की होगी समीक्षात्मक बैठक

थम नहीं रहा आवारा कुत्तों का आतंक। जागरण

मृत बच्चे के कानूनी प्रतिनिधियों को नहीं है जान के सौदे का अधिकार

विनीत त्रिपाठी ● जागरण

नई दिल्ली : लापरवाही से कार चलाने के कारण सड़क हादसे में पांच साल के बच्चे की मौत के बाद उसके स्वजन द्वारा आरोपितों के साथ चंद रुपयों के लिए समझौता कर लेना दिल्ली हाई कोर्ट को नागवार गुजरा है। दोनों पक्षों के बीच एक लाख रुपये के मुआवजे के आधार पर प्राथमिकी रद करने को लेकर हुए समझौते को अस्वीकार करते हुए अदालत ने तीखी टिप्पणी की। याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने कहा कि इस तरह के समझौते को मंजूरी देने के बाद प्राथमिकी को रद करना ब्लड मनी (खून के बदले पैसे) के समान होगा और यह भारत की कानूनी व्यवस्था द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।

आरोपित को राहत देने से इन्कार करते हुए पीठ ने कहा कि कोई भी सभ्य समाज ब्लड मनी को स्वीकार नहीं करेगा। पीठ ने कहा कि इन तथ्यों को देखते हुए समझौते के आधार पर प्राथमिकी को रद करना उचित नहीं लगता। ऐसे में याचिका खारिज की जाती है।

▸ हाई कोर्ट ने पांच साल के बच्चे की मौत मामले में समझौते के आधार पर प्राथमिकी रद करने से किया इन्कार

दिल्ली हाई कोर्ट। फाइल

अदालत ने रिकार्ड पर लिया कि समझौते के तहत आरोपित ने मृत बच्चे के कानूनी प्रतिनिधियों को एक लाख रुपये देने की पेशकश की थी। अदालत ने कहा कि जांच फाइल से ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्घटना के बाद याचिकाकर्ता को मौके पर ही कार के साथ पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार याचिकाकर्ता ने अपनी अर्टिगा कार को तेजी और लापरवाही से चलाते हुए ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। इसके कारण ई-रिक्शा पलट गया और पांच साल का बच्चा मारा गया।

बीटेक की छात्रा ने फंदा लगाकर दी जान, केसीसी प्रबंधन पर प्रताड़ना का आरोप

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

शारदा विश्वविद्यालय की बीडीएस की छात्रा ज्योति शर्मा प्रकरण की भांति ही केसीसी प्रबंधन की प्रताड़ना से बीटेक की छात्रा ने अपने फ्लैट में मंगलवार रात फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सेमेस्टर परीक्षा के लिए केसीसी को केंद्र बनाया गया था। परीक्षा के दिन पहले छात्रा को गलत विषय का प्रश्नपत्र थमा दिया, विरोध करने पर नकल करने का आरोप लगा यूएफएम (अनुचित साधन एवं कदाचार) की कार्रवाई कर दी गई। विद्यार्थियों के सामने सार्वजनिक रूप से अपमानित करने से छात्रा मानसिक तनाव में थी। स्वजन ने केसीसी प्रबंधन, अज्ञात प्रोफेसर व कर्मचारियों के खिलाफ बीटा दो कोतवाली में मामला दर्ज कराया है।

मूलरूप से बिहार के वैशाली जिला के रहीमपुर गांव निवासी राजवल्लभ पंडित परिवार के साथ बीटा दो कोतवाली क्षेत्र में सेक्टर सिग्मा-4 स्थित ग्रांड फोर्ट सोसायटी में परिवार के साथ रहते हैं। उनकी 18 वर्षीय बेटी खुशबू नालेज पार्क स्थित जीएनआइओटी कालेज में बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रा थी। एकेटीयू ने सेमेस्टर परीक्षा के लिए केसीसी कालेज को परीक्षा केंद्र बनाया था। नौ जुलाई को खुशबू की रसायनशास्त्र विषय की परीक्षा थी जबकि केसीसी के परीक्षकों ने उसे भौतिक विज्ञान विषय का पेपर थमा दिया। परीक्षकों ने अपनी गलती मानने के बजाय खुशबू को अन्य छात्रों के सामने अपमानित किया। प्रताड़ित खुशबू वाशरूम चली गई। परीक्षक वाशरूम में पहले से पड़ीं कुछ पर्चियां उठा लाए जो उसके विषय से संबंधित नहीं थीं। घटना के बाद से खुशबू मानसिक परेशान थी। मंगलवार रात करीब 10 बजे खुशबू ने पंखे पर दुपट्टे से फंदा लगाकर जान दे दी। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने कहा कि जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वहीं फर्स्ट ईयर के एचओडी योगेश गुप्ता ने कहा कि हम एकेटीयू द्वारा चयनित परीक्षा सेंटर हैं। हमारे यहां दूसरे संस्थानों से परीक्षा देने आते हैं। एकेटीयू के निर्देशानुसार ही हम परीक्षा कराते हैं। कहीं पर बच्चे से पर्ची मिलती है तो प्रोफार्मा भरवाया जाता है। खुशबू के पास पर्ची मिली थी। इसी के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की थी। कार्रवाई की पूरी सूचना एकेटीयू को भेजी गई थी।

▸ परीक्षा में दूसरे विषय का प्रश्नपत्र दिया, नकल का आरोप लगा उत्तर पुस्तिका छीन किया अपमानित

खुशबू का फाइल फोटो।

जोमैटो से पता निकालकर दबोजे डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

मुंबई साइबर क्राइम का सब इंस्पेक्टर बनकर दिल्ली की एक गृहिणी को डिजिटल अरेस्ट कर उनसे 38 लाख रुपये ठगने के मामले में क्राइम ब्रांच ने दो मुख्य मास्टर माइंड को पानीपत से गिरफ्तार किया है। महिला के आधार कार्ड का उपयोग आपराधिक गतिविधियों में किए जाने की झूठी बात बताकर आरोपितों ने उन्हें और उनके आयकर विभाग में सीनियर पद पर तैनात पति को गिरफ्तार करने की धमकी दी थी। करीब तीन माह तक महिला को डरा कर रखा गया। इस दौरान आरोपित उनसे अलग-अलग बहाने से रुपये ऐंठते रहे। उन्हें डराने के लिए उनके वाट्सएप पर फर्जी एफआइआर और जाली गिरफ्तारी वारंट भेजे गए। शिकायत मिलने पर पहले आरोपितों के खातों को खंगाला जिससे उन्हें एक ईमेल मिला। ईमेल को ट्रैक कर आइपी पते का पता लगाया गया जिससे कुछ मोबाइल नंबर मिलने पर पुलिस ने जोमैटो से शुभम शर्मा नाम के आरोपित के घर का पता लगा उसे दबोच लिया। इससे पूछताछ के बाद दूसरे आरोपित मोहित को भी पकड़ लिया गया।

डीसीपी आदित्य गौतम के मुताबिक, शिकायतकर्ता महिला गृहिणी हैं। उन्हें एक ठग ने साइबर क्राइम, मुंबई से सब-इंस्पेक्टर प्रशांत शर्मा बनकर काल की और लगभग तीन महीनों के दौरान उन्हें बार-बार डिजिटल अरेस्ट कर कई बहानों से पैसे ऐंठते रहे। हर बार भुगतान करने पर उन्हें सभी डिजिटल साक्ष्य मिटाने का भी निर्देश दिया गया।

▸ मुंबई साइबर क्राइम का सब इंस्पेक्टर बनकर गृहिणी महिला को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे थे 38 लाख

प्रतीकात्मक

पहल

सभी 11 जिलों ने विकल्प के लिए भेजे दो स्थान के नाम, एक का होगा चयन, गोशालाओं में बेसहारा पशुओं के लिए होंगी आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं

बेसहारा गोवंशियों के लिए हर जिले में बनाए जाएगी गोशाला

लोकेश शर्मा ● जागरण

नई दिल्ली : राजधानी में बेसहारा गोवंशियों की समस्या बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले दिनों में योजना बनाने की बात कही थी। इस पर अब सरकार आगे बढ़ गई है। दिल्ली के सभी 11 जिलों में एक-एक गोशालाएं खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। पशुपालन विभाग ने सभी जिलों से उन स्थानों की जानकारी मांगी है जहां बेसहारा गोवंशियों को आश्रय देने के लिए गोशाला निर्माण किया जा सकता है।

सूत्रों के मुताबिक पशुपालन विभाग ने पत्र जारी कर सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टर, जिला इंचार्ज और पशु चिकित्सा अधिकारियों को राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर उन सरकारी जमीनों का निरीक्षण करने को कहा गया है जहां गोशाला बनाई जा सकती है। इसके बाद राजस्व के सभी जिलों की तरफ से पशुपालन विभाग को दो-दो जगह बताए गए हैं। इनमें से एक-एक जगह का चयन होना है। मध्य दिल्ली में सिविल लाइंस स्थित मुकुंदपुर में बताई गई जगह पर मुहर लग गई है। अन्य स्थानों के लिए प्रक्रिया अभी जारी है।

गोशालाओं में मिलेंगी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं : गोशालाओं में गोवंशियों की देखभाल के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक गोशाला में एक बड़ा कक्ष तैयार किया जाएगा, जहां चिकित्सा उपकरण रहेंगे। यहां 24 घंटे पशु चिकित्सक की तैनाती होगी जो उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच करेंगे। घायलों का उपचार करेंगे। इसके अलावा चारे और स्वच्छ पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।

रखरखाव के लिए होंगे अनुभवी कर्मी : गोशालाओं के सुचारू संचालन के लिए अनुभवी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। ये कर्मी गोवंशियों के रखरखाव, सफाई और गोबर प्रबंधन का कार्य करेंगे। प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें पशुपालन का अनुभव हो और जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हों। अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली सरकार गोवंशियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उन्हें किसी भी तरह की क्षति से बचाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं।

बाहरी रिंग रोड पर दीपाली चौक के पास बेसहारा पशु। जागरण आर्काइव

आयोग बनाने की मांग

बेसहारा गोवंशियों को आश्रय देने के लिए आयोग बनाने की मांग की गई है। अखंड भारत मोर्चा के अध्यक्ष संदीप आहूजा ने दिल्ली सरकार की पहल का स्वागत किया है। इसके साथ उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से दिल्ली गोसेवा आयोग बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि किसी तरह का सर्वे नहीं होने के कारण बेसहारा पशुओं का कोई प्रमाणिक आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है लेकिन अनुमान है कि इनकी संख्या तीन से चार लाख हो सकती है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में गोवंशियों की देखभाल के लिए सरकार पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत विभिन्न संस्थाओं को जिम्मेदारी दे सकती है।

लेडी हार्डिंग अस्पताल ने क्षेत्र विवाद में उपचार करने से किया इन्कार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

पुलिस थानों का सीमा विवाद तो आए दिन सुनाई देता है लेकिन देश की राजधानी में सरकारी अस्पताल भी भौगोलिक सीमाओं में बंधकर काम कर रहे हैं। वह खुद ही यह तय कर रहे हैं कि किसी क्षेत्र के घायल को वह उपचार देंगे और किसको नहीं। ऐसा ही एक मामला लेडी हार्डिंग अस्पताल से सामने आया है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन की आरपीएफ पोस्ट के जवानों को अक्षरधाम गेम्स विलेज के पास रेलवे लाइन के किनारे घायल व्यक्ति मिला जिसे लेकर वह लेडी हार्डिंग अस्पताल पहुंचे। वहां अस्पताल के डाक्टरों ने यह कहकर उपचार करने से इन्कार कर दिया कि जिस स्थान पर दुर्घटना हुई है, वह जीटीबी या डा. हेडगेवार अस्पताल के दायरे में आता है। मजबूरन आरपीएफ और दिल्ली पुलिस उसे लेकर डा. हेडगेवार अस्पताल पहुंचे तब जाकर उसे भर्ती कराया जा सका। इस पर आरपीएफ ने प्रश्न पूछा है कि क्या अस्पताल की भी क्षेत्रीय सीमा होती है। इसका जवाब अस्पताल प्रशासन से मांगा गया तो वह चुप्पी साध गए।

▸ आरपीएफ ने पूछा कि क्या अस्पताल की भी होती है क्षेत्रीय सीमा, इस आधार पर कैसे हो सकेगा उपचार

लेडी हार्डिंग अस्पताल। फाइल

****

2024 एकड़ रक्षा भूमि पर अतिक्रमण, केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में 75,629 एकड़ रक्षा भूमि में से 1,575 एकड़ भूमि उन लोगों के अनधिकृत कब्जे में है जिन्होंने कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि पट्टे पर ली थी।

कान खोलकर सुन लें, 22 अप्रैल से 16 जून तक नहीं हुई मोदी-ट्रंप में बात : जयशंकर

अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों पर भरोसा कर सवाल उठा रहे विपक्ष को विदेश मंत्री का दो टूक जवाब

अमेरिका-पाकिस्तान रिश्तों पर कहा, भारत और अमेरिका का दृष्टिकोण अलग-अलग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से किसी बाहरी हस्तक्षेप पर आपरेशन सिंदूर रोकने के आरोपों को खारिज किए जाने के बावजूद पुराने सवाल ही दोहरा रहे विपक्ष से बुधवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने फिर से कहा, 'कान खोलकर सुन लें, 22 अप्रैल से 16 जून तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई फोन वार्ता नहीं हुई।' अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर भी विदेश मंत्री ने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान को लेकर भारत और अमेरिका का अलग-अलग दृष्टिकोण है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मंगलवार को लोकसभा में दिए गए वक्तव्य के बाद विदेश मंत्री ने बुधवार को राज्यसभा में भी स्पष्ट शब्दों में दावा किया कि नौ मई को अमेरिका के उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस का फोन आया था, लेकिन अन्य देशों की तरह ही अमेरिका से भी कह दिया गया था कि भारत आत्मरक्षा के अधिकार के तहत सिर्फ पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर ही कार्रवाई कर रहा है। भारत का सभी को संदेश था कि इस मामले में किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी।

इसके बाद भारतीय सैन्य बलों ने पाकिस्तानी एयरबेस पर हमले किए भी। जयशंकर ने ट्रंप के 'ट्रेड प्रेशर' के दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि संघर्ष विराम की वार्ता में ट्रेड का कोई लेना-देना नहीं था। सिंधु जल समझौते, अनुच्छेद-370 आदि की चर्चा करते हुए विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलतियों को प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक किया है।

संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को राज्यसभा में बोलते विदेश मंत्री एस जयशंकर। एएनआइ

चीन के राजदूत से प्राइवेट ट्यूशन ले रहे विपक्षी नेता हिस्ट्री की क्लास में सो रहे थे क्या?

विदेश मंत्री जयशंकर ने विपक्ष को चीन की चुनौती और पाकिस्तान से उसके संबंधों के सवाल पर भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने तंज कसा, विपक्ष में कुछ 'चाइना गुरु' आजकल कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन एक-दूसरे के करीब आ गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यह जानती है, लेकिन सच यह है कि यह सब अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इसका भी इतिहास है। उन्होंने 2006 में भारत और चीन के बीच रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, हम्बनटोटा बंदरगाह का निर्माण, पाकिस्तान-चीन के बीच 1967 में शुरू हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास सहित कई उदाहरण दिए। साथ ही कटाक्ष किया, विपक्ष के जो नेता चीन के राजदूत से प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हैं, वह हिस्ट्री की क्लास में क्या सो रहे थे? जयशंकर ने अपनी चीन यात्रा के दौरान हुई बातचीत को लेकर उठाए गए सवालों पर कहा कि हमने आतंकवाद पर बात की, परस्पर हित और सम्मान की बात की। साथ में कटाक्ष किया, 'हमारी मीटिंग और वार्ता सार्वजनिक थी, हम चीन से सीक्रेट मीटिंग नहीं करते।'

तुष्टीकरण की मिठाई खिलाती रही कांग्रेस सरकार, पाकिस्तान बरसाता रहा बम : नड्डा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- आपरेशन सिंदूर पर चर्चा करते हुए समझाया संवेदनशील और असंवेदनशील सरकार का फर्क
- आतंकी को छुड़वाने के प्रयास की घटना याद दिलाकर समाजवादी पार्टी को भी लिया आड़े हाथ
- मोदी सरकार में 2014 के बाद आतंकी घटनाएं 7,217 से घटकर 2,150 रह गईं

आपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष इतिहास के सहारे विपक्ष को आईना दिखाने के आपरेशन में गंभीरता से जुटा दिखाई दिया। राज्यसभा में सदन के नेता व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 2004 से 2014 तक संप्रग काल को अमावस और 2014 के बाद से मोदी के कार्यकाल को पूर्णमासी की संज्ञा देते हुए तब हुई आतंकी घटनाओं, तत्कालीन सरकार के रुख और वर्तमान सरकार के रुख की चर्चा की। उन्होंने आरोप लगाया कि संप्रग सरकार तुष्टीकरण की मिठाई खिलाती रही और पाकिस्तान भारत पर बम बरसाता रहा।

नड्डा ने कहा कि संवेदनशील और असंवेदनशील सरकार के अंतर को समझने के लिए सिर्फ पहलगाम की घटना को देखना अन्याय है। इसे दो चरणों में देखना होगा। पहला 2004 से 2014 और दूसरा 2014 से 2025 तक की सरकार का कार्यकाल, क्योंकि अमावस दिखाने के बाद ही पूर्णमासी समझ में आती है। उन्होंने 2005 में श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम विस्फोट, दिल्ली में बम विस्फोट, 2006 में वाराणसी में बम धमाके, मुंबई में बम धमाके आदि की याद दिलाते हुए आरोप लगाया कि इन घटनाओं के बाद तत्कालीन संप्रग सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। मुंबई की घटना के बाद ज्वाइंट एंटी टेरोरिज्म मैकेनिज्म जरूर बना, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान के साथ कारोबार चलता रहा, बातचीत चलती रही और आतंकी हमले भी होते रहे। 2007 में गोरखपुर, लखनऊ और अयोध्या में आतंकी हमले हुए। उसी के बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने गुड्स कैरियर के लिए अटारी और वाघा बार्डर खोल दिया।

आइएनडीआइए की सहयोगी समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना नड्डा ने याद दिलाया कि रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले में शहाबुद्दीन नाम के आतंकी का हाथ था। उसे छुड़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार ने आदेश दिया था, तब हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप कर ऐसा करने से रोका था।

नेता सदन ने कुछ आंकड़े भी सदन में रखे। 2004-2014 और 2014-2025 तक के कार्यकाल की तुलना करते हुए दावा किया आतंकी घटनाएं 7,217 से घटकर 2,150 रह गईं।

नागरिकों की मृत्यु का आंकड़ा 1,770 से घटकर 357 पर आ गया। सुरक्षा बलों के जवानों के बलिदान होने की संख्या 1,060 से कम होकर 542 पर आ गई, वहीं आतंकियों के मारे जाने का आंकड़ा 23 प्रतिशत बढ़ गया।

राज्यसभा में बुधवार को आपरेशन सिंदूर के संबंध में जारी बहस के दौरान बोलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। एएनआइ

राहुल गांधी ने 1971 के युद्ध के तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया : निशिकांत दुबे

- इंदिरा गांधी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को लिखे गए एक पत्र का दिया हवाला
- कहा, इंदिरा ने पाकिस्तान के साथ युद्ध को रोकने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की विनती की थी

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में इंदिरा गांधी की भूमिका को लेकर राहुल गांधी द्वारा पेश किए गए तथ्यों को गलत बताया। कहा कि राहुल गांधी ने इस संबंध में जो तथ्य पेश किए, वे गलत हैं। उन्होंने तथ्यों को तोड़-मरोड़कर कर पेश किया। दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से विपक्ष के नेता के बयान को गंभीरता से लेने का आग्रह किया। सूत्रों ने बताया कि बिरला को लिखे पत्र में राहुल गांधी के बयानों के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही भाजपा सांसद ने सदन में इस मुद्दे को उठाने के लिए अध्यक्ष से अनुमति भी मांगी है।

राहुल गांधी ने मंगलवार को आपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कहा था कि यदि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी में इंदिरा गांधी जैसा 50 प्रतिशत भी साहस होता तो वह स्पष्ट रूप से कहते कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में मध्यस्थता की थी। उन्होंने कहा था कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने सशस्त्र बलों को पूरी छूट दी थी, जबकि मोदी सरकार ने उनके हाथ बांध दिए हैं। दुबे ने पांच दिसंबर 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को लिखे गए एक पत्र का हवाला दिया। इसमें उनसे पाकिस्तान के साथ युद्ध को रोकने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की विनती की गई थी। भाजपा सांसद ने अध्यक्ष को सौंपे ज्ञापन में इस पत्र को संलग्न किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़कर जनता के विश्वास को तोड़ा है।

निशिकांत दुबे। एएनआइ

इंदिरा ने पाक से युद्ध समाप्त करने के लिए की थी अमेरिकी हस्तक्षेप की मांग : अनुराग ठाकुर

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में दावा किया कि इंदिरा गांधी ने 1971 में प्रधानमंत्री रहते हुए पाकिस्तान के साथ युद्ध रोकने के लिए अमेरिका से हस्तक्षेप की मांग की थी। 1971 का युद्ध भारतीय सैनिकों ने जीता था, लेकिन किसी और को लौह महिला घोषित कर दिया गया। दावा किया कि युद्ध रणभूमि में जीता गया था, लेकिन बातचीत की मेज पर हारा गया। उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को पत्र लिखा था।

कपिल सिब्बल ने कहा, पाक से युद्ध के लिए नहीं है पर्याप्त संसाधन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कहा, जब हम पाकिस्तान से युद्ध की बात करें तो उसमें चीन को भी जोड़ें
- चीन का है पाक को समर्थन, उसके पास उन्नत तकनीक व विमान दोनों हैं

राज्यसभा में आपरेशन सिंदूर व पहलगाम आतंकी हमले पर चल रही चर्चा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने देश की रक्षा तैयारियों पर सवाल खड़े किए। कहा कि भारत के पास पाकिस्तान से युद्ध लड़ने और उसे बर्बाद करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। जब हम पाकिस्तान से युद्ध की बात करें तो उसमें चीन को भी जोड़ें, क्योंकि दोनों अलग नहीं हैं। चीन का उसे खुला समर्थन है। चीन के पास उन्नत तकनीक और विमान दोनों हैं।

राज्यसभा में बुधवार को आपरेशन सिंदूर पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सिब्बल ने कहा कि पाकिस्तान और उसके समर्थक चीन के पास उन्नत विमान हैं, जबकि भारत का राफेल आधी क्षमता वाला विमान है। आंकड़े गिनाते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन हैं जबकि चीन के पास 138 स्क्वाड्रन है। वहीं भारतीय वायुसेना के वैसे तो कुल 32 स्क्वाड्रन है, जो किसी भी भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान सबसे कम संख्या है। इनमें भी मिग-21, मिग-29 और मिराज-2000 को बेड़े से चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। ऐसे में देखें तो भारत के पास लगभग पाकिस्तान के बराबर ही स्क्वाड्रन हैं।

उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना प्रमुख भी इस चिंता को स्वीकार कर चुके हैं। ऐसे में हमारे पास सिर्फ सुखोई-30 है। राफेल की बात करें तो वह 4.5 पीढ़ी का विमान है, जबकि चीन इस साल के अंत तक छठी पीढ़ी का विमान लांच करने की तैयारी में है। वहीं भारत अभी पांचवीं पीढ़ी का मध्यम लड़ाकू विमान बनाने की तैयारी कर रहा है। यह 2028-29 तक तैयार हो सकेगा। सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री पर सवाल खड़े करते हुए आठ अप्रैल को जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा पर बुलाई गई बैठक में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को नहीं बुलाए जाने की आलोचना की।

संसद प्रश्नोत्तर

आठवीं अनुसूची में भाषाओं के समावेश पर विचार की कोई समयसीमा नहीं

- सरकार ने कहा-भोजपुरी और राजस्थानी सहित कई भाषाएं शामिल करने की मांगें उठी हैं
- मंत्री नित्यानंद राय बोले-सरकार अन्य भाषाओं को शामिल करने की मांग पर संवेदनशील

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया कि संविधान की आठवीं अनुसूची में अधिक भाषाओं के समावेश की मांगों पर विचार के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि वर्तमान में कोई तय मानदंड नहीं हैं।

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को एक लिखित उत्तर में कहा कि सरकार अन्य भाषाओं के समावेश की मांगों के प्रति संवेदनशील है। ऐसी मांगों पर विचार करते समय इन संवेदनाओं और अन्य प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखना आवश्यक है। चूंकि वर्तमान में संविधान की आठवीं अनुसूची में किसी भी भाषा के समावेश के लिए कोई निश्चित मानदंड नहीं हैं, इसलिए अधिक भाषाओं के समावेश की मांगों पर विचार के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। मंत्री ने कहा कि समय-समय पर भोजपुरी और राजस्थानी सहित कई भाषाओं के समावेश की मांगें उठाई गई हैं। चूंकि बोलियों और भाषाओं का विकास एक गतिशील प्रक्रिया है, जो सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकासों से प्रभावित होती है।

नित्यानंद राय। फाइल

2018 से 2022 के बीच यूएपीए के केवल दो मामले खारिज: 2018 से 2022 के बीच देशभर में कड़े आतंकवाद विरोधी कानून, अवैध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, के तहत केवल दो मामले अदालतों द्वारा खारिज किए गए। गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा कि इस अवधि में यूएपीए के तहत 6,503 व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, जबकि 252 लोगों को अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया।

मनी लांड्रिंग के 49 मामलों में ईडी की क्लोजर रिपोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने राज्यसभा को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साढ़े दस सालों में मनी लांड्रिंग से जुड़े अपराधों के लिए विशेष अदालतों के समक्ष 49 मामले बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में लिखित बयान में कहा कि जांच एजेंसी ईडी ने 2015 से जून 2025 के बीच पीएमएलए अदालतों से 15 लोगों के खिलाफ आठ सजा आदेश प्राप्त किए हैं। सदन में उनसे ईडी के 2015 से दर्ज उन सभी मामलों का ब्योरा पूछा गया था, जिनमें अभी तक अदालतों में आरोपपत्र भी दाखिल नहीं किया गया है और ना ही आरोपितों का ट्रायल शुरू हुआ है।

पंकज चौधरी। फाइल

अधिग्रहण संबंधी समस्या के कारण 489 परियोजनाएं लंबित

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि लगभग 489 सड़क परियोजनाएं, जिन्हें मूल रूप से मार्च 2025 तक पूरा होना था, भूमि अधिग्रहण, वन/वन्यजीव मंजूरी और रेलवे मंजूरी में देरी के कारण लंबित हैं। सरकार इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ प्रयास कर रही है। कुछ विलंबित परियोजनाओं में लागत में वृद्धि हुई है जैसे भूमि और संरचनाओं के लिए मुआवजे की बढ़ी हुई लागत, मूल्य वृद्धि, जीएसटी का प्रभाव, रेलवे मानकों को पूरा करने के लिए जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग (जीएडी)/डिजाइन में बदलाव आदि।

नितिन गडकरी।

लोस ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने को दी मंजूरी

- सरकार ने दावा किया कि पूर्वोत्तर राज्य में बनी हुई है शांति
- राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से सिर्फ एक व्यक्ति की गई है जान

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकसभा ने बुधवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 अगस्त से आगे छह महीने के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार ने दावा किया कि पूर्वोत्तर राज्य में शांति बनी हुई है।

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के वैधानिक प्रस्ताव पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि फरवरी में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से राज्य में केवल एक व्यक्ति की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि वहां शांति लौटने का इससे बड़ा सुबूत और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि शांति स्थापित करने के लिए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होना जरूरी है। वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। स्थायी शांति स्थापित करने के लिए बातचीत के जरिए दोनों जातीय समुदायों के बीच मतभेदों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस सदस्य एंटो एंटनी की इस टिप्पणी को खारिज कर दिया कि मणिपुर में संघर्ष दो धर्मों के बीच है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा जातीय थी।

चर्चा में भाग लेने वाले कांग्रेस सदस्य ए. बिमोल अकोईजाम ने राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाए जाने का विरोध किया और मणिपुर में चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भाजपा मणिपुर में सरकार बनाने में असमर्थ रही है। उन्होंने मणिपुर की वर्तमान स्थिति के लिए जवाबदेही तय करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की भी मांग की।

कांग्रेस की प्राथमिकता सुरक्षा नहीं, राजनीति है : शाह

प्रथम पृष्ठ से आगे

अमित शाह ने कांग्रेस नेताओं पर हर चीज को हिंदू-मुस्लिम के नजरिये से देखने का आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता सुरक्षा नहीं, बल्कि राजनीति है। इसी तुष्टीकरण की मानसिकता के कारण आतंकियों को बचाने के लिए कांग्रेस ने एक तरफ पोटा को खत्म किया, तो दूसरी ओर हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ने के लिए कई देशभक्त धार्मिक संस्थाओं के विरुद्ध झूठे केस बनाए। लेकिन इनमें से एक भी केस नहीं टिका।

छह माह में कश्मीर का एक भी युवा आतंकी नहीं बना : अनुच्छेद-370 निरस्त करने के बाद भी आतंकवाद खत्म नहीं होने के विपक्षी सांसदों के आरोपों का जवाब देते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस ने आतंकवाद की जड़ें इतनी गहरी डाली हैं कि समाप्ति में समय लगेगा। लेकिन आंकड़े गवाह हैं कि यह समाप्ति की कगार पर है और हम इसे पूरी तरह से खत्म करके रहेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने कहा, ''जम्मू-कश्मीर में 2010 में 2,564 पत्थरबाजी की घटनाएं हुईं। 2024 के बाद एक भी घटना नहीं हुई है। पाकिस्तान में बैठे हुर्रियत नेताओं द्वारा घोषित हड़तालें, पिछले तीन वर्षों में एक बार भी नहीं हुईं। अब उनमें बंद का आह्वान करने का साहस नहीं है। हमने कश्मीर में भारतीय संविधान का झंडा फहराया है। उनके अनुसार कश्मीर से आतंकवाद का इकोसिस्टम ध्वस्त कर दिया गया है।

जितना चाहे कर लो... जम्मू-कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होगा : पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि धर्म के आधार पर लोगों की हत्या की गई। आतंकियों ने पर्यटकों की हत्या करके यह संदेश दिया कि वे कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त नहीं होने देंगे। गृह मंत्री ने कहा, ''मैं इस सदन के माध्यम से आतंकियों से कहना चाहता हूं, जितना चाहे कर लो... जम्मू-कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होगा। यह मोदी जी का संकल्प है।''

पीड़ितों की इच्छानुसार आतंकियों के सिर में मारी गोली : गृह मंत्री ने कहा कि पहलगाम हमले के पीड़ितों के परिवार और कई अन्य लोग चाहते थे कि तीनों आतंकियों को सिर में गोली मार दी जाए। आपरेशन महादेव में उनका यही हश्र हुआ। उन्होंने कहा, ''कल आप (कांग्रेस) पूछ रहे थे कि वे (पहलगाम के आतंकी) आज के दिन क्यों मारे गए? उन्हें कल क्यों नहीं मारा जाना चाहिए था? क्योंकि राहुल गांधी को अपना भाषण देना था? यह काम इस तरह से नहीं होता। पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस की प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद को खत्म करना नहीं है, बल्कि राजनीति, उनका वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति है।'' पी. चिदंबरम के बयान को कांग्रेस की मानसिकता बताते हुए शाह ने कहा यदि कांग्रेस सत्ता में होती तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देती।

आधे घंटे में बर्बाद कर सकते हैं पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणाली : शाह ने कहा कि कांग्रेस ने सेना की तैयारी के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। चीन से युद्ध के दौरान हमारे पास ठंड में पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं थे... न नमक था, न माचिस और हमारे पास बंदूकों व कारतूसों की भारी कमी थी। मोदी जी के नेतृत्व में सेना ब्रह्मोस मिसाइल जैसे आधुनिक हथियारों से लैस है। 'आकाश तीर' मिसाइल दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देती है और हमारी सेना पाक की वायु रक्षा प्रणाली को सिर्फ आधे घंटे में बर्बाद कर सकती है।

आपरेशन सिंदूर

सरकार ने डिजिटल मीडिया पर झूठे व भ्रामक कंटेंट रोकने की दी जानकारी, मीडिया चैनलों को लाइव कवरेज दिखाने से बचने की सलाह जारी की थी

1,400 से अधिक फर्जी यूआरएल ब्लाक करने के दिए गए निर्देश

नई दिल्ली, आइएएनएस : सरकार ने 'आपरेशन सिंदूर' के दौरान डिजिटल मीडिया पर 1,400 से अधिक यूआरएल को ब्लाक करने के निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि उनके कंटेंट में झूठी, भ्रामक, भारत विरोधी समाचार सामग्री, साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री (मुख्य रूप से पाक स्थित इंटरनेट मीडिया खातों से) व भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाफ भड़काऊ सामग्री शामिल थी।

केंद्रीय रेल और इलेक्ट्रानिक्स एवं आइटी मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि भारत के बाहर से संचालित हो रहे कुछ इंटरनेट मीडिया हैंडल समेत कई डिजिटल प्लेटफार्म पहलगाम आतंकवादी हमले और 'आपरेशन सिंदूर' के दौरान झूठी और संभावित रूप से हानिकारक जानकारी का सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा, ''सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69ए के तहत सरकार ने भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में वेबसाइटों, इंटरनेट मीडिया हैंडल और पोस्ट को ब्लाक करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए।'' 26 अप्रैल, 2025 को आइटी मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों का लाइव कवरेज दिखाने से बचने के लिए एक सलाह जारी की थी। 'आपरेशन सिंदूर' के दौरान एक केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया था ताकि अंतर-विभागीय और अंतर-क्षेत्रीय समन्वय किया जा सके। यह सभी मीडिया हितधारकों को वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करने में सहायक था। इस नियंत्रण कक्ष में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के नोडल प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न सरकारी मीडिया इकाइयों के अधिकारियों व प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआइबी) अधिकारियों को शामिल किया गया था। फर्जी समाचार और गलत जानकारी फैलाने वाले इंटरनेट हैंडल और पोस्ट को सक्रिय रूप से पहचाना गया।

43 ओटीटी प्लेटफार्मों को अब तक ब्लाक किया गया : सरकार ने अब तक स्पष्ट, वयस्क, हिंसक या सांस्कृतिक रूप से असंवेदनशील सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए 43 ओवर-द-टाप (ओटीटी) प्लेटफार्मों को ब्लाक किया है और कानूनी और नैतिक मानकों का पालन सुनिश्चित किया है। लोकसभा में केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स और आइटी मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने बताया कि डिजिटल समाचार प्रकाशकों और आनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (ओटीटी प्लेटफार्मों) के प्रकाशकों के लिए एक नैतिकता कोड प्रदान किया गया है।

अश्विनी वैष्णव। फाइल

ब्यूरोक्रेट को सेवानिवृत्ति के बाद विशेष परिस्थितियों में विस्तार : सरकार

सरकार ने कहा कि आइएएस, आइपीएस व अन्य अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सेवा विस्तार विशेष परिस्थितियों में और जनहित में दिया जाता है। यह बयान उस प्रश्न के उत्तर में आया जिसमें पिछले पांच वर्षों में सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) और भारतीय राजस्व सेवा (आइआरएस) के अधिकारियों को दिए गए विस्तार की संख्या के विवरण की मांग की गई थी। केंद्रीय राज्य मंत्री (कार्मिक) जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा, ''सेवानिवृत्ति के बाद सेवा का विस्तार विशेष परिस्थितियों में जनहित में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को दिया जाता है, जो कि अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958/प्रासंगिक नियमों के प्रविधानों के अनुसार है।'' हालांकि, उत्तर में पांच वर्षों में दिए विस्तार की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया।

****

कह कर रहेंगे

माधव जोशी

100 – 100 गज के रिहायशी प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे हरियाणा में। सीएम नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा की है। उन्हें प्लाट के कागज भी सौंपे जाएंगे। राज्य सरकार जल्द पुलिस की भर्ती निकालेगी।

डिंपल के अपमान पर असमंजस में सपा, मुस्लिम वोट बैंक साधे या महिला सम्मान

विषम परिस्थिति ▶ भाजपा के लगातार हमलों से पार्टी के लिए बढ़ रही चुनौती

समाजवादी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा वरिष्ठ नेता मौन की रणनीति पर चल रहे

दिलीप शर्मा • जागरण

डिंपल यादव। फाइल

लखनऊ : मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी ने पार्टी के सामने विषम परिस्थियां पैदा कर दी हैं। एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक को नाराज न होने देने की चुनौती है तो दूसरी तरफ महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर पार्टी की आक्रामक रणनीति के कमजोर पड़ने का डर। मुश्किल इसलिए भी अधिक है, क्योंकि टिप्पणी किसी सामान्य नेता या कार्यकर्ता पर नहीं, बल्कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी पर हुई है और दूसरी तरफ भाजपा लगातार इस मुद्दे को गर्मा रही है। सपा मुखिया की चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सपा ने रणनीति के तहत नेताओं-कार्यकर्ताओं को विरोध जताने की छूट दे दी गई है, परंतु बड़े नेताओं का मौन जारी रहेगा। दूसरी तरफ भाजपा की कोशिश विवाद को लंबे समय तक खींचकर सपा को बैकफुट पर बनाए रखने की है।

सपा मुखिया पिछले दिनों डिंपल और अन्य पार्टी सांसदों के साथ दिल्ली में संसद भवन के पास स्थित मस्जिद में गए थे। इस पर एक न्यूज चैनल पर बहस के दौरान आल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने मस्जिद के अंदर डिंपल के पहनावे को लेकर विवादास्पद टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद लखनऊ से दिल्ली तक राजनीति गर्माई हुई है। महिला के अपमान और उस पर सपा की चुप्पी को भाजपा ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। भाजपा की महिला सांसदों ने संसद भवन के बाहर इसे लेकर प्रदर्शन किया। लखनऊ में महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने सीधे अखिलेश पर हमला बोला। कहा कि सपा मुखिया की चुप्पी कहीं न कहीं उनकी वोट बैंक की लालसा को दर्शाती है। क्या उन्होंने सत्ता के लिए अपनी पत्नी का अपमान स्वीकार कर लिया है? सपा का मौन क्या इस सोच की सहमति है कि सपा में महिलाओं की गरिमा अब मौलवी तय करेंगे? भाजपा के अन्य नेता भी लगातार सपा को घेर रहे हैं। इससे सपा की बेचैनी बढ़ी है। माना जा रहा है कि सपा अपने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फार्मूले में शामिल मुस्लिम वोट बैंक को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। टिप्पणी मामले में बयानबाजी से उसे नुकसान की आशंका है। इसके चलते ही प्रकरण पर शुरुआत से ही पूरी तरह चुप्पी साधी गई, परंतु अब भाजपा की रणनीति से सपा को महिला सम्मान का मुद्दा हाथ से फिसलता दिख रहा है और पार्टी इस उलझन से निकलने का रास्ता तलाश रही है। इसके तहत ही मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही पार्टी ने अपने फ्रंटल संगठनों को विरोध के लिए आगे किया गया है, जिससे बड़े नेताओं की चुप्पी भी बनी रहे और विरोध का संदेश भी चला जाए।

मौलाना रशीदी ने जमीयत व मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड की चुप्पी पर उठाए सवाल

जासं, नई दिल्ली: आल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने सपा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मारपीट के मामले में जमीयत उलेमा-ए-हिंद व मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड जैसे संगठनों की चुप्पी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि देश के मुस्लिम समाज को भाजपा का डर दिखाने वाले अब सपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी पिटाई पर चुप क्यों हैं? यही चुप्पी पूर्व में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा द्वारा कैराना से सपा सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी पर भी थी। मौलाना साजिद रशीदी ने सपा कार्यकर्ताओं से जान का खतरा बताते हुए कहा है कि उन्हें लगातार फोन पर धमकियां मिल रही हैं। संसद परिसर में अखिलेश यादव द्वारा उन पर हुई हिंसा को गलत बताए जाने पर रशीदी ने कहा कि इतना कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि दोषियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना होगा।

देश को 109 आइएफएस अफसर मिले, केरल के मिधुनमोहन ने किया टाप

जागरण संवाददाता, देहरादून : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आइजीएनएफए) के वर्ष 2023-2025 बैच के दीक्षा समारोह के साथ ही देश को 109 आइएफएस अफसर मिल गए। वे अब अपने-अपने कैडर के राज्य में युवा वनाधिकारी के रूप में सेवा देंगे। पासआउट होने वालों में आइएफएस के अलावा दो प्रशिक्षु अधिकारी भूटान के भी हैं।

सर्वाधिक 17 अफसर मध्य प्रदेश को मिले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश को 12 अधिकारी मिले हैं। दीक्षा समारोह में सर्वांगीण उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार केरल कैडर के मिधुनमोहन एसबी को मिला।

वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ) में आइजीएनएफए के दीक्षा समारोह का उद्घाटन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन ने किया। उन्होंने युवा अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रशासनिक दायित्वों के साथ नैतिक एवं सांविधिक प्रतिबद्धताओं के अनुरूप कार्य करने की सीख दी।

जस्टिस रामसुब्रमण्यन ने युवा अधिकारियों को एक तरफ जीवन में किसी बदलाव को स्वीकार करने की सीख दी तो दूसरी तरफ नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए भी प्रेरित किया। अकादमी के निदेशक डा. जगमोहन श्रम ने कहा कि पासआउट होने वाले प्रशिक्षु अधिकारियों में 22 महिला आइएफएस अधिकारी भी शामिल हैं।

एक साथ चुनाव कराने से जीडीपी में 1.5% की हो सकती है वृद्धि

▶ वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष समेत विशेषज्ञों ने जेपीसी के समक्ष रखी राय

▶ कहा- इससे पूंजीगत व्यय व निवेश गतिविधियों में भी बढ़ोतरी की उम्मीद

एनके सिंह। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र: वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह और अन्य विशेषज्ञों ने बुधवार को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के समक्ष 'एक राष्ट्र एक चुनाव' के आर्थिक पहलुओं पर चर्चा की। इससे वास्तविक जीडीपी में 1.5 प्रतिशत (4.50 लाख करोड़) की वृद्धि संभव है। साथ ही पूंजीगत व्यय व निवेश गतिविधियों में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

विशेषज्ञों ने 2023-24 के आंकड़ों के संदर्भ में जीडीपी में 4.50 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया। हालांकि, चुनावों के बाद खर्च बढ़ने से राजकोषीय घाटा 1.3 प्रतिशत अंक बढ़ने की संभावना भी जताई गई। पूर्व राजस्व सचिव एनके सिंह और अशोका यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर प्राची मिश्रा ने बताया कि 1967 तक देश में एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन उसके बाद से लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग-अलग होने लगे थे।

विशेषज्ञों ने कहा कि बार-बार चुनावों के कारण अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती है और इससे आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट आती है। प्रवासी श्रमिकों को बार-बार अपने मूल स्थान पर लौटना पड़ता है और इससे उत्पादकता पर असर पड़ता है।

उन्होंने उल्लेख किया कि प्रवासी, भारत की आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा हैं तथा बार-बार चुनाव कराने से उन पर भी वित्तीय बोझ पड़ता है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी पर तैनात करने और स्कूलों को मतदान केंद्रों में परिवर्तित करने के कारण स्कूल नामांकन में भी 0.5 प्रतिशत की कमी आती है। उन्होंने तर्क दिया कि पुलिसकर्मियों को बार-बार चुनावी कार्यों में लगाए जाने के चलते चुनावों के दौरान आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती हैं। वर्ष 1986 के बाद से भारत में एक भी साल ऐसा नहीं रहा, जब चुनाव नहीं हुए हों और इस कारण देश लगातार चुनावी माहौल में रहा। उन्होंने कहा कि लगातार चुनाव अस्थायी कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देते हैं, जिससे लोकलुभावन वादों में वृद्धि होती है।

न्यूज गैलरी

मप्र विस में पहली बार संस्कृत में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

नईदुनिया, भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा में पहली बार संस्कृत में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ा गया। जबलपुर उत्तर से भाजपा विधायक अभिलाष पांडे ने संस्कृत में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ते हुए कहा कि उनका उद्देश्य संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन पर सरकार का ध्यान खींचना है। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने शुरुआती जवाब संस्कृत में दिया। कहा कि सरकार का प्रयास है कि ऐसा संस्थान बनाया जाए जहां संस्कृत, वैदिक, योग तीनों की शिक्षा एक साथ दी जा जा सके। अभी प्रदेश में 271 संस्कृत के विद्यालय संचालित हैं। (राब्यू)

राहुल पांच को 'वोट चोरी' के विरोध में करेंगे प्रदर्शन

बेंगलुरु : कांग्रेस नेता राहुल गांधी 'वोट चोरी' के विरोध में पांच अगस्त को बेंगलुरु में आयोजित होने वाले प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे और यहां निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपेंगे। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को दी। राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया था कि उनकी पार्टी ने कर्नाटक के एक लोकसभा क्षेत्र का अध्ययन करके यह पता लगाया है कि किस प्रकार 'वोट चोरी' की जाती है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जारी विवाद के बीच राहुल ने 23 जुलाई को आरोप लगाया था कि भारत में वोटों की चोरी हो रही है और दावा किया था कि उनकी पार्टी ने पता लगा लिया है कि ये कैसे किया जा रहा है। (प्रेट्र)

उमर अब्दुल्ला ने केंद्र पर साधा निशाना

अहमदाबाद : जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुजरात पहुंचते ही आतंकवाद के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि अनुच्छेद-370 हटने के छह वर्ष बाद भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं। उप राज्यपाल ने सुरक्षा की विफलता की बात कही लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है। अहमदाबाद पहुंचे उमर ने कहा कि 2019 में अनुच्छेद-370 हटाते समय केंद्र ने कहा था कि अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा लेकिन छह वर्ष बाद भी राज्य के लोगों को आतंकाद का शिकार होना पड़ रहा है। आतंक की वजह से राज्य का पर्यटन उद्योग ठप हो गया है। गुजरात से बड़ी संख्या में पर्यटक जम्मू-कश्मीर आते हैं, आतंक घटनाओं से पर्यटन प्रभावित हुआ है। (राब्यू)

उठक-बैठक लगा माफी मांगने वाले आइएएस एसडीएम पद से हटाए गए

▶ शासन ने लिया मामले का संज्ञान, राजस्व परिषद से किए गए संबद्ध

▶ पुवायां एसडीएम ने अधिवक्ताओं के सामने लगाई थी उठक-बैठक

अधिवक्ताओं के सामने उठक-बैठक लगाते रिंकू सिंह। फाइल

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर

पुवायां में वकीलों के सामने उठक बैठक लगाने वाले आइएएस रिंकू सिंह राही को शासन ने एसडीएम पद से हटा दिया है। उन्हें राजस्व परिषद से संबद्ध किया गया है। तीन दिन पूर्व रिंकू सिंह को यहां संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद पर भेजा गया था। पुवायां में अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन और एसडीएम चित्रा निर्वाल के प्रति नाराजगी को देखते हुए डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने रिंकू सिंह को वहां का एसडीएम बनाया था।

मंगलवार को कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने तहसील परिसर में शौचालय के बाहर लघुशंका कर रहे अधिवक्ता के मुंशी और कुछ लोगों से उठक-बैठक लगवा दी थी। अधिवक्ताओं ने शौचालय गंदे बताते हुए इसे प्रशासन की लापरवाही बताया तो उन्होंने कहा कि गलती किसी की हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। एसडीएम होने के नाते शौचालय गंदे होने के लिए वह जिम्मेदार हैं। इतना कहकर वहां उठक-बैठक लगाते हुए माफी मांगने लगे। अधिवक्ताओं ने उन्हें ऐसा करने से रोका। रिंकू सिंह के इस तरह माफी मांगने से संबंधित खबर इंटरनेट मीडिया व प्रिंट में प्रसारित हो गई। इसका शासन ने संज्ञान लिया। जिलाधिकारी से भी रिपोर्ट मांगी गई थी।

पीठ पर गाय को बांध खतरनाक पहाड़ी रास्ता तय कर पहुंचाया अस्पताल

जागरण संवाददाता, सिरमौर

जहां बहुत से लोग पशुओं को बेसहारा छोड़ पीछा छुड़ाते हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश के कुराई गांव से दो ग्रामीणों ने करुणा और जिम्मेदारी की मिसाल पेश की। दया राम और लाल सिंह ने बीमार गाय को बेसहारा नहीं छोड़ा, बल्कि उसे पीठ पर रस्सियों से बांधकर 400 मीटर तक का खतरनाक पहाड़ी रास्ता तय किया। यह वही रास्ता था, जो टूटा, संकरा और फिसलन भरा था। यहां एक गलत कदम जानलेवा हो सकता था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। गाय को पशु अस्पताल तक पहुंचाकर उसकी जान बचाई।

दरअसल दीपराम शर्मा की करीब दो क्विंटल वजन की गाय बीमार हो गई थी। इसके बाद गांव के लोग मदद के लिए आगे आए। दया राम और लाल सिंह ने गाय को पीठ पर बांधकर लोगों की मदद से एक जगह 300 और दूसरी 400 मीटर चढ़ाई वाला रास्ता पार करवाया। कुराई गांव से पशु अस्पताल लगभग तीन किलोमीटर दूर क्यारी गुडाहां में है। गाय को उठाकर टूटा हिस्सा पार करवाकर अस्पताल पहुंचाने के अलावा ग्रामीणों के पास अन्य कोई विकल्प नहीं था।

पशु अस्पताल क्यारी गुडाहां में गाय का उपचार करवाया गया। एक दिन गाय को पशु अस्पताल में रखा तथा उसके बाद दीपराम उसे घर ले गए। गाय की जान बचाने को ग्रामीणों के इस अनूठे प्रयास की हर तरफ चर्चा हो रही है।

हौसले को सलाम

▶ दया राम व लाल सिंह ने मानवता, संवेदनशीलता और सच्ची गोसेवा का उदाहरण पेश किया

▶ गाय की जान बचाने के लिए ग्रामीणों के इस अनूठे प्रयास की हर तरफ हो रही चर्चा

सच्ची गोसेवा की जीवंत तस्वीर

आज जहां सड़कों पर घूमती बेसहारा गायें आम देखी जा सकती हैं, ऐसे में इस घटना ने मानवता, संवेदनशीलता और सच्ची गोसेवा की जीवंत तस्वीर खींच दी है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा इस घटना का वीडियो बेहद मार्मिक है।

सिरमौर के क्यारी गुडाहां पंचायत के कुराई गांव में बीमार गाय को पीठ पर उठाकर ले जाते हुए दयाराम व लाल सिंह। वीडियो ग्रैब

सेना की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान भेजने वाला जासूस गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पटियाला: पुलिस ने भारतीय सेना की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान भेजने के आरोप में एक जासूस को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चार मोबाइल भी बरामद किए गए हैं, जिनका उपयोग वह पाकिस्तान में बैठे लोगों को सेना की खुफिया जानकारी भेजने के लिए कर रहा था।

एसएसपी वरुण शर्मा ने बताया कि पटियाला के गांव फरीदपुर निवासी 38 वर्षीय गुरप्रीत सिंह हनीट्रैप में फंसने के बाद डेढ़ वर्ष से जासूसी कर रहा था। गुरप्रीत फेसबुक पर पंजाबी कुड़ी नाम से फेसबुक प्रोफाइल पर बात करता है, जिस पर लिव इन कराची लिखा है। पंजाबी कुड़ी प्रोफाइल यूजर की सलाह पर गुरप्रीत ने दिसंबर 2024 में अपने नाम से बीएसएनएल का सिम लिया और नंबर पाकिस्तान में रहने वाले किसी लड़के या लड़की को दे दिया। इस नंबर पर पाकिस्तान में बैठे अज्ञात लोग वाट्सएप चला रहे हैं। गुरप्रीत सिंह विभिन्न एप के जरिये पाकिस्तान में बात कर रहा था। काफी समय से केंद्रीय एजेंसियां उस पर नजर रख रही थीं।

'दिल्ली पुलिस ने महिला से कहा-जय श्रीराम बोलो, नहीं कहने पर 25,000 मांगे'

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता: बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस पर मालदा जिला निवासी जिस बांग्लाभाषी प्रवासी श्रमिक परिवार की महिला और उसके बच्चे की पिटाई व प्रताड़ना का आरोप लगाया था, तृणमूल कांग्रेस उस परिवार को बुधवार को कोलकाता ले आई। यहां तृणमूल भवन में सत्तारूढ़ दल के नेताओं की मौजूदगी में एक संवाददाता सम्मेलन में मारपीट की शिकार महिला सजनूर परवीन ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। सजनूर ने बताया कि दिल्ली पुलिस के लोगों ने उनसे जय श्रीराम कहने को कहा। दावा किया कि मुस्लिम होने के कारण जय श्रीराम कहने से उन्होंने इन्कार कर दिया। इसके बाद, उनसे 25,000 रुपये मांगे गए। दावा किया कि रुपये नहीं देने पर उन्हें और उनके बच्चे को पीटा गया। मालूम हो कि मुख्यमंत्री ममता ने रविवार को अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट कर दावा किया था कि दिल्ली पुलिस ने बांग्ला बोलने के चलते मालदा निवासी महिला और उसके बच्चे को बेरहमी से पीटा।

बंगाल में मतदाता सूची में नए नाम शामिल करने में हुई अनियमितता

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

▶ सीईओ ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को लिखा पत्र

▶ चुनाव आयोग ने 14 अगस्त तक मांगी जांच रिपोर्ट

प्रतीकात्मक

बिहार की तरह बंगाल में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण जल्द शुरू करने की गहमागहमी के बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों को कहा है कि पिछले एक साल में सूची में नए नाम शामिल करने में अनियमितताएं हुई हैं।

सीईओ कार्यालय ने नियमित मतदाता सूची जांच और नमूना सर्वेक्षण के दौरान इन अनियमितताओं को चिन्हित किया है। उन्होंने सभी डीईओ को पिछले एक साल में मतदाता सूची में जोड़े गए सभी नए नामों की गहन जांच और सत्यापन करने का निर्देश दिया है। साथ ही इस प्रक्रिया की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बनाने का भी निर्देश दिया है। सीईओ ने सभी डीईओ से इस संबंध में 14 अगस्त तक एक जांच रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। सीईओ कार्यालय ने इस गंभीर अनियमितता को देखते हुए तीन जिलों के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को चेतावनी भी जारी की है। साथ ही उन्होंने पत्र में कहा कि सामने आई अनियमितताओं को देखते हुए कम से कम दो ईआरओ के खिलाफ कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। इधर, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने सीईओ द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) को जारी नवीनतम पत्र पर कहा कि यह लोकतंत्र के साथ एक घिनौनी धोखाधड़ी को उजागर करता है।

बिहार में सिम बाक्स से फर्जी एक्सचेंज का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना: आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने बिहार में सुपौल की तरह भोजपुर में भी साइबर ठगी के अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। भोजपुर जिले के नारायणपुर गांव में सिम बाक्स की मदद से फर्जी तरीके से समानांतर एक्सचेंज का संचालन किया जा रहा था। गिरोह के तार भी कंबोडिया, थाईलैंड एवं अन्य देशों के साइबर अपराधियों से जुड़े हैं। मामले में आरोपित मुकेश कुमार को चार सिम बाक्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। ईओयू ने सुपौल में अंतरराष्ट्रीय साइबर सिंडिकेट के भंडाफोड़ के बाद मामले की विस्तृत जांच के लिए एसआइटी का गठन किया था। इसी सिलसिले में एसआइटी को भोजपुर में फर्जी एक्सचेंज चलाने की सूचना मिली जिसके बाद बुधवार को छापेमारी कर मामले का राजफाश किया गया। यहां भी सिम बाक्स के माध्यम से कंबोडिया, थाईलैंड और अन्य देशों की साइबर धोखाधड़ी एवं फ्राड से जुड़ी इंटरनेट काल को लोकल जीएसएम काल में रूपांतरित कर लोगों से साइबर धोखाधड़ी की जा रही थी।

सीबीआइ-पुलिस जांच के विरुद्ध सुरेंद्र कोली के लिए हथियार बना आरटीआइ

आशुतोष गुप्ता • जागरण

▶ सुरेंद्र कोली ने कई विभागों में लगाई थीं एक हजार से अधिक आरटीआइ

▶ आरटीआइ में मिले विरोधाभासी जवाब से कोली व पंधेर को मिली राहत

डा. वीरेश राज शर्मा। स्वयं

गाजियाबाद: मुंबई में सिलसिलेवार ट्रेन धमाकों के सभी 12 आरोपितों को 19 साल बाद बाम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में बरी कर दिया था। इस मामले में आरटीआइ ने अभियोजन पक्ष के मामले को ध्वस्त करने में अहम भूमिका निभाई। देश के चर्चित निठारी कांड में भी दोषी सुरेंद्र कोली के लिए आरटीआइ बरी होने का आधार बन गया। सुरेंद्र कोली ने डासना जेल में रहते हुए केस से संबंधित विभागों में एक हजार से अधिक आरटीआइ आवेदन किए। इन जवाबों के माध्यम से कोली ने कोर्ट में अपना केस खुद लड़ा। आरटीआइ के जवाबों में विरोधाभास होने के कारण यह मामला भी पुलिस व सीबीआइ पर भारी पड़ गया। इससे सुरेंद्र कोली के साथ मोनिंदर सिंह पंधेर को भी राहत मिल गई। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट से दोनों को राहत मिल गई।

निठारी कांड में जब दोनों आरोपितों को डासना जेल लाया गया था तो पंधेर के पास अधिवक्ताओं की फौज थी, लेकिन कोली के पास वकील नहीं था। वह अनपढ़ था। जेल में उसने पढ़ना-लिखना सीखा। कानूनी किताबों से केस को समझा। इसके बाद कोली ने फोरेंसिक लैब, विकास प्राधिकरण, अस्पताल, पुलिस समेत विभिन्न विभागों में एक हजार से अधिक आरटीआइ लगाईं। इनसे मिले दस्तावेज का अध्ययन कर जवाब तैयार कर कोर्ट में पेश किए। जेल के सूत्र बताते हैं कि कोली यदि 18 घंटे जागता था तो इसमें से 15 घंटे पढ़ता था। तत्कालीन डासना जेल अधीक्षक डा. वीरेश राज शर्मा का कहना है कि कोली जेल में आने के बाद ही साक्षर हुआ। वह कानूनी किताबें पढ़ता था और हमेशा पन्नों पर लिखता रहता था। लगातार वह जेल प्रशासन से आरटीआइ के लिए मदद मांगता था। नियमानुसार जेल से उसके दस्तावेज का आदान-प्रदान कराया जाता था।

आरटीआइ से मिली नालों की गहराई

फिर लड़ी लड़ाई : सुरेंद्र कोली ने पुलिस व सीबीआइ की केस डायरी पढ़ने के बाद नोएडा विकास प्राधिकरण से आरटीआइ के जरिये उस नाले की लंबाई-चौड़ाई और गहराई का पता किया, जिसमें बच्चों के कंकाल मिले थे। सुरेंद्र कोली का आरोप था कि नाले से मिली हड्डियों से उसका कोई लेना-देना नहीं है। उसने नोएडा के एक अस्पताल पर किडनी रैकेट चलाने का आरोप लगाते हुए हड्डियों का कनेक्शन अस्पताल से जोड़ा। इसके बाद अलग-अलग सवालों पर प्राधिकरण से भी अलग-अलग जवाब मिले। इनमें पुलिस और सीबीआइ की थ्योरी में विरोधाभास था। इसे ही हथियार बनाकर कोर्ट में पेश किया। कोली कोर्ट में बहस नहीं कर पाता था, इसलिए अपने सभी जवाब कोर्ट में लिखित रूप से प्रस्तुत किए। बार-बार कोर्ट में वह कहता रहा कि असली आरोपित पकड़ से दूर है।

पंधेर कंपाउंडर बन कर रहा था बंदियों की सेवा: मोनिंदर सिंह पंधेर जेल में बंदियों की सेवा कर रहा था। जेल अस्पताल में रहकर वह कंपाउंडर बन गया था। गरीब बंदी जो जमानत नहीं करा पाते थे, उनकी भी पंधेर आर्थिक मदद करता था। जेल में धीरे-धीरे वह अध्यात्म की तरफ रुख करने लगा था, लेकिन बाद में उसे करुण अंत वाले उपन्यास पढ़ने का शौक हो गया था।

बिखर चुका है कोली का परिवार

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा

निठारी कांड के आरोपित सुरेंद्र कोली को सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा समेत 14 मामलों में बरी कर दिया है लेकिन एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे कोली की दुनिया तो उजाड़ हो चली है। अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाते-लगाते बूढ़ी मां कुंती देवी करीब तीन वर्ष पूर्व दुनिया छोड़ चुकी हैं। उत्तराखंड में स्याल्दे ब्लाक की गिवाईपानी ग्राम पंचायत के लोग कहते हैं कि रोजगार के लिए पहाड़ से दिल्ली गए गरीब को बड़े लोगों ने दोषी बना दिया। कोली के सुप्रीम कोर्ट से बरी करने पर उन्हें संतोष तो है मगर सब कुछ बर्बाद होने के बाद मिले न्याय से निराशा भी है।

देशभर में चर्चित निठारी कांड में मोनिंदर पंढेर के साथ स्याल्दे ब्लाक के मंगरूखाल तोक निवासी सुरेंद्र कोली को भी आरोपित बनाया गया। मां कुंती देवी अपने बेटे तो पत्नी शांति देवी पति के लिए हरदम ढाल बनकर लड़ती रहीं। करीब 11 वर्ष पूर्व सुरेंद्र कोली को सजा सुनाए जाने के बाद पंचायत प्रतिनिधि नारायण सिंह रावत तब अपने खर्च से सुरेंद्र कोली की मां व पत्नी को दिल्ली ले गए थे।

पत्नी का पता नहीं

पंचायत प्रतिनिधि धर्म सिंह के अनुसार सुरेंद्र कोली की पत्नी शांति देवी ने कठिन परिस्थिति में भी पति का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन हालात से हारी और दुनिया के तानों से परेशान शांति 2022 में सास कुंती देवी के चल बसने के बाद अचानक बच्चों को लेकर कहां चली गई, इसका किसी को पता नहीं है। सुरेंद्र के दो भाई दिल्ली में रहते हैं। ग्रामीणों के अनुसार छोटा भाई आनंद राम इंटर कालेज में संविदा शिक्षक के पद पर तैनात था। वह भी अपने परिवार के साथ मासी (चौखुटिया) में रहने लगा है।

साक्ष्य अधिनियम पर चीफ जस्टिस ने स्पष्ट की स्थिति

प्रथम पृष्ठ से आगे

चीफ जस्टिस ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 पुलिस हिरासत में किसी अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी के उस हिस्से को स्वीकार्य मानती है, जिससे किसी सुसंगत तथ्य का पता चलता हो। भले ही वह जानकारी अपराध स्वीकारोक्ति के बराबर क्यों न हो। कोर्ट ने कहा कि प्रविधान के मुताबिक यदि कोई अभियुक्त ऐसी जानकारी देता है, जिससे पुलिस को अपराध से जुड़ी कोई जानकारी प्राप्त करने में मदद मिली हो, तो उस विशिष्ट जानकारी के केवल उस हिस्से को ही सुबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

चार मई, 2024 को सुप्रीम कोर्ट कोली को बरी करने के मामलों में दाखिल अपीलों पर सुनवाई के लिए राजी हो गया था। इनमें में एक अपील पीड़ितों में से एक पप्पू लाल ने दाखिल की थी, जिसमें सिर्फ कोली को पक्षकार बनाया गया था। लाल ने हाई कोर्ट के 16 अक्टूबर, 2023 के फैसले को चुनौती दी थी। मामले में निचली अदालत ने पंधेर को बरी कर कोली को मृत्युदंड सुनाया था।

हाई कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को बरी करते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे मामला साबित करने में नाकाम रहा है। हाई कोर्ट ने जांच पर भी सवाल उठाए थे। हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को 12 और पंढेर को दो मामलों में दी गई मृत्युदंड की सजा को पलटते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष दोनों अभियुक्तों के खिलाफ संदेह से परे मामला साबित करने में नाकाम रहा है। जांच जिम्मेदार जांच एजेंसियों पर जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात से कम नहीं है। हाई कोर्ट ने मामले में हुई बरामदगियों और अभियुक्तों की अपराध स्वीकारोक्ति के बयानों को स्वीकार नहीं किया था।

निठारी कांड ने देश को हिला दिया था। इसमें अभियुक्तों पर अपहरण करने, हत्या और यौन शोषण के आरोप थे। इस मामले में कुल 19 केस दर्ज हुए थे। सीबीआइ ने सुबूतों के अभाव में तीन मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, जबकि शेष 16 मामलों में से तीन में कोली को पहले ही बरी कर दिया गया था। एक मामले में उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। वकील के मुताबिक कोली की मौत की सजा उम्रकैद में बदलने के आदेश को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है, जो अभी लंबित है। हालांकि इस मामले में कोली को निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से फांसी की सजा हुई थी, लेकिन फांसी में अत्यधिक देरी के आधार पर हाई कोर्ट ने उसकी फांसी उम्रकैद में तब्दील कर दी थी। इसका मतलब है कि आज के फैसले के बावजूद कोली जेल से बाहर नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट में पंधेर के खिलाफ दो अपीलें सीबीआइ की थीं और एक अपील पीड़ित अनिल हलदर की ओर से थी।

****

1962 के बाद से चीन अरुणाचल में न तो एक इंच घुसा है और न उसने एक इंच जमीन हथियाई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में आपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान यह बयान दिया।

हर 12 दिन में धरती का नक्शा बनाएगा निसार

भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग की उड़ान हुई शुरू, 19 मिनट में अपनी कक्षा में पहुंच गया

पूरी धरती पर नजर रखेगा इसरो और नासा की ओर से विकसित उपग्रह

- जीएसएलवी एफ-16 ने 19 मिनट की उड़ान के बाद 745 किलोमीटर की दूरी पर उपग्रह को स्थापित किया
- इसे अंतरिक्ष की दुनिया का सबसे महंगा मिशन बताया जा रहा, अनुमानित लागत 1.5 अरब डालर

श्रीहरिकोटा से बुधवार को निसार सेटेलाइट के साथ प्रक्षेपित जीएसएलवी-एफ16 राकेट। रायटर

श्रीहरिकोटा, प्रेट्र : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के बीच साझेदारी के तहत बुधवार को जीएसएलवी राकेट की सफल उड़ान के साथ निसार उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया। यह उपग्रह 240 किमी चौड़े रडार क्षेत्र का उपयोग करके हर 12 दिन में धरती का मानचित्र बनाएगा, जिससे विज्ञानियों और आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियों को हिमालय में ग्लेशियरों के पीछे हटने से लेकर दक्षिण अमेरिका में संभावित भूस्खलन क्षेत्रों तक हर चीज पर नजर रखने के लिए डाटा उपलब्ध होगा।

नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार) उपग्रह को दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। हालांकि, इसरो ने अतीत में रिसोर्ससेट और रीसेट सहित पृथ्वी पर नजर रखने वाले उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है, लेकिन इन उपग्रहों से एकत्रित डाटा भारतीय क्षेत्र तक ही सीमित था। इसरो और नासा ने मिलकर पहली बार ऐसा सेटेलाइट लांच किया है, जो पूरी धरती पर नजर रखेगा। इसरो के जीएसएलवी एफ-16 ने लगभग 19 मिनट की उड़ान के बाद लगभग 745 किलोमीटर की दूरी पर निसार उपग्रह को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा (एसएसपीओ) में स्थापित कर दिया, जिससे विश्व की दो शीर्ष अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच सहयोग का सफल रहा। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जीएसएलवी एफ-16 ने निसार उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया है।

बुधवार का मिशन कथित तौर पर दुनिया का सबसे महंगा मिशन था, जिसकी अनुमानित लागत 1.5 अरब डालर थी। इसके अलावा यह सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा के लिए पहला जीएसएलवी मिशन भी था। अब तक सभी जीएसएलवी मिशन जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर आर्बिट (जीटीओ) में ही गए हैं। एसएसपीओ मिशन होने के नाते इसकी पूरी तरह सफल बनाने के लिए कई विश्लेषण और अध्ययन किए गए।

नारायणन ने कहा कि सभी वाहन प्रणालियों का प्रदर्शन अपेक्षा और पूर्वानुमान के अनुरूप सामान्य रहा। आज हमने इच्छित कक्षा प्राप्त कर ली।

आपदा से निपटने को अधिक समय

नासा ने कहा कि निसार से प्राप्त डाटा सरकार और प्रशासन को प्राकृतिक और मानव-जनित खतरों से निपटने के लिए योजना बनाने में महत्वपूर्ण इनपुट मुहैया कराएगा। निसार खतरे की निगरानी के प्रयासों में मदद कर सकता है और संभावित रूप से प्रशासन को संभावित आपदा से निपटने के लिए तैयारी करने हेतु अधिक समय दे सकता है।

भूकंप और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की निगरानी

निसार उपग्रह पृथ्वी की भूमि और बर्फ का 3-डी तस्वीरें प्रदान करेगा। दिन-रात बादलों और हल्की बारिश के पार देखने की अपनी क्षमता से यह उपग्रह डाटा यूजरों को भूकंप और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की निरंतर निगरानी करने और यह निर्धारित करने में सक्षम बनाएगा कि ग्लेशियर और बर्फ की चादरें कितनी तेजी से बदल रही हैं।

भूमि व बर्फ के बदलाव पर नजर

इसरो के अनुसार, इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य अमेरिकी और भारतीय विज्ञानी समुदाय के साझा हित के क्षेत्रों में भूमि और बर्फ के बदलाव, भूमि पारिस्थितिकी तंत्र और समुद्री क्षेत्रों का अध्ययन करना है। यह मिशन बायोमास को मापने, फसलों के विस्तार में परिवर्तन को ट्रैक करने और जलाशयों में परिवर्तन को समझने में मदद करेगा।

पवित्र पिपरहवा के बुद्ध अवशेष 127 वर्षों बाद भारत लौटे : मोदी

- अवशेष 1898 में यूपी के पिपरहवा के प्राचीन बौद्ध स्तूप की खोदाई से निकाले गए थे
- बुद्ध के अवशेष, रत्न व आभूषण उपनिवेशी शासन में भारत से बाहर ले जाए गए थे

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बताया कि पवित्र पिपरहवा के भगवान बुद्ध के अवशेष 127 लंबे वर्षों के बाद भारत लौट आए हैं। ये अवशेष 1898 में खोजे गए थे लेकिन उपनिवेशी शासन के दौरान भारत से बाहर ले जाए गए थे। पीएम मोदी ने कहा कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लिए एक खुशी का दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संबंध में एक्स पर कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट करके बताया, यह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि पिपरहवा से मिले भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 127 लंबे वर्षों के बाद घर लौट आए हैं। ये पवित्र अवशेष भगवान बुद्ध और उनके महान शिक्षाओं के साथ भारत की धरोहर की गरिमा को दर्शाते हैं। यह गौरवमयी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को संरक्षित और सुरक्षित रखने के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।" उन्होंने कहा कि जब ये पवित्र अवशेष इस वर्ष की शुरुआत में एक अंतरराष्ट्रीय नीलामी में आए, तो भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया कि ये घर लौटें। वह उन सभी की सराहना करते हैं जो इस प्रयास में शामिल रहे हैं।

अवशेषों में महात्मा बुद्ध की हड्डियों के अवशेष भी शामिल : एक वेबसाइट पिपरहवा.काम के अनुसार 'पिपरहवा परियोजना' पर शोध और जानकारी के अनुसार ये अवशेष 1898 में उत्तर प्रदेश के पिपरहवा में एक प्राचीन बौद्ध स्तूप की खोदाई के दौरान निकाले गए थे, जो भारत-नेपाल सीमा के निकट स्थित है। इन अवशेषों में गौतम बुद्ध की मानी जाने वाली हड्डियों के टुकड़े, सेलखड़ी नामक पत्थर जो मूर्ति तराशने और कलात्मक चीजों में उपयोग होता है। इसके अलावा, क्रिस्टल के संदूक, एक बलुआ पत्थर की तिजोरी और सोने के आभूषण और कीमती रत्न शामिल हैं। वेबसाइट में कहा गया है, "हड्डियों के अवशेषों को सियाम (थाईलैंड) के राजा को सौंप दिया गया था, ताकि उसे विश्व के बौद्धों में वितरित किया जा सके।"

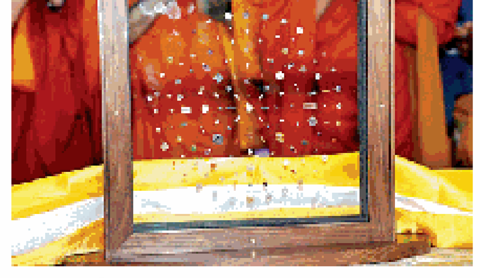
नई दिल्ली में बुधवार को पहुंचे भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेष। एएनआइ

नौकरी के बदले जमीन में कार्यवाही पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

- राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को शीर्ष न्यायालय से झटका

सीबीआइ ने 2022 में लालू के खिलाफ दर्ज किया था मामला

नई दिल्ली, एएनआइ : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने पर चल रही सुनवाई को स्थगित करने से इन्कार कर दिया। जस्टिस एमएम सुंदरेश व जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि आरोप तय करने से हाई कोर्ट में लंबित याचिका निरर्थक नहीं हो जाएगी।

मामले की सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने लालू यादव की याचिका का विरोध किया। उन्होंने आवेदन दायर करने के लिए लालू यादव पर उचित जुर्माना लगाने की भी मांग की, लेकिन अदालत ने कोई जुर्माना नहीं लगाया। लालू यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा मुकदमे पर रोक लगाने से इन्कार करने के फैसले को चुनौती दी थी। 29 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान हुए जमीन के बदले नौकरी घोटाले में मुकदमे पर रोक लगाने की लालू यादव की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है। ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए, हाई कोर्ट ने सीबीआइ की प्राथमिकी रद करने की लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सीबीआइ को नोटिस जारी किया था और सुनवाई 12 अगस्त के लिए निर्धारित की थी। 18 मई 2022 को सीबीआइ ने एक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2004 से 2009 के बीच लालू यादव ने मंत्री पद का दुरुपयोग करके परिवार के लिए ग्रुप डी रेलवे की नौकरियों के बदले में जमीन का हस्तांतरण करवाया था।

टीकाकरण में हुई प्रगति सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि : राष्ट्रपति

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को भारत में टीकाकरण के क्षेत्र में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। बंगाल के नदिया जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), कल्याणी के पहले दीक्षा समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सकों ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हुए देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के समय औसत जीवन केवल 32 वर्ष था, जो अब बढ़कर लगभग 70 वर्ष हो गया है। टीकाकरण के क्षेत्र में असाधारण प्रगति हुई है और कई बीमारियों का उन्मूलन भी संभव हुआ है। भारत को पिछले वर्ष ट्रेकोमा-मुक्त घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि मधुमेह, हृदय रोग और मोटापे जैसी समस्याओं को नियंत्रित करने में डाक्टरों की भूमिका सरकार या अन्य पक्षकारों से भी अधिक महत्वपूर्ण है।

भिलाई व जम्मू समेत पांच आइआइटी में बढ़ेंगी 65 सौ से अधिक सीटें

- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी, अगले चार सालों में चरणबद्ध तरीके से बढ़ेंगी ये सीटें
- इस शैक्षणिक सत्र के लिए भी बढ़ाई गई 13 सौ से अधिक सीटें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आइआइटी में दाखिले को लेकर बढ़ी प्रतिस्पर्धा के बीच शिक्षा मंत्रालय ने भिलाई, जम्मू सहित तीसरी पीढ़ी के देश के पांच आइआइटी में 6576 सीटें और बढ़ाने की मंजूरी दी है।

बढ़ाई गई इन सीटों को अगले चार सालों में चरणबद्ध तरीके से अमल में लाया जाएगा। मौजूदा शैक्षणिक सत्र यानी 2025-26 में इन पांचों संस्थानों में बढ़ाई गई सीटों में से 1364 सीटें बढ़ा भी दी हैं। इन सीटों पर छात्रों को इस वर्ष से दाखिला मिलेगा।

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, तीसरी पीढ़ी के जिन पांच आइआइटी में सीटों को बढ़ाने का फैसला लिया गया है, इन्हें 2015 व 2016 के बीच खोला गया था। इनमें आइआइटी भिलाई, जम्मू, पलक्कड़, धारवाड़ व तिरुपति शामिल हैं। मंत्रालय के अनुसार, सीटों को बढ़ाने की जो योजना बनाई गई है, उनमें शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 1364 सीटें, 2026-27 में 1738 सीटें, 2027-28 में 1767 सीटें और 2028-29 में 1707 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मौजूदा समय में देश में कुल 23 आइआइटी हैं, जिनमें इस बढ़ोतरी के बाद सीटों की कुल संख्या करीब 25 हजार हो गई है। देश में पहली पीढ़ी के आइआइटी में मद्रास, खड़गपुर, बांबे, दिल्ली, कानपुर, गुवाहाटी, रुड़की, बीएचयू स्थित आइआइटी हैं।

दूसरी पीढ़ी के आइआइटी में जोधपुर, रोपड़, गांधीनगर, हैदराबाद, पटना, भुवनेश्वर, मंडी और इंदौर स्थित आइआइटी आते हैं। जबकि तीसरी पीढ़ी के आइआइटी में भिलाई, जम्मू, धारवाड़, पलक्कड़, तिरुपति, गोवा व धनबाद स्थित आइआइटी आते हैं। इससे देश में उच्च स्तर पर तकनीकी शिक्षा को विस्तार मिल सकेगा।

9.7 करोड़ किसानों को दो अगस्त को मिलेगी सम्मान निधि

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त दो अगस्त को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी में विशेष कार्यक्रम में आनलाइन माध्यम से नौ करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में लगभग 20,500 करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित करेंगे।

इसकी तैयारियों को लेकर बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें देशभर के 731 कृषि विज्ञान केंद्र वर्चुअल रूप से शामिल हुए। कृषि मंत्रालय की तैयारी कार्यक्रम को जन अभियान और उत्सव के रूप में मनाने की है। 2019 से शुरू इस योजना में अभी तक 3.69 लाख करोड़ की राशि किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। कृषि मंत्री ने कहा कि हर चार महीने पर मिलने वाली दो हजार की किस्त से किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार की सहायता दी जाती है। कार्यक्रम में कृषि सखी, ड्रोन दीदी, बीमा सखी एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

मप्र में भारी वर्षा से बिगड़े हालात, गुना व शिवपुरी में सेना की तैनाती

- चंबल व सिंध नदियों में उफान, दमोह में 24 गांव बाढ़ से घिरे, 500 मकान क्षतिग्रस्त
- भोपाल अंचल में दो दिनों में 12 लोगों की हुई मौत, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर

मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गुना में सेना के रेस्क्यू आपरेशन के बाद अब शिवपुरी में भी सेना को बुलाना पड़ा है। ग्वालियर-चंबल अंचल में चंबल और सिंध नदियां उफान पर हैं। दमोह में 24 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 500 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भोपाल अंचल में पिछले दो दिनों की बाढ़ में 12 लोगों की जान चली गई है।

शिवपुरी के पचावली गांव में 30 स्कूली बच्चे फंसे हुए हैं। बदरवास के निजी स्कूल की बस बच्चों को लेने गई थी, लेकिन नाले में जलस्तर बढ़ने से रास्ता बंद हो गया। बच्चों को सरपंच के घर में सुरक्षित रखा गया है। अन्य गांवों में भी करीब 100 से अधिक लोगों के फंसे होने की सूचना है। मुख्यमंत्री ने राहत व बचाव कार्य के लिए सेना से दो हेलीकाप्टर की मांग की, ताकि फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा सके। प्रशासन ने 91 गांवों के लिए 64 राहत शिविर स्थापित किए। उधर, श्योपुर में पार्वती और सीप नदियों में उफान के कारण बड़ौदा क्षेत्र में भी जलभराव हो गया है।

मप्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फंसे लोगों को निकालते सेना के जवान। प्रेट्र

राजस्थान का मप्र से सड़क संपर्क कटा

जागरण संवाददाता, जयपुर : राजस्थान में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, दौसा, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर, टोंक सहित दर्जन भर से अधिक जिलों में हालात बिगड़े हुए हैं। प्रदेश के 14 जिलों में अगले दो दिनों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। उधर, पार्वती नदी में तेज उफान के कारण राजस्थान और मप्र का सड़क संपर्क कट गया है।

गौरीकुंड हाईवे अवरुद्ध, केदारनाथ यात्रा स्थगित

जासं, रुद्रप्रयाग : उत्तराखंड में गौरीकुंड हाईवे सोनप्रयाग से आगे 70 मीटर बह गया। इस कारण केदारनाथ धाम की यात्रा स्थगित रही। तीन हजार से अधिक यात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया। गौरीकुंड में फंसे 350 यात्रियों को पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों ने सुरक्षित निकाला। हाईवे के सुचारू होने में दो से तीन दिन लग सकते हैं।

चंबा में फटा बादल, दो गांवों में भारी नुकसान

जासं, शिमला : हिमाचल प्रदेश में चंबा की जंद्रोग पंचायत में मंगलवार रात बादल फटने से गांव भगसियार व ढलियार में भारी नुकसान हुआ। लोगों ने भागकर जान बचाई। उधर, चमोली के ज्योतिर्मठ में देवग्राम पंचायत के गांव ताके में भूस्खलन के कारण दो भवन क्षतिग्रस्त हो गए।

जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन के कारण चार की मौत

राज्य ब्यूरो • जम्मू : जम्मू-कश्मीर में तेज वर्षा और भूस्खलन के कारण तीन शिक्षकों सहित चार लोगों की जान चली गई। उधमपुर के दो शिक्षक रामबन जिले में नत्याटाप के पास बरसाती नाले को पार करते पानी के तेज बहाव में बह गए।

दिल्ली-मथुरा ट्रैक पर ट्रेनों को मिला सुरक्षा 'कवच'

- रेल मंत्री बोले-छह वर्षों में देशभर के सभी प्रमुख मार्गों पर लग जाएगा कवच

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रेलवे ने दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग के अत्यंत व्यस्त मथुरा-कोटा सेक्शन पर 'कवच-4.0' प्रणाली को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। यह पूरी तरह स्वदेशी है, जिसे भारतीय इंजीनियरों ने डिजाइन, विकसित एवं निर्मित किया है। अब सफर के दौरान रेल यात्रियों की सुरक्षा पहले से ज्यादा पुख्ता हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले छह वर्षों में देशभर के सभी प्रमुख मार्गों पर कवच को लगा दिया जाएगा।

मथुरा-कोटा सेक्शन पर प्रतिदिन 160 से अधिक मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें तथा 110 मालगाड़ियां अप-डाउन दिशा में संचालित होती हैं। ऐसे में कवच लगाना तकनीकी रूप से ही नहीं, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी बड़ी उपलब्धि है। इस प्रणाली के शुरू होने से अब लोकोपायलट को कोहरे जैसी कम दृश्यता की स्थिति में केबिन से बाहर झांकने की जरूरत नहीं होगी। सिग्नलों की जानकारी अब केबिन के अंदर ही डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होती रहेगी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' विजन से प्रेरणा लेकर यह तकनीक देश में ही विकसित की गई है। रेलवे ने इसे रिकार्ड समय में पूरा किया, जबकि कई विकसित देशों को ऐसी प्रणाली लागू करने में 20 से 30 साल लग गए। हमने कुछ ही वर्षों में पूरा कर दिखाया है। पिछले 60 वर्षों के दौरान देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर की उन्नत रेल सुरक्षा प्रणालियां स्थापित नहीं की जा सकी थीं। कवच प्रणाली की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। इसका परीक्षण तीन वर्षों तक बड़े स्तर पर किया गया।

न्यूज गैलरी

शाह ने गोवा के सीएम के पत्र का कोंकणी में दिया जवाब

पणजी : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत द्वारा एक मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर उन्हें लिखे गए पत्र का जवाब कोंकणी भाषा में दिया। सावंत ने बुधवार को शाह द्वारा लिखा गया पत्र पोस्ट किया, जो उनके उस पत्र के जवाब में था, जिसमें उन्होंने आनलाइन धोखाधड़ी में सीबीआइ द्वारा केस दर्ज करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने पत्र को संज्ञान में लेने के लिए अमित शाह को धन्यवाद दिया। (प्रेट्र)

भाजपा सांसद ने दलाई लामा को भारत रत्न देने की मांग की

नई दिल्ली : अरुणाचल प्रदेश से भाजपा सांसद तापिर गाओ ने बुधवार को केंद्र से दलाई लामा को भारत रत्न देने का आग्रह किया व उन्हें अहिंसा और करुणा का वैश्विक प्रतीक बताया। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान मुद्दा उठाते हुए गाओ ने कहा कि भारत अहिंसा की भूमि है। दलाई लामा अहिंसा व करुणा के दूत हैं। सरकार को उन्हें भारत रत्न देकर उनके योगदान को मान्यता देनी चाहिए। (प्रेट्र)

अभिनेता प्रकाश राज से ईडी ने की चार घंटे पूछताछ

हैदराबाद : अभिनेता प्रकाश राज बुधवार को अवैध आनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़े मनी लांड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय के समक्ष पेश हुए। प्रकाश राज से लगभग चार घंटे तक पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2016 में आनलाइन सट्टेबाजी एप के साथ काम किया था, लेकिन नैतिक आधार पर उन्होंने इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने इन एप का प्रचार करना बंद कर दिया है। अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। (प्रेट्र)

गोवा घोटाले में ईडी ने 200 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली : ईडी ने बुधवार को कहा कि उसने गोवा के प्रमुख स्थानों पर स्थित 200 करोड़ से अधिक की संपत्तियां कुर्क की हैं। यह संपत्तियां भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लांड्रिंग जांच के तहत कुर्क की गई हैं। घोटाले में एक व्यक्ति शामिल है, जिसने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था लेकिन वह असफल रहा था। (प्रेट्र)

मेघालय में अवैध रूप से बने छह मकान ढहाए गए

शिलांग : मेघालय में अवैध रूप से निर्मित छह मकानों को गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएडीसी) ने ध्वस्त कर दिया। असम से लगती मेघालय की सीमा पर इस अतिक्रमण के लिए स्वदेशीकरण की कार्रवाई की गई। जीएचएडीसी के उप मुख्य कार्यकारी सदस्य निकमन च. मारक ने बताया कि परिषद ने अवैध रूप से रहने वाले लोगों को पहले नोटिस जारी किया था, लेकिन वे संपत्ति के दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहे। (प्रेट्र)

असम से सात घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया

गुवाहाटी : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि सुरक्षा बलों ने बुधवार को असम के श्रीभूमि जिले से सात घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेज दिया। मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए बुधवार तड़के श्रीभूमि से सात बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेज दिया गया। (प्रेट्र)

बिहार की पूर्व मंत्री बीमा भारती से ईओयू ने की पूछताछ

पटना : पिछले साल फरवरी में नीतीश सरकार के विश्वासमत के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों को प्रलोभन देने के मामले में बुधवार को पूर्व मंत्री बीमा भारती से आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने चार घंटे तक पूछताछ की। ईओयू के अनुसार, बीमा भारती ने कुछ प्रश्नों के जवाब दिए, जबकि कुछ प्रश्नों के संतोषजनक जवाब नहीं दे पाईं। उनसे पहली नोटिस मिलने के बावजूद ईओयू कार्यालय न आने को लेकर भी सवाल-जवाब किए गए। (राब्यू)

सुविधा

अभी 25 हजार से अधिक की नकदी होने पर रकम जब्त कर लेती थी नेपाल पुलिस, पर्यटन पर पड़ते प्रभाव को देखकर नेपाल के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया निर्णय

भारतीय सवा चार लाख नकद लेकर जा सकेंगे नेपाल

सतीश पांडेय • जागरण

महराजगंज के सोनौली में स्थित भारत-नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा। जागरण आर्काइव

गोरखपुर : पर्यटन, उपचार और कारोबार के सिलसिले में नेपाल जाने वाले लोग अब ज्यादा नकदी ले जा सकेंगे। नेपाल सरकार ने भारतीयों के लिए नकद राशि की सीमा 25 हजार से बढ़ाकर 4.25 लाख रुपये कर दी है। अन्य विदेशी यात्री पांच हजार अमेरिकी डालर (4,34,048 रुपये) व ट्रैवलर्स चेक साथ ले जा सकेंगे। छह लाख तक की रकम ले जाने वाले अन्य विदेशी नागरिकों को भंसार कार्यालय पर लिखित जानकारी देनी होगी। अभी तक भारतीयों के पास यदि 25 हजार रुपये से अधिक की धनराशि मिलती थी, तो कस्टम या नेपाल पुलिस उसे जब्त कर लेती थी। नेपाल सरकार ने यह निर्णय पर्यटन उद्योग और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए लिया है।

भारत और नेपाल के बीच आने-जाने के लिए पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता नहीं है। इस कारण बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक काठमांडू, पोखरा, पशुपतिनाथ समेत अन्य पर्यटन स्थलों पर घूमने जाते रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग दांत और आंख का उपचार कराने भी नेपाल जाते हैं। भारत की तुलना में वहां उपचार सस्ता है। मसाला, सूखा मेवा और कास्मेटिक उत्पाद के कारोबार से जुड़े व्यापारियों का भी आना-जाना लगा रहता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय पर्यटकों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही थी। 25 हजार रुपये की नकदी वाली व्यवस्था को इसकी प्रमुख वजह माना जा रहा था। नेपाल मंत्रिमंडल की बैठक में उप प्रधानमंत्री-सह वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने भारतीय पर्यटकों के लिए नकद राशि की सीमा बढ़ाने की घोषणा की। नकद ले जाने की सीमा भले बढ़ा दी गई है, लेकिन नेपाल में 100 से अधिक मूल्य के भारतीय नोटों के चलन पर रोक जारी है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले भारतीय इस फैसले से प्रसन्न हैं।

डीजीसीए को घरेलू एयरलाइन के 23 आडिट में मिलीं 263 खामियां

- डीजीसीए ने कहा- एअर इंडिया की सर्वाधिक 93 खामियां सामने आईं, इनमें 19 लेवल-वन यानी गंभीर किस्म की

मुंबई, प्रेट्र : नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बुधवार को बताया कि पिछले एक साल में आठ घरेलू एयरलाइन कंपनियों के 23 आडिट के दौरान उसे 263 खामियां मिली हैं। इनमें से कुछ खामियां ऐसी हैं जिनमें तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जरूरत है। इसके लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

डीजीसीए के आंकड़ों के अनुसार, टाटा समूह के स्वामित्व वाली एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस में 93 खामियां सामने आई हैं। इनमें 19 लेवल-वन के हैं, जिन्हें गंभीर सुरक्षा जोखिम माना जाता है और इनके लिए विमान सेवा देने वाली कंपनी को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

सूत्रों के अनुसार, डीजीसीए को एअर इंडिया के प्रशिक्षण, चालक दल के आराम और ड्यूटी अवधि के मानदंडों से संबंधित उल्लंघनों का पता चला है। डीजीसीए ने कहा कि वह परिचालन की सुरक्षा बढ़ाने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर आडिट करता है।

बयान में यह भी कहा गया कि व्यापक परिचालन और बड़े आकार के बेड़े वाली एयरलाइन कंपनियों के लिए आडिट में खामियों की अधिक संख्या सामान्य है। पिछले वर्ष में इंडिगो की 23, स्पाइसजेट की 14, अलायंस एयर की 57, विस्तार जेट की 35, घोडावत स्टार की 41 और पूर्ववर्ती विस्तारा की 17 खामियां सामने आईं।

वैश्विक स्तर पर, विमानन नियामकों को प्रमुख एयरलाइन कंपनियों के साथ इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

अयोध्या में बहू ने फेंका था कैंसर पीड़ित सास को सड़क किनारे

जागरण संवाददाता, अयोध्या : रामनगरी में ई-रिक्शा से वृद्ध महिला को फेंकने वाले परिवारवालों की पुलिस ने पहचान कर ली है। महिला का नाम भगवती था, जो गोंडा जिले के नबाबगंज नगवां की रहने वाली थीं। वृद्धा कैंसर से पीड़ित थीं और परिवार की माली हालत ऐसी नहीं थी कि घर वाले वहन कर पाते। बीती 24 जुलाई की रात को किशुनदासपुर में ई-रिक्शा से पहुंचे तीन लोग सड़क के किनारे लावारिस उतार कर भाग गए थे। पुलिस ने महिला को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया, जहां दूसरे दिन निधन हो गया था।

बीमार भगवती से दामन छुड़ाने के लिए बहू ने रामनगरी लाकर बेसहारा छोड़ दिया था। पहले रेतिया में छोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन लोगों के विरोध के बाद भागना पड़ा, जिसके बाद दर्शन नगर के किशुनदासपुर में छोड़ दिया गया।

****

6 करोड़ का घोटाला कर के फरार क्लर्क मथुरा में पकड़ा गया। उसने पंजाब में फरीदकोट स्थित एसबीआइ शाखा में घोटाला किया था। पुलिस के आने की भनक लगने पर वह नौवीं मंजिल की बालकनी से लटक गया। पकड़ने पर जान देने की धमकी देता रहा।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 31 जुलाई, 2025

कदाचार की सूरत में जज को हटाने की सीजेआइ कर सकते हैं सिफारिश

माला दीक्षित ● जागरण

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

- सरकारी आवास से नकदी मिलने के आरोपों से घिरे जस्टिस वर्मा की आपत्तियों पर कोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख
- कहा- चीफ जस्टिस राष्ट्रपति व पीएम को सूचना दे सकते हैं, सीजेआइ की सिफारिश संसद पर बाध्यकारी नहीं
- अगर आंतरिक जांच प्रक्रिया पर आपत्ति थी तो आपने उसे पहले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दी?

जस्टिस यशवंत वर्मा। फाइल

नई दिल्ली: सरकारी आवास से नकदी मिलने के आरोपों का सामना कर रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा की ओर से बुधवार को चीफ जस्टिस की उन्हें हटाने को लेकर उठाई गई आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। शीर्ष कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि चीफ जस्टिस कोई पोस्ट आफिस नहीं हैं कि वह सिर्फ सूचना का आदान-प्रदान करें। न्यायपालिका के मुखिया होने के नाते उनका राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्य है। अगर उन्हें उपलब्ध सामग्री के आधार पर जज का कदाचार नजर आता है तो वे इसकी सूचना दे सकते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को उन्होंने इसकी सूचना दी। वह निश्चित तौर पर पद से हटाने की सिफारिश कर सकते हैं। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि सीजेआइ की सिफारिश संसद पर बाध्यकारी नहीं है। संसद स्वतंत्र है और वह अपना काम करेगी। आगे कार्यवाही करनी है कि नहीं, ये राजनीतिक निर्णय है, लेकिन न्यायपालिका को समाज को संदेश देना है कि प्रक्रिया का पालन हुआ है। याचिका पर बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने जस्टिस वर्मा से सवाल किया कि अगर आपको आंतरिक जांच प्रक्रिया पर आपत्ति थी और आप उसे असंवैधानिक मान रहे थे तो आपने उसे पहले चुनौती क्यों नहीं दी? जब कपिल सिब्बल ने कहा कि वह कमेटी के सामने इसलिए पेश हुए क्योंकि उन्हें लगा कि कमेटी पता लगा लेगी कि पैसा किसका है। लेकिन जस्टिस दत्ता ने कहा कि कमेटी के विचार का यह दायरा ही नहीं था कि वह पता लगाती कि पैसा किसका है? कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि मामले पर ज्यादा चर्चा न हो, तो संसद में मामला है और उसे ही तय करने दीजिए। हम कमेटी की रिपोर्ट पर यहां चर्चा नहीं करेंगे। आपको जो संवैधानिक दलीलें देनी हैं, वह दीजिए। कोर्ट ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट सिर्फ प्रारंभिक रिपोर्ट है। उसकी सिफारिश भी बाध्यकारी नहीं है। महाभियोग के प्रस्ताव पर संसद स्वतंत्र होकर निर्णय लेगी। सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को संविधान के अनुच्छेद 124 के मुताबिक सिर्फ संसद में महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। सीजेआइ भी इस रिपोर्ट के आधार पर उन्हें हटाने की सिफारिश नहीं कर सकते। ये संविधान सम्मत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 141 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश का कानून हो जाता है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि जस्टिस वर्मा एक जज हैं। उन्होंने संविधान और कानून के पालन की शपथ ली है तो वे कानून को चुनौती कैसे दे सकते हैं? हम सभी न्यायाधीशों को मालूम है कि जज को कैसे आचरण करना चाहिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की उस दलील से सहमति जताई कि उनके निवास पर मिली जलती हुई नोटों की गड्डियों का वीडियो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर नहीं अपलोड किया जाना चाहिए था। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि जलती हुई नकदी का वीडियो वेबसाइट पर अपलोड करना प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता।

कोर्ट में आज एक और याचिका थी जिसमें वकील मैथ्यू जे नेदुंपरा ने दिल्ली पुलिस को जस्टिस वर्मा के घर नकदी मिलने के मामले में एफआइआर दर्ज कर जांच करने का निर्देश मांगा था लेकिन कोर्ट ने नेदुंपरा से सवाल किया कि उन्होंने पुलिस को कब शिकायत दी जिस पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्होंने याचिका में पुलिस पर आरोप लगाया है कि उसने शिकायत पर कार्रवाई नहीं की।

इसके अलावा कोर्ट ने नेदुंपरा से यह भी कहा कि वह हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताएं कि उन्हें आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट कहां से प्राप्त हुई।

सुप्रीम कोर्ट कभी भी प्रधान न्यायाधीश केंद्रित अदालत नहीं होनी चाहिए

- चीफ जस्टिस बीआर गवई ने ने बार व बेंच को 'समान भागीदार' माना
- गवई ने कहा- उनके फैसले पूर्ण अदालत के निर्णय ही होते हैं

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी ''प्रधान न्यायाधीश-केंद्रित अदालत'' नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रधान न्यायाधीश केवल समानता में पहले हैं। सीजेआइ ने कहा कि उन्होंने हमेशा बार और बेंच को न्याय प्रशासन के संस्थान में ''समान भागीदार'' माना है।

प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के आयोजित एक समारोह में कहा, 'मेरा मानना है कि प्रधान न्यायाधीश केवल समानता में पहले हैं और सर्वोच्च न्यायालय कभी भी प्रधान न्यायाधीश-केंद्रित अदालत नहीं होनी चाहिए।''

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय सभी न्यायाधीशों और बार के सदस्यों की अदालत होनी चाहिए। इसलिए वह लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली में विश्वास करते हैं। इसलिए वह जो भी निर्णय लेते हैं, वे पूर्ण अदालत के निर्णय होते हैं।'' सीजेआइ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले कई वर्षों में 26 मई से 11 जुलाई के बीच आंशिक कार्य दिवसों के दौरान सबसे अधिक मामलों का निपटारा किया है। इस वर्ष शीर्ष अदालत ने अपनी पारंपरिक गर्मी की छुट्टियों को ''आंशिक अदालत कार्य दिवस'' के रूप में पुनः नामित किया था। उन्होंने कहा, 'मुझे कहना चाहिए कि आप सभी और मेरे सहयोगियों के सहयोग से हमने पिछले कई वर्षों में आंशिक कार्य दिवसों के दौरान सबसे अधिक मामलों का निपटारा किया है।''

सीजेआइ ने कहा कि बार के सदस्यों ने हमेशा उन्हें बहुत सारा प्यार और स्नेह दिया है। वास्तव में उन्होंने हमेशा बार और बेंच को न्याय प्रशासन के संस्थान में समान भागीदार माना है। वे न्याय प्रशासन के संस्थान के सुनहरे रथ के दो पहिए की तरह हैं।

न्यूज गैलरी

हाई कोर्ट ने जमानत नहीं देने पर मांगा स्पष्टीकरण

जयपुर : राजस्थान उच्च न्यायालय ने जमानती अपराध के बावजूद सेक्सटार्शन की आरोपित दो महिलाओं को जमानत नहीं देने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायाधीश अनिल उपमन की अदालत ने मितू पारीक और इंदू वर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि दोनों महिलाओं के खिलाफ दर्ज धाराएं जमानती अपराध की श्रेणी में आती हैं, लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट और एडीजे ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए, उन्हें अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा। (जासं)

बागमती एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना साजिश के कारण हुई

नई दिल्ली: तमिलनाडु के कवराईपेट्टई स्टेशन पर 11 अक्टूबर, 2024 को मैसूरु-दरभंगा बागमती एक्सप्रेस की दुर्घटना का कारण साजिश बताया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने बताया कि बदमाशों द्वारा ट्रैक इंटरलाकिंग सिस्टम में तोड़फोड़ की गई थी। दक्षिणी सर्किल के रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) एएम चौधरी ने कहा कि जांच में पाया गया है कि बागमती एक्सप्रेस और खड़ी मालगाड़ी के बीच टक्कर किसी उपकरण के अचानक विफलता के कारण नहीं हुई, बल्कि बदमाशों द्वारा एलएच (बाएं हाथ) टंग रेल की डिजाइन में जबरदस्ती परिवर्तन करने के कारण हुई। सीआरएस ने कहा कि इसलिए इस दुर्घटना को तोड़फोड़ की श्रेणी में रखा गया है। (प्रेट्र)

'हरिद्वार में गंगा किनारे 48 स्टोन क्रशर बंद कराएं'

नैनीताल : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हरिद्वार में रायवाला से भोगपुर व कुंभ मेला क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे 48 स्टोन क्रशर को तत्काल बंद कराने व उनकी बिजली-पानी के कनेक्शन काटने के जिलाधिकारी और एसएसपी हरिद्वार को आदेश दिए हैं। न्यायाधीश रवींद्र मैठाणी व न्यायाधीश पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने अवैध खनन के विरुद्ध मातृ सदन आश्रम हरिद्वार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करने को कहा है। (जासं)

रेवन्ना के खिलाफ दुष्कर्म मामले में फैसला एक को

बेंगलुरु : बेंगलुरु स्थित सांसदों/विधायकों की विशेष अदालत ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते और पूर्व जेडी (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो और दुष्कर्म मामले में फैसला एक अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। अदालत ने कहा कि कुछ स्पष्टीकरणों की आवश्यकता के कारण फैसला टाला गया है। (आइएएनएस)

पुंछ में एलओसी पर घुसपैठ का बड़ा षड्यंत्र विफल, दो आंतकी ढेर

अभियान ▶ आपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से यह घुसपैठ की चौथी घटना

दो दिन पहले श्रीनगर के दाचीगाम में भी मारे गए थे तीन पाकिस्तानी आतंकी

जागरण संवाददाता, पुंछ

जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर मारे गए आतंकियों से बरामद हथियार व अन्य सामान। पुलिस

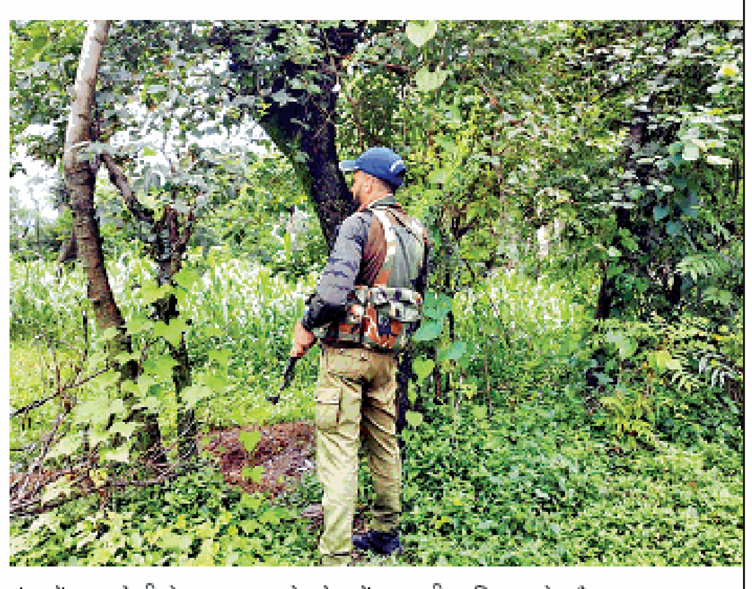

पुंछ में एलओसी के आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बल के जवान। पुलिस

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से की जा रही आतंकी घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को सतर्क सुरक्षाबलों ने नाकाम करते हुए दो आतंकियों को मार गिराया। उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और अन्य साजो-सामान बरामद किया गया। मंगलवार मध्य रात्रि को इस घटना के बाद बुधवार सुबह सेना, पुलिस के एसओजी के दल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने नियंत्रण रेखा के साथ सटे क्षेत्रों की घेराबंदी कर बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चला रखा है।

सैन्य अधिकारियों के अनुसार, गुलपुर सेक्टर के कोसलिया क्षेत्र में दो से तीन आतंकियों का एक दल नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की फिराक में था। जैसे ही घुसपैठियों ने नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र में कदम रखा तो पहले से सतर्क सुरक्षाबलों के जवानों ने उन्हें ललकारते हुए आत्मसमर्पण करने को कहा। इस पर घुसपैठियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और वापस पाकिस्तान की तरफ भागने की कोशिश की। भारतीय सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दो घुसपैठियों को मार गिराया और एक अन्य के घायल होने की आशंका है। इसी को लेकर सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा के नजदीक घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया।

बता दें कि आपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से राजौरी व पुंछ जिला में एलओसी पर यह घुसपैठ के प्रयास की चौथी घटना है। सुरक्षाबल ने गत सोमवार को श्रीनगर के दाचीगाम में भी एक मुठभेड़ में पहलगाम हमले के गुनाहगार तीन पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया था।

बाबा बुड्ढा अमरनाथ यात्रा के चलते बढ़ाई गई सतर्कता

इस समय पुंछ में बाबा बुड्ढा अमरनाथ यात्रा चल रही है, जिसमें देशभर से श्रद्धालु भाग लेने आ रहे हैं। इस घटना के बाद नियंत्रण रेखा से लेकर पुंछ नगर तक और सतर्कता बढ़ा दी गई है, ताकि दुश्मन देश या आतंकी संगठन यात्रा में किसी प्रकार का खलल न डाल सकें।

आतंकियों से बरामद हथियार

सुरक्षा बलों ने आतंकियों से दो असाल्ट राइफलें, गोलियों सहित एक पिस्तौल, हथगोले, दो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, भारी मात्रा में गोला-बारूद, संचार उपकरण, दवाइयों के अलावा खाने-पीने का सामान भी बरामद किया।

अलकायदा माड्यूल की सरगना गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, जागरण ● अहमदाबाद

- बेंगलुरु से हुई शमा परवीन की गिरफ्तारी, इंटरनेट मीडिया के जरिये युवाओं को देश विरोधी गतिविधियों के लिए उकसाती थी

गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते ने एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार आतंकी नेटवर्क से जुड़कर भारत विरोधी साजिश रचने वाले आतंकियों को दबोचा है। एटीएस ने बेंगलुरु से महिला आतंकी शमा परवीन अंसारी को पकड़ा है। शमा अलकायदा इन इंडियन सबकांटिनेंट की सरगना बताई जाती है जो इंटरनेट मीडिया के जरिये युवाओं को देश विरोधी गतिविधियों के लिए उकसाती थी। वह पाकिस्तानी संस्थाओं के साथ फोन और ईमेल के माध्यम से संपर्क में थी। वह इंटरनेट मीडिया पर जिहाद के लिए भड़काऊ सामग्री साझा करती थी ताकि देश में अशांति फैलाई जा सके।

एटीएस के आइजी सुनील जोशी के अनुसार, शमा को भारत में युवाओं को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसने अलकायदा आतंकी मौलाना असीम उमर और मारे गए अलकायदा आतंकी अनवर अल-अव्लाकी के भड़काऊ भाषण भी प्रसारित किए थे। एटीएस के अनुसार, अंसारी ने लाहौर की लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज का एक वीडियो भी पोस्ट किया था, जिसमें उन्हें भारत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मुसलमानों को उकसाते हुए देखा गया। आतंकी माड्यूल से जुड़े अन्य युवकों के बारे में शमा से पूछताछ जारी है। शमा को 29 जुलाई को पकड़ा गया जबकि इससे पहले 23 जुलाई को एटीएस ने नोएडा, दिल्ली, अहमदाबाद और गुजरात के मोडासा से आतंकी समूह से जुड़े एक-एक युवक को पकड़ा था। ये चारों युवक जिहादी प्रचार करने समेत भड़काऊ सामग्री प्रसारित कर रहे थे।

शुरू से ही कट्टर सोच की रही है शमा : शमा मूल रूप से झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित झुमरीतिलैया के हसनाबाद की रहने वाली है। उसके पिता शमशुल हक की 2019 में मौत के बाद परिवार बेंगलुरु में शिफ्ट हो गया था। कोडरमा के उसके घर में किरायेदार रहते हैं।

शमा के पड़ोसियों के अनुसार वह शुरू से ही कट्टर सोच की रही है। वह हमेशा बुर्के में रहती थी और कट्टर इस्लामिक सोच से प्रेरित बातें करती थी। वह आतंकियों के संपर्क में कैसे आई, इस संबंध में पड़ोसियों को कोई जानकारी नहीं है।

पटना हाई कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने में प्रशासनिक लापरवाही पर जताई नाराजगी

विधि संवाददाता, जागरण ● पटना: पटना हाई कोर्ट ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में सरकारी जमीनों पर जारी अतिक्रमण को हटाने में प्रशासनिक लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। न्यायाधीश पीबी बजनथ्री की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए पटना के जिलाधिकारी को अतिक्रमण हटाने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि तय समयावधि में कार्रवाई नहीं हुई, तो यह मामला केंद्र सरकार को सौंपा जा सकता है। यह आदेश डा. अमित कुमार सिंह द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। कोर्ट ने नाराजगी जताई कि पूर्व में अतिक्रमण हटाए जाने के बावजूद उन्हीं स्थानों पर फिर से कब्जा हो गया, जो दर्शाता है कि कार्रवाई प्रभावी ढंग से नहीं की गई।

2019 से जारी है मामला: यह मामला 2019 का है, जब हाई कोर्ट की पीठ ने पटना के कई क्षेत्रों में सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। डा. अमित कुमार सिंह ने 2018 में जिलाधिकारी को इस संबंध में एक विस्तृत आवेदन दिया था, जिसमें अतिक्रमण से जुड़े गंभीर सामाजिक और सुरक्षा संबंधी पहलुओं को उजागर किया गया था।

बिहार में दिनदहाड़े किशोरी को बाइक से किया अगवा, 18 घंटे बाद छुड़ाया

- अगवा होने के बाद सक्रिय हुई पुलिस, आरोपित गिरफ्तार, मामला दो समुदायों का होने से तनाव

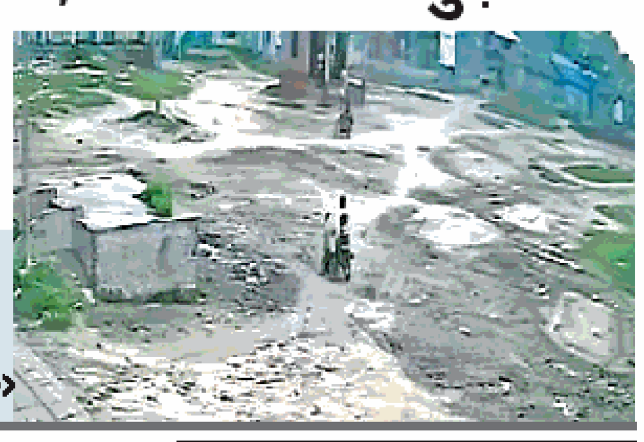

बिहार के दरभंगा जिले में किशोरी को बाइक पर जबरन बैठाता आरोपित। सीसीटीवी फुटेज »

जासं, अलीनगर (दरभंगा)

बिहार के दरभंगा में 15 वर्षीय एक किशोरी का दिनदहाड़े अपहरण कर लिया गया। घटना में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दो दिन पहले आरोपित ने पीड़िता के घर पर हमला कर अगवा करने की धमकी दी थी। शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामला दो समुदायों से जुड़ा है।

बताया गया कि मंगलवार की शाम लगभग पांच बजे किशोरी अपने पिता की पान दुकान से बहन के पुत्र के साथ घर लौट रही थी। इसी दौरान उसके गांव का हिजबुल रहमान उर्फ आरजू बाइक से पीछा करने लगा। रास्ते में एक जगह हिजबुल ने उसे घेर लिया और जबरन बाइक पर बिठाकर अगवा कर लिया। पीड़िता मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं आया। पूरी घटना सीसी कैमरे में कैद हो गई। किशोरी को अगवा किए जाने की सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। 18 घंटे बाद बुधवार को आरोपित को गिरफ्तार कर किशोरी को मुक्त कराया।

पिस्टल दिखाकर की थी मारपीट

पीड़िता के पिता ने कहा कि रविवार को आरोपित ने पहले उनकी पान की दुकान को क्षतिग्रस्त किया और घर पर पथराव किया। आरोपित ने छोटी पुत्री को पिस्टल दिखाकर मारपीट की और अपहरण करने की धमकी दी। सोमवार को थाने में आवेदन दिया गया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

असम में 1,500 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी

गोलाघाट, प्रेट्र: असम के गोलाघाट जिले में लगभग 1,500 हेक्टेयर वन भूमि पर कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई के कारण लगभग 1500 परिवार प्रभावित होंगे और इनमें से अधिकतर मुस्लिम समुदाय से हैं।

सरुपथार उप-मंडल में असम-नगालैंड सीमा पर उरियमघाट में रेंगमा वन अभयारण्य की 3,600 एकड़ से अधिक भूमि पर अतिक्रमण को हटाने के लिए मंगलवार सुबह बेदखली अभियान शुरू किया गया था। जिला प्रशासन के ने बताया कि बुधवार सुबह करीब नौ बजे सोनारी बील और पीठाघाट इलाके में बेदखली अभियान शुरू हुआ। अब तक सब कुछ योजना के अनुसार और शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। वहीं, वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वीकार किया कि वहां पीएम आवास योजना के तहत मकान थे और जल जीवन मिशन के तहत पानी का कनेक्शन था। इन क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उप-स्वास्थ्य केंद्र और लगभग हर घर में बिजली कनेक्शन के अलावा बाजार, मस्जिद, मदरसे और चर्च भी हैं।

श्रद्धा का महासावन

पुण्य कमाने का एक श्रेष्ठ अवसर है सावन

सावन सनातनी परंपरा में विशेष महत्व रखता है। यह महीना भगवान शिव की भक्ति को समर्पित है। यह समय वर्षाऋतु का होता है, जब प्रकृति अपने पूर्ण सौंदर्य में होती है। हरियाली, शीतल वातावरण और शुद्ध हवा मानव मन को आनंदित करती है। इस माह में श्रद्धालु शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, दूध आदि अर्पित कर उनका पूजन करते हैं। सोमवार का व्रत विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन पुण्य कमाने का एक श्रेष्ठ अवसर है। इस महीने किया गया दान सौगुना फल देने वाला माना गया है। शिवपुराण एवं स्कंदपुराण में उल्लेख है कि सावन में अन्नदान से समस्त पापों का नाश होता है और शिवकृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि सावन में दिया गया दान सीधे शिव को अर्पित होता है। यह दान न केवल सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। सावन में धार्मिक आयोजन, भजन-कीर्तन और मेलों का आयोजन होता है। यह परंपरा सामाजिक एकता और धार्मिक आस्था को प्रबल करती है। सावन का महीना महिलाओं के लिए भी खास होता है। वे हरी चूड़ियां पहनती हैं, हाथों में मेंहदी लगाती हैं और तीज-रक्षाबंधन जैसे त्योहार मनाती हैं। यह समय प्रेम, सौंदर्य और उत्सव का प्रतीक बन जाता है। इस प्रकार सावन का महीना न केवल धार्मिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह महीना आत्मिक शांति, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति प्रेम का संदेश देता है।

स्वामी रामेश्वर गिरि
महंत, श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर, ऋषिकेश

भोपाल में ड्रग्स तस्कर गिरोह से जुड़ी 100 करोड़ की संपत्तियों पर चला बुलडोजर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल

- हिंदू युवतियों को नशे का आदी बना दुष्कर्म के सुनियोजित अपराध में शामिल थे आरोपित
- आरोपितों के फार्म हाउस, वेयरहाउस और अवैध मदरसा ध्वस्त, 10 करोड़ का मकान भी सील

भोपाल में ड्रग्स तस्करी के आरोपित के कोकता स्थित अवैध ठिकानों को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ढहाया गया। नईदुनिया

भोपाल में क्लब और पबों के माध्यम से ड्रग तस्करी कर हिंदू युवतियों को नशे का आदी बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। गिरोह से जुड़े आरोपितों की लगभग 100 करोड़ रुपये की संपत्तियों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया है। इनमें फार्म हाउस, वेयरहाउस और अवैध मदरसा शामिल हैं। इसके साथ ही एक तीन मंजिला मकान को सील किया गया है।

अनंतपुरा कोकता क्षेत्र में 200 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में 15 बुलडोजर लगाकर प्रशासन ने करीब 50 एकड़ में बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। अधिकारियों का कहना है कि ये निर्माण सरकारी जमीन पर बिना अनुमति किए गए थे।

इन संपत्तियों का संबंध ड्रग तस्करी और हिंदू युवतियों से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार ड्रग माफिया शाहवर अहमद और उसके भतीजे यासीन से है। जिन अन्य आरोपितों की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है, उनमें शारिक मछली का नाम भी शामिल है, जो अप्रैल में सामने आए दुष्कर्म-ब्लैकमेलिंग के संगठित गिरोह से जुड़ा था, हालांकि पुलिस ने आरोपपत्र में उसका नाम शामिल नहीं किया।

एसडीएम विनोद सोनकिया ने कहा कि गुरुवार को भी आरोपितों के ठिकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी।

राहुल गांधी के निर्देश पर बच्चों को पढ़ाई के लिए दी गई राहत राशि

जागरण संवाददाता, पुंछ : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के निर्देश पर यूथ कांग्रेस ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिला में आपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलाबारी में अपने माता-पिता को खोने वाले 30 बच्चों को पढ़ाई के लिए 40-40 हजार रुपये के चेक प्रदान किए। कुल 12 लाख की राशि दी गई। राहुल ने 12वीं कक्षा तक इन सभी बच्चों की शिक्षा के खर्च का जिम्मा उठाया है। प्रत्येक दो वर्ष बाद इन बच्चों को राहत राशि दी जाएगी। पुंछ के डाक बंगला में यूथ कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रधान उदय भानु चिब व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद करा ने चेक प्रदान किए। इस मौके के प्रभावित परिवारों के सदस्य व अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे।

****

जालंधर सिविल अस्पताल मामले में एक डाक्टर बर्खास्त, तीन निलंबित

राज्य ब्यूरो, जागरण ● चंडीगढ़

- आक्सीजन प्लांट बंद होने से आइसीयू में भर्ती तीन मरीजों की हो गई थी मृत्यु
- स्वास्थ्य मंत्री बोले- जांच जारी, दोषी मिले तो निलंबित डाक्टर होंगे बर्खास्त

जालंधर के सिविल अस्पताल में रविवार रात आक्सीजन प्लांट बंद होने के कारण ट्रामा सेंटर के आइसीयू में भर्ती तीन मरीजों की मृत्यु की घटना पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। एक डाक्टर को बर्खास्त किया गया है और तीन अन्य डाक्टरों को निलंबित किया गया है। यह निर्णय विभाग के डायरेक्टर की अगुआई में गठित तीन सदस्यीय कमेटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डा. बलबीर सिंह ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और यदि निलंबित डाक्टरों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, तो उन्हें भी बर्खास्त किया जा सकता है। बर्खास्त डाक्टर शविंदर सिंह हाउस सर्जन थे। उनकी आइसीयू में ड्यूटी थी। निलंबित डाक्टरों में एमएस डा. राज कुमार, एसएमओ डा. सुरजीत सिंह और कन्सल्टिंग एनेस्थीसिया डा. सोनाक्षी शामिल हैं। डा. बलबीर सिंह ने स्वीकार किया कि समस्या स्थानीय प्रशासन की है।

उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि आक्सीजन प्लांट के इंजीनियर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। कहा कि आक्सीजन प्लांट को चलाने के लिए आइसीयू में कार्यरत सभी स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाता है। आपातकालीन स्थितियों में वैकल्पिक प्रबंध करना आवश्यक है, ताकि ऐसी घटनाएं न हों।

ननों को नहीं मिली जमानत, विशेष न्यायालय में करना होगा आवेदन

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग: छत्तीसगढ़ में मतांतरण और मानव तस्करी में दुर्ग स्थित केंद्रीय जेल में बंद नन प्रीति मेरी, वंदना फ्रांसिस और पास्टर सुखमन मंडावी को जमानत नहीं मिल सकी है। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश अनीष दुबे ने कहा कि यह मामला उनके श्रवण क्षेत्राधिकार में नहीं आता। आरोपितों को अब बिलासपुर में एनआइए के विशेष न्यायालय में आवेदन देना होगा। उधर, जमानत के लिए आवेदन करने की जानकारी मिलने पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य न्यायालय परिसर में बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए थे, जिसके चलते पुलिस बल तैनात किया गया। तीनों आरोपितों को 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था, जब वे तीन आदिवासी युवतियों को मतांतरण के लिए नौकरी का प्रलोभन देकर आगरा ले जा रहे थे।

डाक्टरों पर दबाव डालने के लिए बांबे हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार

- गर्भपात की इच्छुक लड़कियों की पहचान उजागर करने को बनाते थे दबाव
- कहा- यह दबाव लड़कियों व डाक्टरों का उत्पीड़न के अलावा और कुछ नहीं

मुंबई, प्रेट्र : बांबे हाईकोर्ट ने गर्भपात कराने की इच्छुक नाबालिग लड़कियों की पहचान उजागर करने के लिए डाक्टरों पर दबाव डालने पर पुलिस को फटकार लगाई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इस पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने 28 जुलाई को कहा कि पुलिस का यह दबाव ''लड़कियों और डाक्टरों का उत्पीड़न'' के अलावा और कुछ नहीं है।

नियमों के अनुसार, जब 18 साल से कम उम्र की कोई लड़की गर्भपात के लिए डाक्टर के पास जाती है, तो डाक्टर को पुलिस को सूचित करना होता है। मुंबई की एक स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा दायर याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि ऐसे ही एक मामले में उन्हें पुलिस को लड़की का नाम बताने के लिए मजबूर न किया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि लड़की ने एक लड़के के साथ सहमति से यौन संबंध बनाए थे। वह और उसके माता-पिता उसके 13 सप्ताह के गर्भ को गिराना चाहते थे, लेकिन उसके भविष्य को देखते हुए पुलिस को उसका नाम नहीं बताना चाहते थे। याची ने 2022 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि किसी भी आपराधिक कार्यवाही में किसी चिकित्सक को नाबालिग की पहचान और अन्य व्यक्तिगत विवरण बताने की आवश्यकता नहीं है।

बहरहाल, कोर्ट ने स्त्री रोग विशेषज्ञ को लड़की का नाम बताए बिना गर्भपात करने की अनुमति दे दी। जजों ने कहा कि यह ''काफी आश्चर्यजनक'' है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद डाक्टरों को अनुमति के लिए हाईकोर्ट का रुख करने को मजबूर होना पड़ा क्योंकि पुलिस ने ऐसे मामलों में नाबालिग पीड़ितों की पहचान उजागर करने पर जोर दिया।

निमिषा प्रिया की मौत की सजा को पलटने का दावा गलत

नई दिल्ली, प्रेट्र : यमन में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय निमिषा प्रिया के मामले में केरल के एक मौलवी द्वारा किए जा रहे दावे गलत हैं। सरकारी सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। साथ ही कहा कि इस संवेदनशील मामले पर किसी भी तरह की अटकलबाजी से बचना चाहिए। सदर मुफ्ती कंथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार ने सोमवार को दावा किया था कि प्रिया की मौत की सजा को पलट दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि उन्होंने प्रिया के मामले से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं और ये दावे गलत हैं। सूत्र ने कहा, ''हम लोगों से इस संवेदनशील मामले पर गलत सूचना और अटकलों से बचने का आग्रह करते हैं।'' स्पष्टीकरण तब आया जब सदर मुफ्ती ने कथित तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय प्रिया मामले में उनके प्रयासों से अवगत हैं। 38 वर्षीय निमिषा की फांसी 16 जुलाई को होनी थी, लेकिन भारतीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद इसे टाल दिया गया।

जब हम वेदों की रक्षा करेंगे तो वेद भी हमारी रक्षा करेंगे : जज

- मद्रास हाईकोर्ट के जज ने एक घटना और उससे जुड़े अदालती मामले का जिक्र किया
- एक हादसे में उनके 'वैदिक विद्वान मित्र को दोषी ठहराया गया था एवं 18 माह जेल की सजा सुनाई गई थी

चेन्नई, प्रेट्र : मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने कहा है कि जब वेदों की रक्षा की जाती है तो वे उन लोगों की भी रक्षा करेंगे जो उनका संरक्षण एवं आत्मसात करते हैं। एक अदालती फैसले ने उन्हें यह अहसास दिलाया है। उन्होंने एक घटना और उससे जुड़े एक अदालती मामले का जिक्र किया जिसने उनके नजरिए को बदल दिया। उन्होंने कहा कि वाहन दुर्घटना मामले में एक वैदिक विद्वान 'शास्त्री' को दोषी ठहराया गया और 18 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

जज ने पिछले हफ्ते यहां एक ट्रस्ट द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वैदिक प्रतिभा सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस घटना का जिक्र किया। उनके संबोधन का एक वीडियो क्लिप अब इंटरनेट मीडिया पर वायरल है।

जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि 'शास्त्री' (शास्त्रों और वेदों का पारंगत, एक वैदिक ब्राह्मण) मेरे लंबे समय के मित्र थे और उस समय मैं एक वकील था। उन्होंने अतीत की घटना का स्मरण करते हुए कहा कि एक दिन शास्त्री अपने एक अन्य मित्र के साथ मुझसे मिलने आए और जब मुझे बताया गया कि शास्त्री को दोषी ठहराया गया है और उन्हें जेल की सजा सुनाई गई है तो मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ।

मद्रास हाईकोर्ट। फाइल

जज ने बताया कि शास्त्री की बहन अमेरिका से भारत आई थीं। अपने बच्चों और भाई के साथ वह मंदिरों में दर्शन करने गईं और कार भी खुद ही चला रही थीं। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या हुआ। कार ने चाय की दुकान के सामने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। शास्त्री की बहन को अमेरिका जाना था, इसलिए शास्त्री ने लापरवाही से कार चलाने का दावा किया और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मामले में मुकदमा चला और शास्त्री को 18 महीने जेल की सजा सुनाई गई।

मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने कहा कि ऐसे मामलों में छह महीने की जेल की सजा आम बात है। शास्त्री पूरी पारंपरिक पोशाक (धोती और ऊपरी वस्त्र के अलावा एक कलगीदार वस्त्र) पहनकर कोर्ट जाते थे। शास्त्री ने उन्हें बताया कि इसी पोशाक के कारण उन्हें 18 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। जब उन्होंने मामले के दस्तावेज देखे तो पाया कि एक भी गवाह ने गाड़ी चलाने वाले की पहचान नहीं की थी। इसके अलावा, कोर्ट में किसी ने भी शास्त्री की पहचान नहीं की। उनके खिलाफ कोई गवाह नहीं था।

जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि उन्होंने उस मामले को इसलिए उठाया क्योंकि उस समय वह एक पेशेवर वकील थे और उन्होंने अपील की थी। जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा, "हमने इस एक बिंदु को उठाया और अपील कोर्ट में बहस की।"

जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने आगे कहा कि यह शास्त्री का सौभाग्य था कि अपील की सुनवाई करने वाला जज उनका सहपाठी था। अंततः शास्त्री को बरी कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सुबूत नहीं था। "उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जब हम वेदों की रक्षा करेंगे, तो वेद हमारी रक्षा करेंगे और मुझे यह एहसास हुआ। उस समय तक, मुझे ऐसे मामलों में गहरी दिलचस्पी नहीं थी। सोचिए, कम से कम एक गवाह तो यह कह सकता था कि शास्त्री जी कार चला रहे थे। एक ने भी ऐसा नहीं कहा। सभी आठ गवाहों ने कहा कि कार अनियंत्रित हो गई थी और टक्कर लगने से उस व्यक्ति की मौत हो गई।"

मुरादाबाद में बुलडोजर कार्रवाई से आहत भाजपा मंडल उपाध्यक्ष के भाई ने दी जान

मौत से पहले फेसबुक पर किया पोस्ट- मंडी के अंदर प्रशासन का आक्रमण, बर्बादी का जिम्मेदार कौन?

पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे उप मुख्यमंत्री पाठक बोले- मुरादाबाद में अफसरों की मनमानी बर्दाश्त नहीं

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद

मुरादाबाद में मंडी समिति में सचिव संजीव कुमार की पिटाई के अगले दिन प्रशासन ने मंडी परिसर में बुलडोजर से अतिक्रमण हटवा दिया। आढ़त पर बुलडोजर कार्रवाई से आहत भाजपा मंडल उपाध्यक्ष विजेंद्र सैनी के बड़े भाई चेतन सैनी अवसाद में चले गए और पत्नी से हाथ छुड़ाकर मकान की पहली मंजिल से कूदकर जान दे दी। इससे पहले उन्होंने फेसबुक अकाउंट पर कार्रवाई का वीडियो पोस्ट कर प्रशासन पर सवाल खड़े किए। बुधवार को शहर में आए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सीधे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। विजेंद्र सैनी ने मंडी सचिव के निलंबन, बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद एडीएम सिटी ज्योति सिंह, एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह और एसडीएम के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। उप मुख्यमंत्री ने पीड़ित को सांत्वना देते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। इस मामले में कड़ी कार्रवाई नजीर बनेगी। मुरादाबाद में अफसरों की मनमानी है। यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। पोस्टमार्टम में मौत की वजह सिर में चोट बताई गई है। एसएसपी सतपाल अंतिल का कहना है कि शिकायती पत्र मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर चेतन सैनी (इनसेट) के स्वजन से घटना की जानकारी करते उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक (दाएं)। जागरण

> दुख की इस घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। इस दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए दोषी किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। -बृजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री

> मरने वाले व्यक्ति के नाम कोई मंडी लाइसेंस नहीं है और न ही उनके द्वारा कोई फड़ लगाया जाता था। कुछ लोग इसे मंडी में हटाए गए अतिक्रमण से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तविकता जांच में ही स्पष्ट होगी। मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट, आडियो-वीडियो बरामद नहीं हुआ है। -अनुज सिंह, डीएम, मुरादाबाद

मंडी समिति मझोला में हुकुम सिंह एंड कंपनी और उमेश एंड ब्रादर्स नाम से फल की दो आढ़तें हैं। दोनों आढ़तों को हुकुम सिंह और उनके बेटे चेतन सैनी, विजेंद्र सैनी, उमेश और नीरज संचालित करते हैं। मंडी सचिव की पिटाई के बाद मंगलवार को मंडी परिसर में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया। हुकुम सिंह की दोनों आढ़तों पर भी कार्रवाई हुई। विजेंद्र का कहना है कि टीम से सामान हटाने के लिए 10 मिनट का समय मांगा, लेकिन नहीं दिया गया। प्रशासनिक तानाशाही दिखाते हुए बुलडोजर चला दिया गया। करीब आठ लाख रुपये के फल और अन्य सामान बर्बाद हो गया। शाम को चेतन ने कहा कि सबकुछ बर्बाद हो गया। मैं तो आत्महत्या करुंगा। परिवार ने समझाया, मगर भाई पूरी तरह से टूट चुके थे। रात करीब 11 बजे वह, पत्नी चंचल, बेटी आरोही और बेटे अभी छत पर थे। चंचल ने उनका हाथ पकड़ रखा था। वह कुछ समझ पातीं कि हाथ छिटक कर चेतन ने छलांग लगा दी। मौत से पहले उन्होंने फेसबुक पर कार्रवाई का वीडियो अपलोड कर पोस्ट भी की।

केमिस्ट्री की दलीलें काम न आईं, महिला प्रोफेसर की सजा बरकरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अपने बचाव में वैज्ञानिक विश्लेषण के जरिए ध्यान खींचने वाली केमिस्ट्री की प्रोफेसर ममता पाठक की दलीलें काम नहीं आईं। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल व न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की युगलपीठ ने उनकी उम्रकैद बरकरार रखी। उन्हें उनके पति डा. नीरज पाठक की करंट देकर हत्या करने का दोषी पाया गया है।

वर्ष 2021 में ग्वालियर में सेवानिवृत्त डा. नीरज की रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो गई थी। पत्नी ममता ने बताया था कि वह बेटे के साथ झांसी गई थीं और लौटने पर पति मृत मिले।

पुलिस जांच में सामने आया कि ममता ने पति को पहले नींद की गोलियां दीं और फिर करंट लगाकर मार डाला। ड्राइवर के बयान, नीरज की एक आडियो क्लिप, जिसमें वह कह रहे हैं कि पत्नी प्रताड़ित करती हैं, और ममता की एक पुरानी शिकायत ने इस केस को मजबूत बना दिया। 2022 में सेशन कोर्ट ने ममता को हत्या का दोषी मानते उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

29 अप्रैल को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने मंगलवार को फैसले में ममता की उम्रकैद की सजा बरकरार रखते शेष कारावास भुगतने के लिए तत्काल ट्रायल कोर्ट में सरेंडर का निर्देश दिया।

'तीसरे बच्चे की मां बनने वाली महिला भी मातृत्व अवकाश की हकदार'

जागरण संवाददाता, शिमला

- कोर्ट ने कहा, दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व खत्म नहीं हो जाता
- सरकार को तुरंत प्रभाव से प्रार्थी को मातृत्व अवकाश देने के दिए आदेश

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मातृत्व अवकाश से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा है कि नियुक्ति पाने के बाद तीसरे बच्चे की मां बनने वाली महिला कर्मचारी भी मातृत्व अवकाश पाने की हकदार है। प्रार्थी के नौकरी पाने से पहले दो बच्चे पैदा हुए थे और तीसरे बच्चे का जन्म नौकरी पाने के बाद हुआ। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने मातृत्व अवकाश को लेकर स्टाफ नर्स अर्चना शर्मा द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए सरकार को आदेश दिया कि वह तुरंत प्रभाव से प्रार्थी को मातृत्व अवकाश प्रदान करे।

प्रार्थी सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में स्टाफ नर्स है। पांच मार्च 2025 को उसने एक बच्चे को जन्म दिया और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल को छह मार्च से मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता की शिकायत थी कि आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिस कारण उसे याचिका दायर करनी पड़ी।

पहली याचिका में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ने सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता के आवेदन पर एक सप्ताह के भीतर विचार करें और निर्णय लें। इसके बावजूद सक्षम अधिकारी ने कोई निर्णय नहीं लिया तो प्रार्थी ने एक और याचिका दायर की।

इस याचिका के लंबित रहते सरकार की ओर से कहा गया कि प्रार्थी मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार नहीं रखती क्योंकि यह दंपती का तीसरा बच्चा है और नियमों के तहत मातृत्व अवकाश केवल दो बच्चों तक के लिए ही है। इस कारण प्रार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया गया।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ने कहा कि दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व खत्म नहीं हो जाता। इन परिस्थितियों में एक महिला के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। केवल इस आधार पर कि महिला ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया है, एक नवजात बच्चे को दूसरों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता।

सेना प्रमुख ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की

इंफाल, प्रेट्र: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बुधवार को मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य में तैनात असम राइफल्स और सेना के गठन की वर्तमान सुरक्षा स्थिति और परिचालन तत्परता की समीक्षा की। सेना प्रमुख ने मणिपुर के राज्यपाल से भी शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान जनरल द्विवेदी ने इंफाल के खुमान लंपक स्टेडियम में डूरंड कप के ट्राउ एफसी बनाम नेरोका एफसी मैच में शामिल हुए।

जनरल द्विवेदी को मणिपुर में जमीनी हालात और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चल रही पहलों के बारे में भी जानकारी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परिचालन तैयारियों का आकलन करने तथा सैन्य-नागरिक सहयोग बढ़ाने के लिए मणिपुर का दौरा किया। जनरल द्विवेदी ने मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से भी शिष्टाचार भेंट की और सुरक्षा और विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। राजभवन ने बयान में कहा कि राज्यपाल ने आपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन पर सेना को हार्दिक बधाई दी।

आंध्र के शराब घोटाले में एसआइटी ने जब्त किए 11 करोड़ रुपये

- वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार के दौरान हुआ था शराब घोटाला
- मुख्य आरोपित केसी रेड्डी राजशेखर रेड्डी के निर्देश छुपाई गई थी नकदी

अमरावती, प्रेट्र: आंध्र प्रदेश में 3,500 करोड़ रुपये के शराब घोटाले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने हैदराबाद के पास एक फार्महाउस से बुधवार को 11 करोड़ रुपये नकद जब्त किए। ये रुपये रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद मंडल के कचराम स्थित सुलोचना फार्म गेस्टहाउस में 12 गत्ते के डिब्बों में रखे गए थे। एसआइटी ने घोटाले के आरोपितों के घरों और कार्यालयों की तलाशी के दौरान यह नकदी जब्त की। यह घोटाला कथित तौर पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार के दौरान 2018 से 2024 के बीच हुआ था।

सूत्र ने बताया कि आरोपित वरुण पुरुषोत्तम ने इस घोटाले में अपनी भूमिका स्वीकार की और महत्वपूर्ण जानकारी उजागर की। पुरुषोत्तम की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसआइटी ने छापेमारी की और नकदी जब्त किए। एसआइटी सूत्रों ने कहा कि मामले के मुख्य आरोपित केसी रेड्डी राजशेखर रेड्डी के निर्देश पर नकदी और शराब छुपाई गई थी। सूत्र ने बताया कि यह हजारों करोड़ रुपये का घोटाला है और इसमें मुखौटा कंपनियां बनाने, रिश्वतखोरी और राजनीतिक संरक्षण के पहलू शामिल हैं। एक अन्य सूत्र ने बताया कि टीम हाल में की गई छापेमारी के दौरान उजागर हुए वित्तीय लेनदेन और राजनीतिक संबंधों पर बारीकी से नजर रख रही है, जिससे इस मामले में जल्द ही और गिरफ्तारियां और जब्ती होने की संभावना है। पुलिस के अनुसार, यह शराब घोटाला युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) की पिछली सरकार के दौरान 2018 से 2024 के बीच हुआ था।

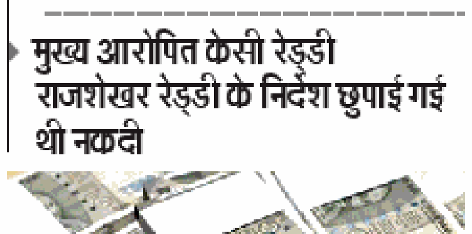

प्रतीकात्मक

सेंथिल से जुड़े मुकदमे के लिए चाहिए होगा क्रिकेट स्टेडियम : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी से जुड़े नौकरी के बदले नकदी घोटाले में 2,000 से ज्यादा को आरोपित बनाने के लिए प्रदेश सरकार की खिंचाई की और उनसे पूछा कि वे पीड़ित हैं या उत्पीड़नकारी। कोर्ट ने कहा कि इस केस की सुनवाई के लिए एक क्रिकेट स्टेडियम की आवश्यकता होगी। मुकदमे को ''बिना पतवार वाला जहाज'' करार देते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होता तो राज्य सरकार सेंथिल बालाजी से जुड़े मामलों को गरिमापूर्ण ढंग से समाप्त कर देती। पीठ ने घोटाले के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रहे और मामलों को एक साथ जोड़ने के फैसले का विरोध कर रहे वाई. बालाजी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन से कहा, ''2,000 से अधिक आरोपितों और 500 गवाहों वाला यह देश का सबसे ज्यादा भीड़-भाड़ वाला मुकदमा होगा। निचली अदालत का एक छोटा कक्ष काफी नहीं होगा। आरोपितों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भी क्रिकेट स्टेडियम की जरूरत पड़ेगी। एआइ से संचालित कई आरोपित उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अचानक सामने आ जाएंगे।''

साइबर ठगों ने सात राज्यों के 35 खातों में ठगी कर उगाहे 150 करोड़

राज्य ब्यूरो, जागरण • अहमदाबाद

- कंबोडिया में बैठकर गिरोह के सरगना इस ठगी के नेटवर्क को कर रहे संचालित
- इस गिरोह के तार राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली से भी जुड़े

गुजरात साइबर सेल ने गत सप्ताह गांधीनगर की एक 78 वर्षीय महिला डाक्टर को तीन माह तक डिजिटल अरेस्ट कर 19 करोड़ 24 लाख रुपये ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था। पुलिस का दावा है कि इस अंतरराष्ट्रीय गिरोह ने सात राज्यों के 35 खातों में आनलाइन ठगी कर करीब 150 करोड़ रुपये जमा किए हैं।

महिला डाक्टर को डिजीटल अरेस्ट कर करोड़ों रुपये ठगने के मामले में गुजरात साइबर सेल के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र शर्मा ने एक टीम बनाकर गहनता से मामले की जांच कराई तो पता चला कि इस गिरोह के तार राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली आदि राज्यों से जुड़े हैं। भारत के बाहर कंबोडिया में बैठकर गिरोह के सरगना इस साइबर ठगी के नेटवर्क को संचालित कर रहे हैं। महिला डाक्टर से ठगी के मामले की जांच के बाद पुलिस ने सूरत के एक हीरा कारीगर लालजी भाई की धरपकड़ की थी। उसके खाते में साइबर ठगों ने करीब एक करोड़ रुपये ट्रांसफर कराए थे। पूछताछ में उसने बताया कि ठगों ने उसे नोएडा बुलाकर एक होटल में बंधक बना लिया था। वहीं पर इन साइबर ठगों ने उसके खाते से अलग-अलग खातों में रुपये ट्रांसफर कराए।

गुजरात साइबर सेल को इस गिरोह की आनलाइन ठगी के शिकार लोगों की ओर से करीब सौ शिकायतें मिली हैं। साइबर ठगी का यह मामला अब 150 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। साइबर सेल मामले की जांच के लिए कंबोडिया तथा अन्य राज्यों की पुलिस से संपर्क साध रही है।

केरल के कोर्ट ने मानव तस्करी में दो नन समेत पांच को बरी किया

त्रिशूर, प्रेट्र : केरल की एक अदालत ने घरेलू कार्य के लिए तीन लड़कियों की तस्करी के मामले में दो नन सहित पांच लोगों को बरी कर दिया। इनमें से तीन लोग झारखंड के हैं। अदालत ने कहा कि धमकी, जबरदस्ती या शोषण का कोई सुबूत नहीं मिला। सेशन कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल नहीं हुआ। आदेश में कहा गया कि इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि लड़कियों को किसी तरह की धमकी देकर ले जाया गया। अपहरण, धोखाधड़ी/छल, दुर्व्यवहार या शक्ति का इस्तेमाल करने का कोई मामला नहीं है। मुख्य आरोप यह है कि किसी प्रकार की जबरदस्ती या प्रलोभन दिया गया है। यह देखा जाना चाहिए कि किसी भी गवाह ने ऐसा नहीं कहा। लोगों का कहना है कि कोई राशि नहीं ली गई थी। इस आशय का कोई दावा भी नहीं है कि गुलामी या दासता जैसा कोई प्रयास किया गया है। रेलवे पुलिस ने 2022 में मामला दर्ज किया था, जिसमें पांचों पर एक साझा इरादे से लड़कियों को झारखंड से केरल विभिन्न कान्वेंट में घरेलू नौकरानी के रूप में काम करने के उद्देश्य से ले जाने का आरोप लगाया गया था।

असमंजस

विधानसभा चुनाव में मतों की गणना से असंतुष्ट कांग्रेस विधायक पहुंचे कोर्ट, चुनाव आयोग ने हाईस्कूल में बने स्ट्रांग रूम में रखी हैं ईवीएम

250 वोट का फेर, हाईस्कूल पर डेढ़ वर्ष से चुनाव आयोग का कब्जा

रविंद्र थाईवत • नईदुनिया

जशपुरनगर: विधानसभा चुनाव 2023 को डेढ़ साल से ज्यादा समय बीत चुका है लेकिन छत्तीसगढ़ में जशपुरनगर का शासकीय जवाहर लाल नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अब भी चुनाव आयोग के कब्जे में है। परिणामस्वरूप, 220 छात्र हास्टल में पढ़ने को मजबूर हैं, जहां ब्लैकबोर्ड तक नहीं है। इस समस्या की जड़ 2023 के चुनाव में पत्थलगांव सीट के नतीजों को लेकर हाईकोर्ट में दायर एक याचिका है जिसके कारण स्कूल परिसर में रखी ईवीएम डेढ़ साल से यहां बने स्ट्रांग रूम में बंद हैं। स्कूल की कक्षाएं लगने से छात्रावास में रहने वाले बच्चों को दूसरे छात्रावास में शिफ्ट किया गया है जहां क्षमता से दोगुना ज्यादा बच्चे हो गए हैं।

दरअसल, जशपुरनगर शहर के नजदीकी डोड़काचौरा गांव में संचालित शासकीय जवाहर लाल नेहरू उच्चतर माध्यमिक आवासीय विद्यालय को सितंबर 2023 में आयोग ने विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए अधिग्रहण किया था। यहां जिले की तीन विधानसभा जशपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव के मतों की गणना संपन्न हुई थी। घोषित परिणाम में पत्थलगांव विधानसभा में पेंच फंस गया। यहां से भाजपा की प्रत्याशी गोमती साय को 250 मतों से विजय घोषित किया गया था। परिणाम घोषित करने से पहले निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस प्रत्याशी रामपुकार सिंह ने निर्वाचन अधिकारी से पुर्नमतगणना का अनुरोध किया था लेकिन इसे स्वीकार न करते हुए चुनाव परिणाम घोषित कर दिया गया था। इससे असंतुष्ट रामपुकार सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुनाव परिणाम को चुनौती दी थी। इस याचिका के कारण स्कूल भवन में निर्मित अस्थायी स्ट्रांग रूम में बीते डेढ़ साल से ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रखा गया है। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ही इस स्कूल भवन को ताले से मुक्ति मिलने की बात शिक्षा विभाग के अधिकारी कह रहे हैं।

शासकीय जवाहर लाल नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अभी भी है चुनाव आयोग के कब्जे में। जागरण

> स्कूल भवन को रिलीज कराने के लिए कोशिश की जा रही है। याचिकाकर्ता से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया गया है। चुनाव के लिए स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र निर्माण के लिए प्रस्ताव चुनाव आयोग को प्रेषित किया जाएगा। - रोहित व्यास, कलेक्टर, जशपुर

2019 के आम चुनाव में भी बनी थी ऐसी ही स्थिति

इससे पहले 2019 के आम चुनाव में भी ऐसी स्थिति इस स्कूल के साथ बनी थी। उस समय भी विधानसभा चुनाव 2018 के स्ट्रांग रूम और मतगणना के लिए इसी स्कूल भवन का अधिग्रहण चुनाव आयोग ने किया था। विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया भी यहीं संपन्न हुई। लोकसभा चुनाव परिणाम को हाई कोर्ट में चुनौती दिए जाने से दो साल से अधिक समय तक यह स्कूल भवन ताले में कैद रहा था।

उत्पीड़न के आरोपित को हाई कोर्ट का जज बनाने पर महिला जज का इस्तीफा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर

- मप्र हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजे इस्तीफे में जताया क्षोभ
- लिखा, न्यायपालिका की चुप्पी के शिकार के रूप में ले रही हूं विदा

मध्य प्रदेश के शहडोल में कार्यरत महिला सिविल जज अदिति शर्मा ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र भेजा है। उन्होंने इस्तीफे में इस बात पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया है कि जिस व्यक्ति पर उन्होंने उत्पीड़न और कदाचार का आरोप लगाया था, उसे मप्र हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है।

अदिति शर्मा ने लिखा है कि वह न्यायिक सेवा से इस्तीफा दे रही हैं, यह दर्शाते हुए कि संस्थान ने उन्हें विफल किया है। उन्होंने एक वरिष्ठ न्यायाधीश के खिलाफ बोलने का साहस किया, जिसने वर्षों तक उनका उत्पीड़न किया। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि कम से कम उनकी शिकायत की सुनवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जिसने उनके दुख की साजिश रची, उसकी जांच नहीं की गई, बल्कि पुरस्कृत किया गया।

अदिति ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी तथ्यों के बावजूद कोई जांच नहीं हुई और न ही उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। उनका उद्देश्य बदला नहीं, बल्कि न्याय की मांग करना था। वह न्यायपालिका की चुप्पी के शिकार के रूप में विदा ले रही हैं। वह इस संस्था को बिना किसी पदक और उत्सव के छोड़ रही हैं, केवल इस कड़वे सच के साथ कि न्यायपालिका ने उन्हें निराश किया है।

गौरतलब है कि तत्कालीन जिला जज पर आरोप लगाए जाने के बाद शासन ने अदिति समेत छह जजों को प्रदर्शन संतोषजनक न होने के आरोप में बर्खास्त कर दिया था।

****

दैनिक जागरण
कल्पना ही विचार का आकार ग्रहण करती है

ट्रंप के आगे झुकना नहीं

आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की अपनी धमकी पर अमल कर दिया। उन्होंने भारत से अमेरिका आने वाली वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के साथ रूस से हथियार और तेल खरीदने पर जुर्माना लगाने की भी घोषणा की। उन्होंने यह सब इसलिए किया, क्योंकि व्यापार समझौते पर 1 अगस्त की समय सीमा तक दोनों देशों के बीच जारी बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचती नहीं दिख रही थी। ऐसा इसलिए था, क्योंकि भारत अमेरिका की शर्तों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं। उसे आगे भी तैयार नहीं होना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं कि भारत अमेरिका से ऐसा व्यापार समझौता कर ले, जो केवल उसके हित में हो। इस तरह के समझौते तो तभी हो पाते हैं, जब दोनों पक्षों के हित सधते हैं। भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए अडिग रहना चाहिए और यह स्पष्ट करने में संकोच भी नहीं करना चाहिए कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुचित दबाव के आगे झुकने वाला नहीं। भारत अपने हित की रक्षा करके ही अमेरिका फर्स्ट की ट्रंप की नीति का साथ दे सकता है। भारत को ट्रंप के मनमाने फैसलों से डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं, क्योंकि वे अपने फैसलों से पीछे हटने और उन्हें पलटने के लिए जाने जाते हैं। उनके इस रवैये के कारण उनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फजीहत भी हो रही है। उन्हें यह समझ आ जाए तो अच्छा कि आज का भारत पहले वाला भारत नहीं है और अमेरिका का भी प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा।

यह किसी से छिपा नहीं कि टैरिफ के मामले में ट्रंप पहले भी मुंह की खा चुके हैं। उन्होंने चीन से आने वाली वस्तुओं पर मनमाने तरीके से टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसके जवाब में चीन ने भी ऐसा ही किया। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका चीन से वार्ता करने के लिए बाध्य हुआ। यह ठीक है कि भारत की आर्थिक स्थिति चीन जैसी नहीं, लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के तथाकथित कठोर रवैये के आगे अपने हितों की बलि दे दे। इसे कोई भी समझ सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने और जुर्माना लगाने की जो घोषणा की, वह उनकी दबाव की राजनीति का ही हिस्सा है। इस राजनीति की पोल खुल चुकी है। अच्छा होगा कि इसे देश के विपक्षी दल भी समझें। इसलिए और भी समझें कि संसद में आपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि सैन्य कार्रवाई को स्थगित किए जाने के सिलसिले में विश्व के किसी भी नेता की कहीं कोई भूमिका नहीं। स्पष्ट है कि भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई को कथित तौर पर रोकने का ट्रंप का दावा फर्जी है। वास्तव में इसी कारण वे अपने इस थोथे दावे को बार-बार दोहरा रहे हैं।

संवेदनहीनता की पराकाष्ठा

डाक्टरी का पेशा बहुत सम्मान और भरोसे का है। सेवा भाव ही इसका ध्येय रहा है। अपने देश में डाक्टर बिधान चंद्र राय जैसे चिकित्सक थे जो मुख्यमंत्री बन जाने के बाद भी अपने चिकित्सकीय कर्तव्य का पालन करते नहीं थकते थे। इन्हें देश ने भारत रत्न से सम्मानित किया और इनकी जयंती चिकित्सक दिवस के रूप में मनाई जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मेरठ के मेडिकल कालेज अस्पताल में रविवार को जिस प्रकार की संवेदनहीनता का प्रदर्शन किया गया, वह निंदनीय है। अस्पताल तो सेवाश्रम है। किसी की जिंदगी बचाने जैसे पुण्य के भागीदार होने का अवसर तो डाक्टरों को ही मिलता है। दरअसल मेरठ मेडिकल कालेज अस्पताल में रविवार की रात सड़क हादसे में घायल युवक को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। उसका खून बहता रहा, पर तत्काल चिकित्सा की जगह ड्यूटी पर रहे डाक्टर घायल युवक की अनदेखी करते रहे, सोते रहे। डाक्टरों को जगाने का प्रयास हुआ तो वह अभद्रता पर उतर गए। ड्यूटी इंचार्ज भी मौके पर नहीं पाए गए। अब जब वहां के जिलाधिकारी की रिपोर्ट में अराजक व्यवस्था की बात सामने आ गई है तो और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यद्यपि जूनियर डाक्टरों का निलंबन हुआ है, परंतु अस्पताल प्रबंधन से जुड़े सीनियर चिकित्साधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अस्पताल पहुंचने के बाद भी इलाज न हो और जान चली जाए, यह तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। वैसे भी इस तरह की घटनाओं के बारे में अन्य जगहों से भी यदा-कदा खबरें आती रहती हैं, जिनमें अस्पताल की ओर से लापरवाही की बातें सामने आती हैं, लिहाजा व्यवस्था में बदलाव अपेक्षित है। ताकि समय रहते इलाज मिलने से घायल को बचाया जा सके।

> मेरठ मेडिकल कालेज अस्पताल में डाक्टरों ने जिस प्रकार के आचरण का प्रदर्शन किया, वह निंदनीय है

धार्मिक विरासत के नाम पर राजनीतिक लड़ाई

विवेक काटजू

थाइलैंड और कंबोडिया में भले ही संघर्ष विराम हो गया हो, लेकिन कहना कठिन है कि विवादित मामले का हमेशा के लिए पटाक्षेप हो जाएगा

थाइलैंड और कंबोडिया के बीच छिड़ी लड़ाई थम गई। अमेरिका और मलेशिया की मध्यस्थता से दोनों देशों में संघर्ष विराम पर सहमति बनी। संघर्ष विराम के लिए यह वार्ता आसियान की कमान संभाल रहे मलेशिया में हुई। इस वार्ता में मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और अमेरिकी एवं चीनी राजदूत की भी उपस्थिति रही, जिन्होंने थाइलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमतम वेचायाचाई और कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मानेत के बीच संधि कराई। हुन कंबोडियाई दिग्गज हुन सेन के बेटे हैं। इस बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी दोनों देशों पर लड़ाई बंद करने के लिए दबाव डाल चुके थे। वैसे तो सीमा विवाद के चलते थाइलैंड और कंबोडिया के बीच अक्सर छिटपुट तनाव भड़कता रहा है, लेकिन ताजा हिंसक टकराव प्रीह विहेयर (प्रिय विहार) नाम के एक हिंदू शिव मंदिर के मुद्दे पर भड़का। इसी कारण भारत के लोगों की इसमें उत्सुकता भी रही। यह स्वाभाविक है। वैसे तो कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बीते कुछ दिनों से तनाव बढ़ रहा था, लेकिन प्रीह विहेयर की स्थिति ने हालात विकट बना दिए। इसके चलते दोनों देशों की सेनाओं ने कमान संभाली और एक दूसरे से लोहा लेने लगीं। इसमें कई सैनिकों और आम नागरिकों की मौत हो गई। एक बड़ी संख्या में लोगों को उन इलाकों से पलायन भी करना पड़ा, जहां यह लड़ाई छिड़ी हुई थी।

दोनों देशों के बीच हाइड्रोकार्बन से समृद्ध एक समुद्री इलाके पर भी तकरार रही है। ऐसे में इनके टकराव को केवल धार्मिक पहलुओं से देखने पर पूरी तस्वीर स्पष्ट नहीं होगी, क्योंकि दोनों देशों में बहुलांश आबादी थेरवाद बौद्ध धर्म को मानने वाली है। पूरे परिदृश्य को समझने के लिए पृष्ठभूमि का संज्ञान लेना होगा। पड़ताल करें तो जहां थाइलैंड सदैव स्वतंत्र रहा है, वहीं पड़ोसी कंबोडिया वियतनाम और लाओस की तरह फ्रांसीसी उपनिवेश रहा। 1907 में कंबोडिया के औपनिवेशिक शासक फ्रांस और थाइलैंड (तब उसका नाम सियाम था) एक व्यापक सीमा समझौते पर सहमत हुए। कंबोडिया 1953 में स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के साथ ही थाइलैंड के साथ उसके सीमा विवाद शुरू हुए। विशेषकर प्रीह विहेयर मंदिर की स्थिति को लेकर। कंबोडिया 1959 में इस मामले को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले गया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 1962 में फैसला कंबोडिया के पक्ष में सुनाया। उस समय थाइलैंड ने मन मसोस कर वह फैसला मान लिया, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं यह भाव घर कर गया कि उससे उसका हक छीन लिया गया। प्रीह विहेयर मामले ने थाई जनता की चेतना को उस समय फिर से झकझोरा जब कंबोडिया ने 2008 में इस मंदिर को विश्व विरासत स्थल की मान्यता दिलाने के लिए यूनेस्को का रुख किया। यहां उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि खमेर शासन के दौरान 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान कंबोडिया में हिंदू धर्म का प्रसार अपने चरम पर पहुंच गया था। इस अवधि में वहां अद्भुत हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ। वैसे तो यह काम मुख्य रूप से सिएम रीप इलाके में हुआ, लेकिन कंबोडिया के दूसरे क्षेत्र भी मंदिर निर्माण से अछूते नहीं रहे। प्रीह विहेयर उसी दौर की अभिव्यक्ति है। भगवान विष्णु को समर्पित भव्य एवं दिव्य मंदिरों में से एक अंगकोरवाट का निर्माण भी सिएम रीप क्षेत्र में 12वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। कालांतर में कंबोडिया में थेरवाद बौद्ध का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ और 12वीं शताब्दी के अंत में अंगकोरवाट भी बौद्ध उपासना स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त करने लगा। हालांकि उपासना का यह क्रम पूर्व स्थापित ढांचे को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना आगे बढ़ता गया। मंदिर के शीर्ष पर बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई, जो मंदिर के बदलते स्वरूप का प्रतीक थी। यही वह दौर था जब कंबोडिया, लाओस, थाइलैंड और बाद में म्यांमार जैसे इलाके थेरवाद बौद्ध धर्म के प्रभाव में आते गए।

अवधेश राजपूत

थेरवाद बौद्ध धारा गौतम बुद्ध की उच्च नैतिक शिक्षाओं पर आधारित है, जो व्यक्ति को जन्म एवं पुनर्जन्म के फेर से मुक्त होकर निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करने की राह दिखाता है। थाइलैंड में बतौर राजदूत अपनी नियुक्ति के दौरान मैंने गौर किया कि जहां थाई बौद्ध बुद्ध को उच्च आध्यात्मिकता का शिखर समझते हैं, वहीं अपने वर्तमान जीवन में सहायता के लिए वे हिंदू देवी-देवताओं की भी पूजा करते हैं। थाई राज परिवार भी थेरवाद बौद्ध धर्म मानता है, लेकिन हिंदू पुजारियों का भी सम्मान करता है। कुछ पुजारी तो राजकीय महल से भी संबद्ध होते हैं। इस क्रम में राजा या राज परिवार का कोई अन्य वरिष्ठ सदस्य फसल बोआई के वार्षिक अनुष्ठान में शामिल होता है, जहां पुजारी बीजों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। रामायण का थाई संस्करण इस देश की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है।

दोनों देशों के रिश्तों में कंबोडिया के दिग्गज नेता हुन सेन और थाइलैंड की बड़ी राजनीतिक हस्ती के रूप में स्थापित हुए थाकसिन शिनवात्रा के बीच की मैत्री की भी छाप रही है। दोनों के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं। थाकसिन के 15 साल चले निर्वासन के दौरान हुन ने उनकी बहुत सहायता की, लेकिन थाकसिन के दोबारा थाइलैंड पहुंचने और वहां राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होने के बाद दोनों नेताओं के संबंध में खटास पैदा हो गई। अगस्त 2024 में थाइलैंड की प्रधानमंत्री बनीं थाकसिन की 36 वर्षीय बेटी पेटोंगटर्न ने हुन सेन के साथ रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलाने का प्रयास किया। एक निजी टेलीफोन बातचीत में हुन को 'अंकल' के रूप में संबोधित करते हुए उन्हें यह कहते हुए सुना गया कि 'दूसरे पक्ष' की ओर से मुश्किलें पैदा की जा रही हैं और वह सेना पर लगाम लगाएंगी। हुन ने बातचीत का ब्योरा इंटरनेट मीडिया पर जारी कर दिया और फिर थाई संवैधानिक अदालत को पेटोंगटर्न ने एक जुलाई को उनके पद से निलंबित कर दिया गया।

अभी दोनों देशों में राष्ट्रवादी भावनाओं का ज्वार उमड़ा हुआ है। ये भावनाएं समय के साथ शांत हो जाएंगी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि प्रीह विहेयर मंदिर प्रकरण का भी हमेशा के लिए पटाक्षेप हो जाएगा। यह विवाद सतह पर उभरता रहेगा। (लेखक थाइलैंड में भारत के राजदूत रहे हैं)

response@jagran.com

मजाक बनता एक गंभीर अपराध

दीपिका नारायण भारद्वाज

तमाम महिलाएं वर्षों तक सहमति से संबंधों के बाद पुरुषों पर फर्जी आरोप लगाकर दुष्कर्म के मामले दर्ज करा रही हैं

आठ साल पहले एक इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर दो बच्चों की मां बबली एक युवक बंटी (बदले हुए नाम) से बात शुरू करती है। जल्द ही यह बातचीत प्यार में बदल जाती है और दोनों कई बार होटल, लाज या कहीं भी मिलते हैं। शारीरिक संबंध बनते हैं। बबली को न अपने पति की कोई चिंता रहती है और न ही बच्चों की। पढ़ी-लिखी महिला अपनी मर्जी से, सोच-समझकर वर्षों शारीरिक संबंध बनाती है। धीरे-धीरे प्यार इतना परवान चढ़ता है कि दोनों शादी करने का सोचते हैं। बबली कई वर्षों तक पति को धोखा देने के बाद उससे तलाक ले लेती है, पर इस मोड़ तक आते-आते बंटी बदल जाता है और शादी करने से मना कर देता है। ऐसी कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी। आगे जो बबली करती है, वह नई कहानी है। यह कहानी है दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध का मजाक उड़ाने, यौन शोषण के नाम पर बदला लेने और सहमति से सैकड़ों बार बने शारीरिक संबंधों को अपराध का चोला पहनाने की।

सालों तक सहमति से बने संबंधों के बाद बबली ने बंटी पर दुष्कर्म का मुकदमा यह कहते हुए कर दिया कि वह इतने वर्षों से उसे शादी का झांसा दे रहा था। न कोई सुबूत, न जांच। बंटी पर दुष्कर्म जैसे संगीन अपराध का मुकदमा दायर हो गया। ऐसे मामलों में पुरुष कितना भी बेकसूर हो, पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। बंटी ने गिरफ्तारी के डर से हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली। इस पर बबली सुप्रीम कोर्ट चली गई, ताकि बंटी की अग्रिम जमानत खारिज करा सके, लेकिन शायद पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कड़वा सच कहा कि अगर सहमति नहीं थी तो बबली को इतनी बार बंटी के साथ होटल जाने की क्या जरूरत थी? उसकी यह टिप्पणी चर्चा का विषय बनी। दो बच्चों की मां बबली को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि शादीशुदा होते हुए गैर मर्द के साथ संबंध बनाने के लिए उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस मामले को कोई आम इंसान भी फर्जी बता देगा, लेकिन बंटी ने लंबे समय तक इस मुकदमे के साथ मानसिक प्रताड़ना और बदनामी का सामना किया। इसलिए किया, क्योंकि एक महिला ने कहा कि शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म हुआ है। यह इकलौता मामला नहीं है। भारत में इस समय ऐसे हजारों मुकदमे हैं। युवतियां-महिलाएं एक साल, दो, पांच, दस साल तक सहमति से बनाए संबंधों के बाद भी झूठा आरोप लगाते हुए दुष्कर्म के मुकदमे करा रही हैं।

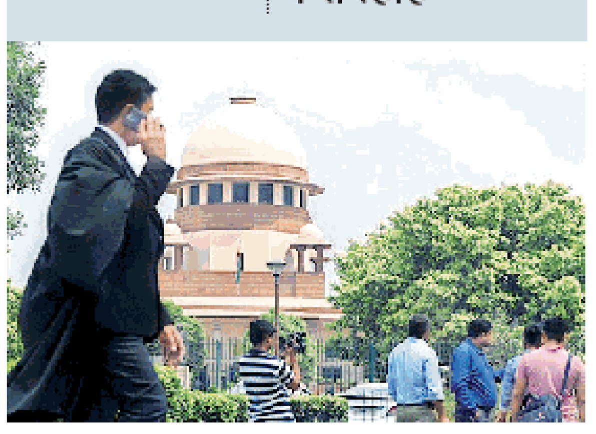

चिंतित करते कानून के दुरुपयोग के बढ़ते मामले। फाइल

आज जब महिलाएं अंतरिक्ष जा रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं, तब कई पढ़ी-लिखी महिलाएं किसी से भी शारीरिक संबंध बना रही हैं और बाद में कह रही हैं कि उनकी सहमति नहीं थी, उनसे शादी का झूठा वादा किया गया। विडंबना यह कि पुलिस, समाज और अक्सर अदालतें भी उन पर यकीन कर रही हैं। एक तरफ युवतियां माई बाडी-माई च्वाइस की बात कर रही हैं, शादी के बाहर या बिना विवाह संबंध बना रही हैं और दूसरी तरफ पुरुष शादी न करे तो उसे दुष्कर्मी कह रही हैं। यह कैसा दोहरा चरित्र है? राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देखें तो शादी का कथित झांसा देकर दुष्कर्म के मामले वर्ष 2015 में कुल दुष्कर्म के मामलों के 21 प्रतिशत थे, पर 2021 तक यह आंकड़ा 51 प्रतिशत तक पहुंच गया। साफ है कि दुष्कर्म के मुकदमों में लगभग आधे ऐसे हैं, जिनमें महिला ने पहले सहमति से संबंध बनाए और फिर कहा कि सहमति तो शादी के लिए दी थी। इस तर्क से तो यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति तलाक मांगता है तो उसे भी दुष्कर्मी बोला जा सकता है, क्योंकि महिला कह सकती है कि उसकी सहमति हमेशा साथ रहने की थी।

भारत के अलावा किसी अन्य बड़े लोकतांत्रिक देश में शादी का झांसा जैसी अवधारणा नहीं है और न ही पुरुषों को ब्रेकअप करने की वजह से जेल भेजा जाता है। हाल में क्रिकेटर यश दयाल को ऐसे ही मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली। जज ने पूछा, कोई महिला पांच साल तक शादी के झांसे में कैसे रह सकती है? जहां कुछ जज ये प्रश्न कर रहे हैं, वहीं दुष्कर्म संबंधी कानून का दुरुपयोग चरम पर पहुंच गया है। अब ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं, जहां एक ही महिला ने अलग-अलग पुरुषों पर चार-छह-दस मुकदमे करा दिए कि सबने शादी का झांसा देकर उसका शोषण किया। ऐसे मामलों में पुलिस ने सच जानने के बाद भी मुकदमे दर्ज किए और पुरुषों को जेल भेजा। कानून के दुरुपयोग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों कोलकाता में 26 साल के युवक के माता-पिता ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि बेटे को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में जेल भेज दिया गया। उसका एक युवती से तीन साल से संबंध था, पर शादी न होने की वजह से उसने दुष्कर्म का मुकदमा कर दिया। अब यदि वह निर्दोष साबित होता है, तो भी उसका सब कुछ लुट चुका है। अनगिनत युवा शादी के झांसे के झूठे मुकदमों में जिंदगी गंवा रहे हैं। आखिर पढ़ी-लिखी महिलाओं की समझ को बच्चों से भी कम क्यों आंका जा रहा है? महिला सशक्तीकरण का यह मतलब नहीं होना चाहिए कि महिला जब चाहे अबला बन जाए और जब चाहे सहमति से बनाए संबंधों को दुष्कर्म बता दे। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे झूठे मामलों में महिलाओं को फटकार लगाने के साथ उन्हें सजा भी देनी चाहिए। एक गंभीर अपराध को मजाक बनाना भी एक अपराध ही है।

(लेखिका फिल्मकार, सोशल एक्टिविस्ट और 'एकम न्याय' फाउंडेशन की संस्थापक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अहिंसा का महत्व

शांति, सुख और समता की प्राप्ति अंतरात्मा की शुद्धि से होती है। शुद्धि की यह राह आत्मजागरण से होकर गुजरती है। जागरण की इस प्रक्रिया में स्वयं को हिंसक प्रवृत्ति से दूर रखकर चित्त को शांत बनाना सीखना होगा। हमें पहले अपनी चिंता करनी चाहिए। यदि संसार न भी बदले, तब भी हमें स्वयं बदलना चाहिए। यही प्रयास दूसरों को भी बदलने की प्रेरणा देगा और यहीं से मैत्री, सहअस्तित्व और करुणा का जन्म होगा। यह भाव शत्रुओं तक के लिए विस्तार लेगा। पूर्ण अहिंसक बनना कठिन है, फिर भी यह हमारा आदर्श होना चाहिए कि हम हिंसा या उससे जुड़े विचारों को मन-मस्तिष्क में पनपने ही न दें। अपने द्वारा की गई हिंसा की नीर-क्षीर विवेचना भी आवश्यक है। इस विवेचना से हम स्वयं में सुधार लाने की ओर उन्मुख होंगे।

यह भी एक मिथ्या धारणा है कि हिंसा केवल शारीरिक होती है। बौद्धिक और आर्थिक हिंसा भी उतनी ही अधिक व्यापक हैं, जिनके दुष्प्रभाव राष्ट्र-समाज को क्षति पहुंचाते हैं। ठगी, रिश्वत, लालच-ये सब आर्थिक हिंसा के सूक्ष्म रूप हैं। एक बार इस मानसिकता का स्वाद लग जाए तो व्यक्ति उसमें फंसता चला जाता है। इसमें लोग एक-दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, पर खुद दोष नहीं छोड़ते। सुधार दोनों ओर से होगा तभी व्यवस्था बदलेगी। इसी प्रकार, अपने विचारों से दूसरों का दमन बौद्धिक हिंसा का उदाहरण है।

यह पूछना व्यर्थ है कि क्या पूरी दुनिया अहिंसक बन सकती है? न तो कभी ऐसा हुआ है और शायद यह संभव भी नहीं, किंतु यह स्पष्ट है कि जब तक अहिंसा का पलड़ा भारी रहेगा, तब तक मानवता की आशा बनी रहेगी। हमारे लिए विकास विलास नहीं, मूल्यनिष्ठा है। यह जीवन-दृष्टि केवल अहिंसा के प्रति गहन आस्था से संभव है। हमें अहिंसा के भाव को आत्मसात करना चाहिए। अहिंसा ही हमें जीवन की सही राह दिखाने में सक्षम है।

स्वामी देवेंद्र ब्रह्मचारी

प्रगति की दौड़ में पिछड़ते संस्कार

देवेंद्रराज सुथार

सामाजिक जागरूकता बढ़ाने से ही बुजुर्गों की देखभाल को सुविधाजनक बनाया जा सकता है

हाल ही में अयोध्या में कैंसर से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला को उसके परिवारजनों ने रात के समय ई-रिक्शा से लाकर सड़क किनारे छोड़ दिया। वह महिला न तो बोलने में सक्षम थी और न ही चलने में। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। बाद में अस्पताल में महिला की मृत्यु हो गई। यह घटना उस अयोध्या में घटित हुई है, जहां पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों की परंपरा रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये केवल सैद्धांतिक स्तर पर सीमित रह गए हैं।

भारत में बुजुर्गों की स्थिति के आंकड़े इस समस्या की गंभीरता को स्पष्ट करते हैं। वर्तमान में देश में 60 वर्ष से अधिक आयु के 10.9 करोड़ बुजुर्ग हैं। वर्ष 2031 तक यह संख्या 19.4 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। परंतु इस जनसांख्यिकीय बदलाव के साथ सामाजिक संरचनाओं में आवश्यक परिवर्तन नहीं हो रहे। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और छोटे परिवारों की बढ़ती संख्या ने पारंपरिक पारिवारिक सहायता प्रणालियों को कमजोर कर दिया है। अनेक बुजुर्ग उपेक्षा और परित्याग का शिकार हो रहे हैं। यह स्थिति मूल्यों में आए परिवर्तन का दुष्परिणाम है।

अयोध्या की घटना आधुनिक भारतीय समाज की उस मानसिकता का प्रतीक है, जहां पारिवारिक दायित्व केवल सुविधा और लाभ के आधार पर निर्धारित होते हैं। जब बुजुर्ग आर्थिक रूप से अनुत्पादक हो जाते हैं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण देखभाल की आवश्यकता होती है, तो वे परिवार के लिए बोझ माने जाने लगते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर तीसरा बुजुर्ग किसी न किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना करता है। भारतीय समाज में जो पारंपरिक मूल्य प्रणाली थी, वह तेजी से विघटित हो रही है। 'मातृ देवो भव, पितृ देवो भव' जैसे आदर्श केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित रह गए हैं। व्यावहारिक जीवन में इनका कोई स्थान नहीं रह गया है। करियर की प्राथमिकताएं, व्यक्तिगत सुख की खोज और भौतिक सफलता की होड़ ने पारिवारिक दायित्वों को द्वितीयक बना दिया है। नई पीढ़ी के लिए बुजुर्गों की देखभाल एक बाधा लगती है। यह स्थिति केवल व्यक्तिगत चरित्र की समस्या नहीं है, बल्कि शिक्षा प्रणाली, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक मूल्यों में आए परिवर्तन का परिणाम है।

वर्तमान कानूनी ढांचा इस समस्या के समाधान में अपर्याप्त साबित हो रहा है। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 बनाया गया था और 2019 में इसमें संशोधन भी किया गया। इस कानून के अनुसार, बच्चों पर अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल की कानूनी जिम्मेदारी है। परंतु अयोध्या जैसी घटनाएं दिखाती हैं कि कानूनी प्रविधान और सामाजिक वास्तविकता के बीच व्यापक अंतर है। समस्या की जड़ें कानूनी ढांचे में नहीं, बल्कि सामाजिक मानसिकता में हैं। जब तक व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक केवल कानूनी प्रविधान प्रभावी नहीं हो सकते।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

भाषा पर होना चाहिए उदार रवैया

'एडीएम को अंग्रेजी बोलना जरुरी क्यों है' शीर्षक से लिखे आलेख में राजीव सचान ने सही लिखा है कि 'अपने देश में केवल अंग्रेजी जानना नहीं, उसे बोलना भी योग्यता और श्रेष्ठता का परिचायक है, इसलिए उसका आतंक है।' अंग्रेजी को ज्ञान बुद्धिमत्ता और काबिलियत की भाषा माना जाता है। जबकि दुनिया के बहुत से देश हैं, जो अपनी मूल भाषा के बल पर अग्रणी बने हुए हैं। किसी भाषा के ज्ञान का बुद्धिमत्ता से कोई सीधा संबंध नहीं है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी खासकर न्यायालयों में अभी भी अंग्रेजी मानसिकता हावी है। न्यायालय आमजन से जुड़ने का प्रयास भी नहीं करते। क्या न्यायाधीशों को नहीं पता कि एक प्रशासनिक अधिकारी का आधिकारिक जीवन स्थानीय लोगों के बीच ही बीतता है। ऐसे में उसका स्थानीय भाषा आना अधिक जरूरी है, बजाय अंग्रेजी आने के। अंग्रेजी को प्राथमिकता देने वाले लोगों पर मैकाले की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। यदि यह माना भी जाए कि उत्तराखंड में विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं और उनसे संवाद अंग्रेजी में ही हो सकता है, इसके बावजूद जैसा कि लेखक ने कहा 'आज एआइ के जमाने में' भाषा अनुवादक एप्लीकेशंस बहुत प्रभावी हैं। उनका उपयोग किया जा सकता है। हालांकि यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अधिकतर विदेशी पर्यटक 'अंग्रेजी भाषी देशों' से ही नहीं आते हैं। तो क्या लोगों को तमाम विदेशी भाषाएं भी आनी चाहिए? अच्छी बात है कि भाषा को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट की टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उदारता दिखाई है।

युवराज पल्लव, सहारनपुर (उ. प्र.)

प्रतिक्रिया

सरकारी अस्पतालों की दशा

अभी भी कई सरकारी अस्पतालों की स्थिति गंभीर है। वहां न तो पर्याप्त संख्या में डाक्टर उपलब्ध हैं और न ही दवाइयों की उचित व्यवस्था है। साफ-सफाई की कमी भी देखने को मिलती है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। मरीजों को इलाज के लिए कई घंटे तक लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। कई बार तो डाक्टर समय पर अस्पताल भी नहीं आते। अस्पताल के खराब बुनियादी ढांचे, गंदगी भरी परिस्थितियों और सीमित चिकित्सा सुविधाओं की ओर सभी संबंधित अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में अक्सर देखा जाता है कि डाक्टरों और प्रशिक्षित कर्मचारियों की यहां भारी कमी रहती है, जिससे मरीजों को, खासकर गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। हाल ही में मेरठ मेडिकल कालेज में ऐसी लापरवाही सामने आई जिसमें एक रात के समय एक घायल युवक का इलाज नहीं हो सका जिस कारण उसकी जान चली गई। वार्डों की स्थिति भी अत्यंत चिंतनीय है, जहां मरीजों को उचित देखभाल मिलना मुश्किल हो जाता है। कर्मचारियों की उदासीनता और लापरवाही मौजूदा हालात को और भी बिगाड़ रही है। स्वास्थ्य सेवा निदेशक और अन्य संबंधित अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि इन समस्याओं को दूर करने के लिए तुरंत कदम उठाए जा सकें।

वैभव, चितकारा यूनिवर्सिटी, पंजाब

सही प्रबंधन से थमेगी भगदड़ की त्रासदी

विमर्श पेज पर बुधवार को प्रकाशित मोनिका राज का आलेख 'गंभीर चुनौती बनता भीड़ प्रबंधन' वाकई में भीड़तंत्र पर एक बेहतरीन विश्लेषणात्मक आलेख है, जो कि भीड़तंत्र पर सार्थक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। हाल ही में हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ ने अपर्याप्त प्रबंधन और संकरी चढ़ाई के कारण भगदड़ का रूप ले लिया। अफवाहों, बिजली के करंट और तार गिरने जैसी घटनाओं ने हालात और भयावह बना दिए। यह पहली बार नहीं है। इसके स्थायी समाधान के लिए भीड़ प्रबंधन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लागू करना होगा। प्रवेश और निकास मार्ग चौड़े किए जाएं, बैरिकेडिंग से नियंत्रित संख्या में ही लोगों को अनुमति दी जाए। सीसीटीवी निगरानी, लाउडस्पीकर से सूचना और सुरक्षा बलों व स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। विशेष आयोजनों में यह प्रणाली अपनाने से अनियंत्रित भीड़ की त्रासदियां रोकी जा सकती हैं।

आदित्य राज, नेहरू विहार, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

89 हजार से अधिक सरकारी स्कूल बंद हुए वर्ष 2014-15 से 2023-24 के दौरान देश भर में। वर्ष 2014-15 में इनकी संख्या 11.07 लाख थी, जो घटकर 10.17 लाख रह गई।

कैलाश बिश्नोई
उच्च शिक्षा मामलों के जानकार

झालावाड़ स्कूल दुर्घटना

बच्चों की सुरक्षा को दी जाए प्राथमिकता

राजस्थान के झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरने से सात मासूमों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। यह हादसा निर्माण में त्रुटि के साथ ही निगरानी व्यवस्था की विफलता भी है। ऐसे में केंद्र सरकार का सुरक्षा आडिट का निर्देश एक आवश्यक कदम है। अब आवश्यकता इस बात की है कि हर राज्य इसे गंभीरता से ले, ताकि शिक्षा के मंदिर दुर्घटना के शिकार न बनें। सरकारी शिक्षा व्यवस्था में यदि विश्वास कायम रखना है, तो बुनियादी ढांचे में निवेश करने के साथ ही उसकी निगरानी व्यवस्था में भी सुधार लाना होगा

बीते शुक्रवार को राजस्थान के झालावाड़ में इसी स्कूल की छत गिरने से सात बच्चे मारे गए और 27 से अधिक घायल हो गए थे। फाइल

झालावाड़ की त्रासदी ने यह दर्शाया है कि शिक्षा केवल पाठ्यक्रम या परीक्षा नहीं, सुरक्षा और सरोकार की बुनियाद भी है। यह हादसा जर्जर भवनों की नहीं, जर्जर जिम्मेदारियों की कहानी है। यदि अब भी हम नहीं जागे, तो हमारी चुप्पी अगली दुर्घटना की भागीदार बनेगी। यह अत्यंत चिंताजनक है कि एक ओर हम शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं, डिजिटल क्लासरूम और स्मार्ट एजुकेशन की योजनाएं गिनाते हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण भारत के लाखों विद्यालयों में बच्चे अब भी उन दीवारों के बीच बैठकर पढ़ते हैं जिनका गिरना केवल समय का इंतजार है। क्या यह हमारी नीति-निर्माण प्रणाली की विफलता नहीं कि हम जर्जर भवनों की सूची तभी तैयार करते हैं जब कोई मासूम हादसे का शिकार हो जाता है? यदि जिला अधिकारी यह कह रहे हैं कि विद्यालय भवन की सूचना नहीं दी गई थी, तो क्या सूचना न देना ही सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाने का प्रमाण है?

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन विद्यालयों में देश का भविष्य पलता है, वही सबसे अधिक उपेक्षा का शिकार होते हैं। और इस उपेक्षा की सबसे बड़ी मार वे बच्चे झेलते हैं जो समाज के सबसे पिछड़े और कमजोर तबकों से आते हैं। जिनके पास न तो विकल्प होते हैं, न ही शिकायत करने की शक्ति। अब समय आ गया है कि हम केवल निर्देश जारी करने की खानापूरी से आगे बढ़ें और व्यवस्थागत बदलावों की दिशा में ठोस कदम उठाएं। राज्य सरकारों को चाहिए कि प्रत्येक जिले में विद्यालयों की संरचनात्मक स्थिति का वैज्ञानिक मूल्यांकन कराएं, और जिन भवनों को खतरा बताया जाए, वहां पढ़ाई तत्काल बंद कर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। जो अधिकारी निर्देशों की अनदेखी करें, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। विद्यालयों की सुरक्षा अब केवल शिक्षा विभाग का विषय नहीं, यह नैतिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, जिसे हर स्तर पर गंभीरता से निभाना होगा। तभी जाकर हम यह दावा कर सकेंगे कि हम सचमुच एक शिक्षित, जागरूक और उत्तरदायी राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं।

स्कूली शिक्षा के समक्ष चुनौतियां : आज जब देश विकास, डिजिटल क्रांति और अमृतकाल की बात कर रहा है, तब यह सच्चाई हमें झकझोरती है कि भारत के सरकारी स्कूलों की बुनियादी संरचना अब भी भयावह स्तर पर जर्जर और असंतुलित है। शिक्षा का अधिकार तो बहुत पहले मिला, लेकिन शिक्षा का वास्तविक अधिकार- सुरक्षित भवन, स्वच्छ शौचालय, बिजली, पानी, खेल, पुस्तकालय आदि आज भी करोड़ों बच्चों के लिए एक सपना बना हुआ है। सरकारी आंकड़ों और विभिन्न रिपोर्ट्स की बात करें तो तस्वीर कहीं से भी संतोषजनक नहीं लगती। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (असर) के अनुसार, देश के 1.52 लाख स्कूलों में बिजली की सुविधा नहीं है। बिजली की अनुपस्थिति न केवल कक्षाओं को प्रभावित करती है, बल्कि गर्मी-सर्दी में बच्चों की सेहत और सीखने के वातावरण को भी सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाती है। यदि डिजिटल लर्निंग की कल्पना की जाए, तो यह असंभव प्रतीत होती है, क्योंकि देश के 90 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है और 60 प्रतिशत से अधिक स्कूलों में कंप्यूटर ही नहीं हैं।

शौचालयों की स्थिति भी अत्यंत दयनीय है। असर रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 67 हजार स्कूलों में कार्यात्मक शौचालय नहीं हैं। चिंताजनक यह कि बालिकाओं के लिए अलग शौचालय 53 प्रतिशत स्कूलों में ही उपलब्ध है। इससे बालिकाओं की उपस्थिति, सुरक्षा और गरिमा पर सीधा असर पड़ता है। यही नहीं, 11 हजार स्कूलों में शौचालय होते हुए भी निष्क्रिय हैं, और 33.2 प्रतिशत स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालय नहीं हैं, जो समावेशी शिक्षा के दावों की पोल खोलते हैं।

एक भयावह सच यह भी है कि वर्ष 2017-18 से 2023-24 के बीच 76 हजार से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। यह दर्शाता है कि स्कूलों की संख्या कम हो रही है, जबकि जनसंख्या और स्कूली बच्चों की संख्या में कमी नहीं आई है। सवाल यह भी उठता है कि क्या ये स्कूल बंद इसलिए हुए, क्योंकि उनकी मरम्मत, संचालन या सुविधा देना शासन के लिए असुविधाजनक था? अब समय आ गया है कि शिक्षा को केवल नीति पत्रों और बजट घोषणाओं से नहीं, बल्कि जमीनी कार्यवाही से जोड़ा जाए। आवश्यक है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक राष्ट्रीय स्तर का स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन प्रारंभ करें, जो समयबद्ध, जवाबदेह और पारदर्शी ढंग से हर स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करे।

शिक्षकों की कमी की समस्या : शिक्षा एक राष्ट्रीय संकल्प है, केवल स्कूली पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, समान अवसर और मानव विकास की कुंजी है। जब तक हमारे स्कूल बच्चों के बैठने, पढ़ने, पीने और सोचने लायक नहीं होंगे, देश के सरकारी स्कूलों को पुनर्जीवित करना अब केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जरूरत है। शिक्षकों की कमी तो जैसे अब एक स्थाई समस्या बन गई है। पूरे देश में शिक्षकों की रिक्तियां 10 लाख से अधिक हैं और सबसे अधिक संकटग्रस्त क्षेत्र है- ग्रामीण भारत। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में शिक्षकों के एक-एक लाख से भी अधिक पद खाली हैं। ये वही राज्य हैं जहां स्कूली बच्चों की संख्या सर्वाधिक है और जहां सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर तबके के बच्चे शिक्षा को जीवन परिवर्तन का साधन मानते हैं। जब शिक्षक ही नहीं होंगे, तो शिक्षा का स्वरूप किस आधार पर टिकेगा? अधिकतर जगहों पर छात्र-शिक्षक अनुपात 47 : 1 तक पहुंच चुका है, जबकि आदर्श अनुपात 30 : 1 होना चाहिए यानी 30 छात्रों पर एक शिक्षक। ऐसी स्थिति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की अपेक्षा करना स्वयं भ्रम पालने जैसा है। और यदि नियुक्त शिक्षक भी प्रशिक्षित न हों, तो वह संकट और गहरा हो जाता है।

यह विडंबना ही है कि डिजिटल युग में भी कई राज्यों में हजारों की संख्या में अयोग्य शिक्षक अब भी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। लिहाजा समय आ गया है कि शिक्षा को केवल नीतिगत घोषणा या चुनावी मुद्दा मानने के बजाय, उसे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का प्राथमिक साधन समझा जाए। हमें शिक्षकों की नियुक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, स्कूलों को डिजिटल और समावेशी बनाना होगा और मूल्यांकन की प्रणाली को 'रचना' पर केंद्रित करना होगा, न कि 'रटना' पर। जब तक शिक्षा की जमीन मजबूत नहीं होगी, तब तक किसी भी समाज की ऊंचाई टिकाऊ नहीं हो सकती।

निजी स्कूलों की ओर बढ़ता रुझान

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पिछले दो दशकों में एक अद्भुत, लेकिन चिंताजनक बदलाव देखा गया है। वस्तुतः सरकारी स्कूल कभी शिक्षा के सर्वसुलभ केंद्र माने जाते थे, परंतु आज धीरे-धीरे आम जन के भरोसे से दूर होते जा रहे हैं। इसके विपरीत, निजी स्कूलों की लोकप्रियता, संख्या और प्रभाव में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यह बदलाव केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं के बदलाव का भी प्रतीक है। निजी स्कूलों के प्रति अभिभावकों का आकर्षण किसी एक कारण से नहीं, बल्कि कई परतों में फैली एक जटिल सच्चाई को उजागर करता है। गुणवत्ता की मांग इस रुझान का प्रमुख कारक है। अधिकांश अभिभावक मानते हैं कि निजी स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता बेहतर है, शिक्षकों की उपस्थिति अधिक है और अंग्रेजी माध्यम के कारण छात्रों को भविष्य में प्रतिस्पर्धा में लाभ मिलता है। यह धारणा चाहे पूरी तरह सही न हो, लेकिन सरकारी स्कूलों की निष्क्रियता और जवाबदेही की कमी ने इसे गहराई से जनमानस में बैठा दिया है।

सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे की कमी आज भी एक कड़वी सच्चाई है। लाखों स्कूलों में अब भी बिजली, पेयजल और कार्यात्मक शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इन कमियों ने सरकारी स्कूलों की साख को उस बिंदु पर पहुंचा दिया है जहां शिक्षा व्यवस्था के बजाय यह केवल नाममात्र की उपस्थिति बनकर रह गए हैं। शिक्षकों की अनुपस्थिति, लापरवाही और कई बार शिक्षण के प्रति उदासीनता ने इस स्थिति को और भी भयावह बना दिया है। इस संकट की एक अन्य परछाई निजी ट्यूशन के बढ़ते चलन के रूप में देखी जा सकती है। जब विद्यालय शिक्षा देने में विफल रहते हैं, तो छात्र ट्यूशन पर निर्भर हो जाते हैं। शहरीकरण ने इस प्रवृत्ति को और गति दी है। जैसे-जैसे शहरी क्षेत्र बढ़ते हैं, वहां निजी स्कूलों की संख्या में तीव्र वृद्धि देखी गई है। मध्यम वर्ग के अभिभावक अब शिक्षा को केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और भविष्य के बेहतर अवसरों का साधन मानते हैं। उनके लिए अंग्रेजी माध्यम, स्मार्ट क्लास और डिजिटल सुविधाएं महज आकर्षण नहीं, बल्कि 'बेहतर भविष्य' की सीढ़ी हैं।

कहा जा सकता है कि शिक्षा का यह निजीकरण केवल सुविधाओं का मामला नहीं है, यह शिक्षा के उद्देश्य और नीति की भी पुनर्समीक्षा की मांग करता है। जब सरकारी स्कूलों में कक्षा तीन के 75 प्रतिशत छात्र कक्षा दो का पाठ तक ठीक से नहीं पढ़ सकते, तब यह केवल व्यक्तिगत विफलता नहीं, बल्कि नीति-निर्धारण की सामूहिक चूक है। वर्ष 2014-15 से 2023-24 के बीच सरकारी स्कूलों की संख्या 11 लाख से घटकर 10 लाख रह गई, जबकि निजी स्कूलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। यही नहीं, अब 22.5 प्रतिशत छात्र निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जबकि 2012-13 में यह आंकड़ा 17.2 प्रतिशत था। शिक्षा में निजी क्षेत्र के इस प्रसार ने इसे सामाजिक अधिकार से अधिक बाजारी उत्पाद बना दिया है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हमारे देश में शिक्षा को फिर से एक सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखा जाए। **(कैलाश बिश्नोई)**

खरी-खरी

साहित्य के बाजार में लाइजनिंग

मनीष कुमार चौधरी

साहित्य के बाजार में उनकी तूती बोला करती थी। साहित्य का 'बाजार' इसलिए लिखा गया है कि आप समझ जाएं, वह लेखक महाशय साहित्य की दुनिया में अपना नाम पैदा करने के लिए जिन हथकंडों का इस्तेमाल करते थे, वह काम बाजार में ही किया जा सकता है। वे कुछ 'इधर' से लेते, कुछ 'उधर' से। इधर-उधर होने की कला में इतने पारंगत थे कि इधर से उधर और उधर से इधर होने में जरा भी नहीं हिचकते थे। कभी 'लेफ्ट वालों के साथ हो लेते, कभी 'राइट' वालों के साथ। वे कभी किसी खूंटे से नहीं बंधे। किसी आजाद पंछी की तरह दूसरे के घोसलों का ही इस्तेमाल करते रहे। साहित्य के बाजार में लाइजनिंग की क्या भूमिका होती है, कोई उनसे सीखे।

साहित्य के कुछ दलालों से उनकी इतनी तगड़ी साठगांठ थी कि साहित्य की दुनिया में चर्चा में बने रहे, वे दलाल काफी हाउस से लेकर तमाम साहित्यिक बैठकों, गोष्ठियों में उनके महान लेखन का गुणगान करते रहते। इसी सशक्त लाइजनिंग के दम पर महीने में दो-चार पुरस्कार हथिया लेना उनके बाएं हाथ का खेल था।

कोई उनकी प्रतिभा पर शंका जताता तो उससे उलझते नहीं थे। यानी वह लेफ्ट-राइट, लेफ्ट-राइट तो करते, पर किसी के साथ 'फाइट' नहीं करते। फाइट करने के लिए जो जिगरा चाहिए, वह उनके पास नहीं था। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर पतली गली से यह कहकर निकल लेते कि मैं तो 'बाइ बोर्न' लेखक हूं। मजे की बात यह कि जिसे वह लेखन बताते थे, वह मौलिक लेखन कम, अनुवाद ज्यादा होता था। जब उनका कुछ मौलिक है ही नहीं, तो उन पर क्या आक्षेप लगाएं।

कहीं से कुछ उठाना और उसे अपना बनाकर पेश करने के लिए उच्च स्तर का 'लाइजनिंग टैलेंट' चाहिए। अवसरवाद का तड़का भी लगाना होता है। इतने प्रयासों के बाद किसी साहित्यिक मौलिक रचना का जन्म होता है। इसलिए उनके साहित्य (अनुवाद) में कापी-पेस्ट का भी ख्याल आता है। हालांकि यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए जमीर को ताक पर रखना पड़ता है, जो कि वह रख चुके थे।

X पोस्ट

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ और पेनाल्टी लगाने का एलान किया है। यह दर्शाता है कि भारत उनकी सौदेबाजी के आगे झुका नहीं। अपने हितों के लिए हमें रूस से और तेल खरीदना चाहिए।
कुशल मेहरा@kushal_mehra

भारत पर टैरिफ की घोषणा के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-अमेरिका संबंधों को भारी क्षति पहुंचाई है। कुछ मुद्दों पर मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों से लगातार परवान चढ़ रहे थे। भारत के लिए भी इस प्रकरण में एक सबक निहित है कि कूटनीति में किसी पहलू को हल्के में न लिया जाए। यहां कोई भी 'दोस्त' नहीं, कम से कम ट्रंप तो कतई नहीं।
निधि राजदान@Nidhi

संसद में आपरेशन सिंदूर पर चर्चा एक बड़ा अवसर थी, लेकिन इससे देश को कुछ हासिल नहीं हुआ। हमें वही कुछ बातें जानने को मिलीं, जिनमें से कुछ पहले से पता थीं। यह बहस केवल सत्तापक्ष और विपक्ष के लिए एक राजनीतिक मौका बनकर रह गई।
संकेत उपाध्याय@sanket

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या कांग्रेस ने शशि थरूर, मनीष तिवारी को आपरेशन सिंदूर पर बहस से दूर रखकर सही किया?

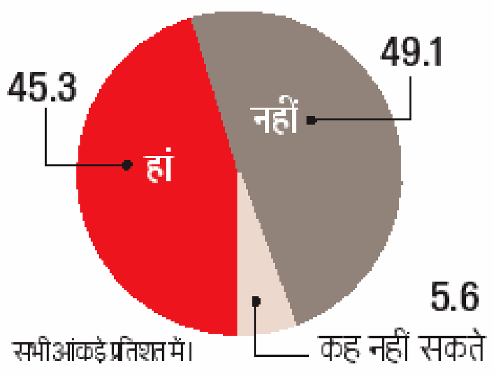

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ घोषणा भारत-अमेरिका संबंधों को क्षति पहुंचाएगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

चर्चा जब-जब चाहते खुलती खुद की पोल,
जब गाएं युवराज तो फट जाता है ढोल।
फट जाता है ढोल खुले पुरखों की नीती,
करने लगते लोग बेवजह बातें बीती।
हो खुद की इंसल्ट बुद्धि जब करते खर्चा,
फिर भी वे हर बार चाहते करना चर्चा!
- ओमप्रकाश तिवारी

धनंजय प्रताप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, नईदुनिया, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश डायरी

राहुल के जाते ही कांग्रेस 'सरेंडर'

धार जिले के पर्यटन स्थल मांडू में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में जुटे प्रदेश कांग्रेस के नेता। फाइल

भाजपा ने डा. मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश में बदलाव के जिस दौर की शुरुआत की थी, उसमें कांग्रेस को मजबूत विपक्ष बनाने की सारी संभावनाएं निहित थीं, लेकिन बीते डेढ़ वर्षों में कांग्रेस पहले से भी कमजोर दिखाई पड़ रही है। जनहित, अपराध, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर वह न सड़क पर मजबूती से उतर पा रही है, न ही सदन में सरकार को घेरने में कामयाब दिखाई दी है। बीते माह भोपाल आए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए 'नरेन्दर सरेंडर' का विवादित बयान दिया था, लेकिन उनके लौटते ही कांग्रेस अपने पुराने ढर्रे पर आ गई।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बदलती हुई संस्कृति पर भाजपा की छाप दिखाई पड़ती है। हाईकमान ने अपनी परिपाटी से अलग चलकर वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया और जीतू पटवारी जैसे युवा नेता को प्रदेश की कमान सौंप दी। पटवारी विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और विधानसभा के अंदर उनकी मौजूदगी नहीं है, ऐसे में सदन के अंदर भी युवा चेहरों पर भरोसा करते हुए उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। उम्मीद थी कि कांग्रेस के युवा चेहरे पहली बार मुख्यमंत्री बने मोहन यादव की सरकार को सीधी टक्कर देंगे। मोहन यादव ने विभागों के बंटवारे में गृह, उद्योग और जनसंपर्क जैसे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास ही रखे हैं, ऐसे में कयास थे कि कानून व्यवस्था, अपराध जैसे मुद्दों पर कांग्रेस सीधे मोहन यादव को घेरेगी, लेकिन भोपाल से उज्जैन, इंदौर तक लव जिहाद जैसे मामलों के पर्दाफाश के बाद भी कांग्रेस इस पर मुखर होने से बचती रही।

भाजपा के अंदरूनी समीकरण में स्पष्ट है कि मोहन यादव विधायक दल से लेकर कैबिनेट तक अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जैसे मजबूत होने का प्रयास कर रहे हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। कई मौकों पर अपने बयानों से मंत्रियों और विधायकों ने सरकार व संगठन की फजीहत कराई है। शिकवे-शिकायतों का दौर भी थम नहीं रहा है। ऐसे मौके विपक्ष के लिए अलग तरीके से बड़े अवसर पैदा करते हैं, लेकिन जीतू पटवारी और उनकी टीम इस दिशा में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकी है। 90 डिग्री कोण वाले पुल के निर्माण कार्यों में तकनीकी खामी को लेकर भी कई मामले सामने आए। मुख्यमंत्री को आगे जाकर कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले पर आगे आने के बजाय दर्शक ही बनी रही।

विंध्य क्षेत्र में गांवों में सड़क न होने से महिलाओं, विशेषकर गर्भवतियों के लिए दुविधा को लेकर इंटरनेट मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए। जनता ने वीडियो बनाकर वायरल किया और जनप्रतिनिधि से सीधा मोर्चा लिया। कांग्रेस इस मामले में साथ भी आई, लेकिन प्रभावशाली तरीके से नागरिकों के सामने नहीं रख सकी। अधिकारियों के खिलाफ जांच का पत्र भी प्रदेश में सनसनी की तरह फैल गया, लेकिन कांग्रेस को इसमें सरकार को घेरने लायक शायद कुछ नहीं दिखा।

भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस ने युवा चेहरों पर भरोसा जताया और इन चेहरों ने भाजपा की तर्ज पर अपने नेताओं को संवाद कौशल विकास की ट्रेनिंग भी दी, लेकिन संगठन में कार्यकर्ताओं की कमी की तरफ अभी अनदेखी ही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ हमेशा कहते रहे हैं कि कांग्रेस में नेता ज्यादा हैं, कार्यकर्ता कम। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की कमी शीर्ष नेतृत्व महसूस करता है। जीतू पटवारी अब तक जितने प्रदर्शन आयोजित कर चुके हैं, उसमें संख्या बल की कमी उनके उत्साह को चोट पहुंचाती है। वरिष्ठ नेताओं को तरजीह न दिए जाने का नतीजा है कि कार्यकर्ताओं का बड़ा धड़ा आने वाले समय में अपने लिए संभावनाएं तलाशता हुआ फिलहाल हाथ पर हाथ धरे बैठा है। कांग्रेस का मुकाबला उस भाजपा से रहा है, जो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है।

युवाओं, महिलाओं, मजदूर और कमजोर वर्ग को जोड़ने में कांग्रेस की दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे वर्गों के मुद्दे उठाने के लिए विधानसभा से बेहतर कौन सी जगह हो सकती है, लेकिन सदन में भी कांग्रेस 'भैंस के आगे बीन बजाने' जैसे प्रदर्शन तक ही सीमित है। ये प्रदर्शन कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं, इस पर कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए। कोई शक नहीं है कि आय की तुलना में लोगों का खर्च बढ़ा है। गरीब और मध्यम आय वर्ग के लिए गुजर बसर आसान नहीं रहा। ऐसे मुद्दों को कांग्रेस गंभीरता से उठाने में चूक कर रही है। इंटरनेट के दौर में जब सारे दावों की हकीकत क्षण भर में पता चल सकती है, तो कांग्रेस ऐसे किसी प्रयोग को लेकर तैयारी नहीं कर रही है। कांग्रेस की यही सरेंडर मुद्रा मोहन सरकार के लिए 2028 तक का सफर तय करने का सरपट रास्ता तैयार कर रही है।

हिमाचल प्रदेश डायरी

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल! क्या तुम्हें नूराकुश्ती पसंद है

सराज में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की गाड़ी का घेराव करते आपदा से प्रभावित लोग। फाइल

बीते दिनों एक बड़े पत्रकार से चंडीगढ़ में मुलाकात हुई। कहा कि वह कई वर्ष पूर्व एक स्टोरी प्लान कर रहे थे कि राज्यों का विकास कैसे हुआ। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से समय लिया और अपने प्रश्न रखते, इससे पूर्व ही धूमल ने उन्हें कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास में केवल मेरा ही योगदान नहीं है, सभी मुख्यमंत्रियों की भूमिका है। इसलिए वीरभद्र सिंह जी को भी यहीं बुला लेते हैं, हम दोनों आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने बीते वर्षों में कैसे उन्नति की। वीरभद्र सिंह भी वहां आए और चर्चाक्रम चला। यह उन नेताओं की बात है जिनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता किसी से नहीं छुपी थी।

आज के हिमाचल प्रदेश की एक बानगी यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी जिले में अपने विधानसभा क्षेत्र सराज में भारी तबाही के बाद से वहीं बने हुए हैं। पर राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ऐसी बातें कर गए हैं जो उनके पद की गरिमा के साथ मेल नहीं खातीं। वह विधानसभा में भी प्रतिपक्ष को बेहद कड़वे बोल बोलने के लिए जाने जाते हैं। सराज से बागवानी कालेज भी सुंदरनगर स्थानांतरित किया गया था। इन सबके कारण एक माहौल था सराज में। जैसे ही मंत्री जी सराज पहुंचे, उनके साथ अप्रिय घटनाक्रम हो गया। गाड़ी में बैठे रहना पड़ा, गाड़ी पर कुछ ऐसी वस्तुएं फेंकी गईं, जिनके बिना विशेषतः बरसात में मनुष्य अधूरा रहता है। इसके बावजूद जनता ने ऐसा किया। कांग्रेस का कहना है कि यह सब नेता प्रतिपक्ष और सराज के विधायक जयराम ठाकुर ने करवाया। क्योंकि बयानयुद्ध जारी था और नेगी किन्नौर से आते हैं, वहां जयराम का पुतला फूंका गया। उस पर मंत्री जी के पुत्र के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज हुई।

इधर सराज में जो मंत्री के साथ हुआ, उस पर कई लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी और सख्त धाराओं में मामला दर्ज हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां तक कहा कि चूंकि यह मंत्री के विरुद्ध हुआ, इसलिए यह तिरंगे का अपमान है।

सामान्यतः भीड़ के विरुद्ध मामला नहीं बनता, लेकिन भीड़ में लोग पहचाने गए और अब कानून अपना काम करेगा। इस पर राजनीतिक आक्षेप भी चले। विधायक सुधीर शर्मा ने ऐसा शब्द प्रयोग किया जो हरमेश मल्होत्रा के निर्देशन में 1975 में बनी एक हिंदी फिल्म का नाम था। इस पर पलटवार करते हुए जगत सिंह ने कहा कि सुधीर को क्षेत्रीय अस्पताल में उपचार करवाना चाहिए। गौरतलब यह है कि सराज में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गए, मंत्रिगण क्रमशः धनी राम शांडिल, विक्रमादित्य सिंह और राजेश धर्माणी गए, किसी के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। अब यह सवाल तो बनता ही है कि केवल मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ ही ऐसा क्यों।

जनता या जनप्रतिनिधि का आक्रोश कितना भी वैध क्यों न हो, वह सभ्य विमर्श और मर्यादित व्यवहार की धज्जियां नहीं उड़ा सकता। यदि राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी के सिर पर घड़ा फूटना गलत था तो मंत्री की असंवेदनशील बयानबाजी भी गलत थी। और यदि यह सब गलत था तो सराज में जो व्यवहार मंत्री के साथ हुआ, वह भी गलत था। लेकिन मूल प्रश्न दो हैं। क्या यही हिमाचल प्रदेश के वास्तविक मुद्दे हैं? क्या यही हिमाचल की राजनीतिक संस्कृति का संरक्षण है? आपदाओं से घिरे रहने वाले, कर्ज के बोझ में दबते, बेरोजगारों का बड़ा समूह तैयार करते प्रदेश की प्राथमिकताएं क्या ऐसी नौटंकियों से नेपथ्य में नहीं जातीं?

जिस प्रदेश में बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली स्वयं अधिकारियों के अहंकार की टंकार से हिल रही हो, वहां व्यवस्था मूल प्रश्न हो या बयानबाजी? बिजली बोर्ड में बड़े अधिकारियों के बीच पत्र युद्ध जारी है। एक पत्र लिखता है तो लगभग पता ही होता है कि दूसरा क्या जवाब देगा। गालिब ने कहा था- कासिद के आते आते खत इक और लिख रखूं/ मैं जानता हूं वो जो लिखेंगे जवाब में। विश्वास का घाटा देखिए कि बिजली बोर्ड का संयुक्त मोर्चा आक्रामक न हो, इसलिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की जा रही है। जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सांसद दिल्ली में प्रदेश के लिए राहत मांग रहे हों, वहां ऐसी बयानबाजी अश्लीलता नहीं तो क्या है।

अच्छा है कि सरकारी नौकरियों में अनुबंध काल समाप्त हो गया, लेकिन अध्यापक पात्रता परीक्षा और कमीशन की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एक और परीक्षा भी मुंह बाए खड़ी होगी, ऐसा अधिसूचना बताती है। उधर मुख्यमंत्री कहते हैं कि परीक्षा नहीं देनी होगी।

इस विमर्श में अच्छा यह है कि मुख्यमंत्री ने सरकारी भवन नदी नालों से 150 मीटर दूर बनाना सुनिश्चित करने को कहा है। दरअसल, धर्मपुर में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में ही मलबा घुस गया था। मुख्यमंत्री ने सेफ्टी आडिट की बात भी कही है। एक प्राथमिकता यह भी हो कि विकास का माडल कंक्रीट या ठेकेदार केंद्रित न हो। कोई तो कारण है कि बरसात का दुष्प्रभाव वहां अधिक हुआ जहां विकास 'अति' की ओर गया था। प्रदेश बचेगा तो ही राजनीति, भाजपा-कांग्रेस, समाज बचेगा...।

****

हुंडई का शुद्ध लाभ जून तिमाही में आठ प्रतिशत घटा

नई दिल्ली : वाहन कंपनी हुंडई मोटर इंडिया का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में आठ प्रतिशत घटकर 1,369 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी ने कहा कि बिक्री घटने से उसका मुनाफा भी कम हुआ है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में वाहन कंपनी का शुद्ध लाभ 1,490 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उसकी कुल आमदनी समीक्षाधीन तिमाही में घटकर 16,628 करोड़ रुपये रह गई। (प्रेट्र)

मैं नेस्ले में एक बहुत ही मुश्किल दौर में आया था। शायद यह अस्तित्व का संकट था। यह उन परिस्थितियों में से एक थी जब भारत के व्यापार जगत में मैगी सभी खबरों के केंद्र में थी।
— सुरेश नारायणन, सीएमडी, नेस्ले

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना प्रति दस ग्राम	चांदी प्रति किलोग्राम	डालर	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल
81,481.86 ▲ 143.91	24,855.05 ▲ 33.95	₹ 98,520 ▲ ₹700	₹1,14,000 ▲ ₹1,000	₹87.80 ▲ ₹0.89	$ 72.19

एक नजर में

एनएसई पर निवेशक ट्रेडिंग खातों की संख्या 23 करोड़

नई दिल्ली : नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया (एनएसई) ने जुलाई में 23 करोड़ निवेशक ट्रेडिंग खातों का आंकड़ा पार कर लिया। एक करोड़ खातों में वृद्धि पिछले तीन महीनों में हुई। महाराष्ट्र 17 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ चार करोड़ निवेशक खातों के साथ सबसे आगे है, इसके बाद यूपी (2.5 करोड़, 11 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ), गुजरात (दो करोड़ से अधिक), और बंगाल और राजस्थान (प्रत्येक 1.3 करोड़ से अधिक) का स्थान है। (प्रेट्र)

माइक्रोसाफ्ट ने नायरा की सेवाएं बहाल कीं

नई दिल्ली : माइक्रोसाफ्ट ने रूस की पेट्रोलियम कंपनी रोसनेफ्ट समर्थित नायरा एनर्जी की ई-मेल सहित सभी सेवाएं बहाल कर दी हैं। इसके बाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने माइक्रोसाफ्ट द्वारा उठाए गए कदमों के खिलाफ दायर मुकदमे का निपटारा नायरा एनर्जी के पक्ष में कर दिया। माइक्रोसाफ्ट ने यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के बाद नायरा एनर्जी को सेवाएं देना बंद कर दिया था। यूरोपीय संघ ने इस महीने की शुरुआत में यूक्रेन के साथ युद्ध को लेकर रूस के खिलाफ नए उपायों के तहत नायरा पर प्रतिबंध लगाए थे। (प्रेट्र)

इंडिगो का शुद्ध लाभ 20% घट 2,176.3 करोड़ हुआ

नई दिल्ली : देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो का अप्रैल-जून तिमाही में शुद्ध लाभ 20 प्रतिशत घटकर 2,176.3 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी को पिछले साल इसी तिमाही में 2,728.8 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ था। इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने कहा, 'भू-राजनीतिक तनाव, हवाई क्षेत्र प्रतिबंध और भारतीय विमानन क्षेत्र में दुखद दुर्घटना से कंपनी को चुनौतीपूर्ण माहौल का सामना करना पड़ा।' यात्रियों संख्या में सालाना आधार पर 12 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हुई है। (प्रेट्र)

अमेरिकी इकोनमी तीन प्रतिशत की दर से बढ़ी

वाशिंगटन : पहली तिमाही में आई गिरावट से उबरते हुए अमेरिकी अर्थव्यवस्था अप्रैल से जून में तीन प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ी। सकल घरेलू उत्पाद जनवरी से मार्च के दौरान 0.5 प्रतिशत की गिरावट के बाद फिर से बढ़ गया। पहली तिमाही में गिरावट मुख्य रूप से आयात में वृद्धि से हुई थी। इसका बड़ा कारण यह था कि ट्रंप के टैरिफ एलान के प्रभावी होने से बड़े पैमाने पर वस्तुओं का आयात किया गया। अर्थशास्त्रियों ने दूसरी तिमाही में दो प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद लगाई थी। (एपी)

वर्ष 2025 में बिजली की मांग चार प्रतिशत बढ़ेगी

नई दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आइईए) ने कहा है कि 2025 में भारत की बिजली की मांग में चार प्रतिशत की मामूली वृद्धि होने की उम्मीद है। बिजली पर अपने अर्धवार्षिक अपडेट में आइईए ने कहा कि वैश्विक बिजली की मांग 2025-2026 की अवधि के पूर्वानुमान की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। हालांकि, चीन और भारत में बिजली की मांग 2025 में 2024 में देखी गई तीव्र वृद्धि की तुलना में अधिक धीमी गति से बढ़ने की उम्मीद है। (प्रेट्र)

ट्रंप के टैरिफ एलान से भारतीय निर्यात को लगेगा झटका

यूरोपीय यूनियन, वियतनाम, जापान व ब्रिटेन जैसे देशों से अधिक शुल्क भारत पर, अब अमेरिका के साथ द्विपक्षीय समझौते पर है सबकी नजर

राजीव कुमार • जागरण

नई दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत की उम्मीद के विपरीत 25 प्रतिशत शुल्क लगाने का एलान कर दिया। ट्रंप के पूर्व के रवैये को देखते हुए 25 प्रतिशत का शुल्क कायम रहने की संभावना कम दिख रही है, लेकिन अगर यह शुल्क जारी रहा तो भारतीय वस्तु निर्यात के लिए निश्चित रूप से झटका होगा। भारत सालाना 440 अरब डालर का वस्तु व्यापार करता है और इनमें 90 अरब डालर का निर्यात अकेले अमेरिका के बाजार में होता है। टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, जेम्स व ज्वैलरी, इलेक्ट्रानिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे रोजगारपरक सेक्टर का 22 प्रतिशत निर्यात अमेरिका में होता है।

अब 25 प्रतिशत के शुल्क लगने के बाद भारतीय वस्तुएं अमेरिका के बाजार में वियतनाम, इंडोनेशिया, यूरोपीय यूनियन, जापान जैसे देशों की वस्तुओं के मुकाबले अधिक महंगी हो जाएंगी और उनकी बिक्री प्रभावित होगी। क्योंकि इन देशों पर अमेरिका ने भारत के मुकाबले कम शुल्क लगाया है।

चीन पर अमेरिका ने फिलहाल 30 प्रतिशत का शुल्क लगा रखा है, इस हिसाब से चीन और भारत के बीच शुल्क का अंतर काफी कम रह जाएगा। चीन काफी बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है, इसलिए चीन की लागत भारत के मुकाबले कम होती है। ऐसे में भारत अमेरिका के बाजार में चीन से भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। सिर्फ बांग्लादेश के मुकाबले भारत पर कम टैक्स लगा है, लेकिन बांग्लादेश के साथ सिर्फ टेक्सटाइल और फुटवियर में भारत का मुकाबला है। यूरोपीय यूनियन और जापान पर ट्रंप ने 15-15 प्रतिशत, इंडोनेशिया पर 19 प्रतिशत, वियतनाम पर 20 प्रतिशत तो बांग्लादेश पर 35 प्रतिशत का शुल्क लगाया है।

टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, जेम्स व ज्वेलरी, इलेक्ट्रानिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे रोजगारपरक सेक्टर का 22 प्रतिशत निर्यात अमेरिका में होता

440 अरब डालर का वस्तु व्यापार करता है भारत सालाना

90 अरब डालर का निर्यात अकेले अमेरिकी बाजार में होता है

हम अमेरिका में सबसे अधिक निर्यात करते हैं और 25 प्रतिशत के शुल्क की घोषणा निश्चित रूप से भारत के लिए झटका है। इससे हमारा निर्यात आज की तारीख में प्रभावित होता दिख रहा है। हालांकि, हमें उम्मीद है कि सरकार कोई न कोई रास्ता निकाल लेगी।
-आरके जालान, चेयरमैन, काउंसिल आफ लेदर एक्सपोर्ट

द्विपक्षीय व्यापार समझौते के बाद 25 प्रतिशत के इस शुल्क का कोई मायने नहीं रह जाएगा और कई वस्तुओं पर काफी कम शुल्क हो जाएगी।
-अजय सहाय, प्रेसिडेंट, फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशंस

अभी है सिर्फ 10 प्रतिशत का शुल्क

दो अप्रैल को अमेरिका ने भारत पर 26 प्रतिशत के पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जिसे गत आठ अप्रैल को 90 दिनों के लिए टाल दिया गया था, फिर उसकी एक अवधि एक अगस्त तक के लिए टाल दी गई। तब भारत पर सिर्फ 10 प्रतिशत का शुल्क लगाया गया जो फिलहाल जारी है। ऐसे में, गारमेंट, लेदर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, जेम्स व ज्वैलरी, फार्मा जैसे आइटम का चीन को मिलने वाला आर्डर भारत की ओर शिफ्ट हो रहा था। अप्रैल से लेकर जून तक में भारत से अमेरिका होने वाले निर्यात में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 20 प्रतिशत से अधिक का इजाफा हुआ। अब यह प्रभावित होगा। इलेक्ट्रानिक्स सामान के निर्यात में वियतनाम भी भारत को टक्कर देता है।

भारत को है शुल्क में बदलाव की उम्मीद

ट्रंप ने हाल ही में यूरोपीय यूनियन और जापान पर पहले 30 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की, लेकिन दोनों देशों की तरफ से इस शुल्क पर आपत्ति जाहिर करने के बाद फिर से वार्ता हुई और शुल्क को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया। वैसे ही वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ किया गया। इसलिए उम्मीद है कि भारतीय नेतृत्व की पहल पर इसका कोई न कोई हल निकल आएगा।

एपल जैसी कंपनियां होंगी प्रभावित

25 प्रतिशत का शुल्क लगने से एपल जैसी कंपनियां प्रभावित होंगी, क्योंकि एपल इन दिनों भारत से ही सबसे अधिक स्मार्टफोन का निर्यात अमेरिका में कर रही है। चीन पर अधिक शुल्क लगने के बाद यह निर्यात काफी तेजी से बढ़ा है। अब एपल जैसी कंपनियां भारत में उत्पादन विस्तार को लेकर पुनर्विचार करेंगी।

अब आगे क्या

सरकार की पूरी कोशिश होगी कि बीटीए के तहत भारतीय वस्तुओं पर शुल्क में राहत के लिए अमेरिका तैयार हो जाए। सितंबर में बीटीए होता है तो सिर्फ एक माह के लिए भारतीय निर्यात प्रभावित होगा।

द्विपक्षीय समझौते से भारत को काफी उम्मीद

माना जा रहा है कि सितंबर में बीटीए के पहले चरण को पूरा कर लिया जाएगा और तब कई सारी वस्तुओं पर शुल्क समाप्त होने या काफी कम हो जाने की उम्मीद है। 25 अगस्त को बीटीए पर वार्ता के लिए अमेरिका के वार्ताकार भारत आ रहे हैं।

किसानों के हितों से समझौता नहीं करना पड़ा भारी

राजीव कुमार • जागरण

- भारत पर लगातार कृषि उत्पाद और डेरी के निर्यात के लिए शुल्क में राहत देने का दबाव बना रहा था अमेरिका
- भारत आटोमोबाइल, वाइन और अन्य वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क में अमेरिका को राहत देने के लिए तैयार

नई दिल्ली : डेरी और कृषि उत्पाद के बाजार को अमेरिका के लिए नहीं खोलना भारत पर भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि अमेरिका भारत पर लगातार कृषि उत्पाद और डेरी के निर्यात के लिए शुल्क में राहत देने का दबाव दे रहा था, जिसे भारत ने साफ तौर पर मना कर दिया है। अमेरिका अपने जेनेटिकलि मोडिफाइड सोयाबीन और मक्का जैसे कृषि उत्पाद के लिए भारत का दरवाजा खुलवाना चाहता था।

भारत आटोमोबाइल, वाइन और अन्य वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क में अमेरिका को राहत देने के लिए तैयार है, लेकिन कृषि प्रधान देश होने के नाते कृषि उपज में अमेरिकी वस्तुओं पर लगने वाले भारी शुल्क में रियायत नहीं देना चाहता है। अभी कृषि वस्तुओं पर भारत ने 40-136 प्रतिशत तक का शुल्क लगा रखा है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने दोहराया है कि राष्ट्रहित से भारत कोई समझौता नहीं करेगा।

ट्रंप के दबाव में नहीं आने का फैसला भारत के लिए सही

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रंप एकतरफा समझौता करना चाहते हैं। भारत समझौते से बाहर नहीं आया है, लेकिन 70 करोड़ किसानों के हित को देखते हुए दबाव में नहीं आने का फैसला किया, जो भारत के लिए एक सफलता है। यूरोपीय यूनियन और जापान जैसे देशों ने शुल्क में कमी कराने के लिए अपने कृषि बाजार को अमेरिका के लिए पूरी तरह से शुल्क मुक्त कर दिया है। वहीं इन देशों ने अमेरिका में 500 अरब डालर से अधिक के निवेश का भी वादा किया।

शुल्क मुक्त तरीके से बाजार का विस्तार कर रहा भारत

भारत ने ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौता कर लिया है और जल्द ही यूरोपीय यूनियन, न्यूजीलैंड, पेरू, ओमान जैसे देशों के साथ भारत व्यापार समझौते की घोषणा कर सकता है। ऐसे में भारत शुल्क मुक्त तरीके से अपने बाजार का लगातार विस्तार कर रहा है। इससे अमेरिका पर भी दबाव बन सकता है। वैसे भी भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और हर साल भारत की विकास दर सबसे अधिक चल रही है। तभी वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल पिछले कुछ दिनों से लगातार यह कह रहे थे कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करेगा, लेकिन राष्ट्रहित पर नहीं।

घरेलू बाजार का बड़ा आकार टैरिफ वृद्धि से बचाएगा

ट्रंप ने भले ही भारत पर टैरिफ का एलान कर दिया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मार्गन स्टेनली ने एक रिपोर्ट में कहा था कि टैरिफ की धमकी से उत्पन्न अनिश्चितता के बीच भारत बेहतर स्थिति में है। इसकी वजह यह है कि उसका वस्तु निर्यात-जीडीपी अनुपात कम है। वहीं फिच ने कहा है कि भारत का घरेलू आकार इतना बड़ा है कि उस पर शुल्क वृद्धि का असर नहीं पड़ेगा। एसबीआइ रिसर्च के अनुसार, अमेरिका को भारत का निर्यात उसके जीडीपी का केवल चार प्रतिशत है, इसलिए भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ में वृद्धि का सीधा प्रभाव सीमित होगा। वित्त वर्ष 2023 से अमेरिका को भारत का निर्यात घट रहा है और कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 17-18 प्रतिशत है। अमेरिका को निर्यात की जाने वाली शीर्ष 15 वस्तुओं का निर्यात में 63 प्रतिशत हिस्सा है।

ट्रंप को चुभ रहा है 44 अरब डालर का व्यापार घाटा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैरिफ और पेनल्टी का एलान किया है। ये टैरिफ 1 अगस्त यानी शुक्रवार से लागू होंगे। आइये जानते हैं भारत अमेरिका को किन उत्पादों का निर्यात करता है और भारत के साथ व्यापार में अमेरिका का घाटा कितना है।

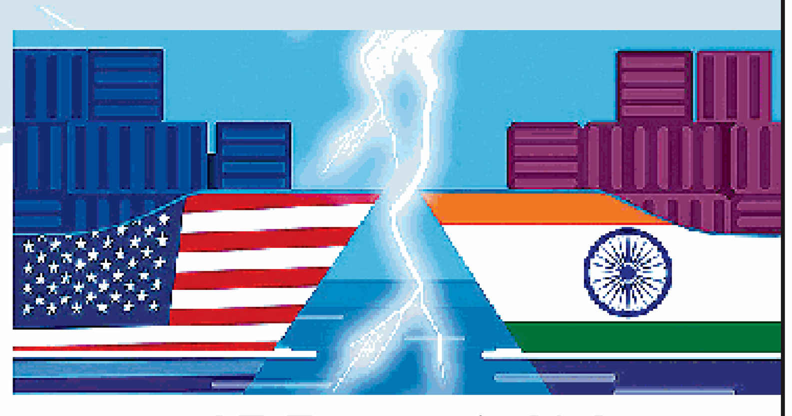

85.5 अरब डालर भारत का अमेरिका को कुल निर्यात

41.4 अरब डालर अमेरिका से भारत का कुल आयात

भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार

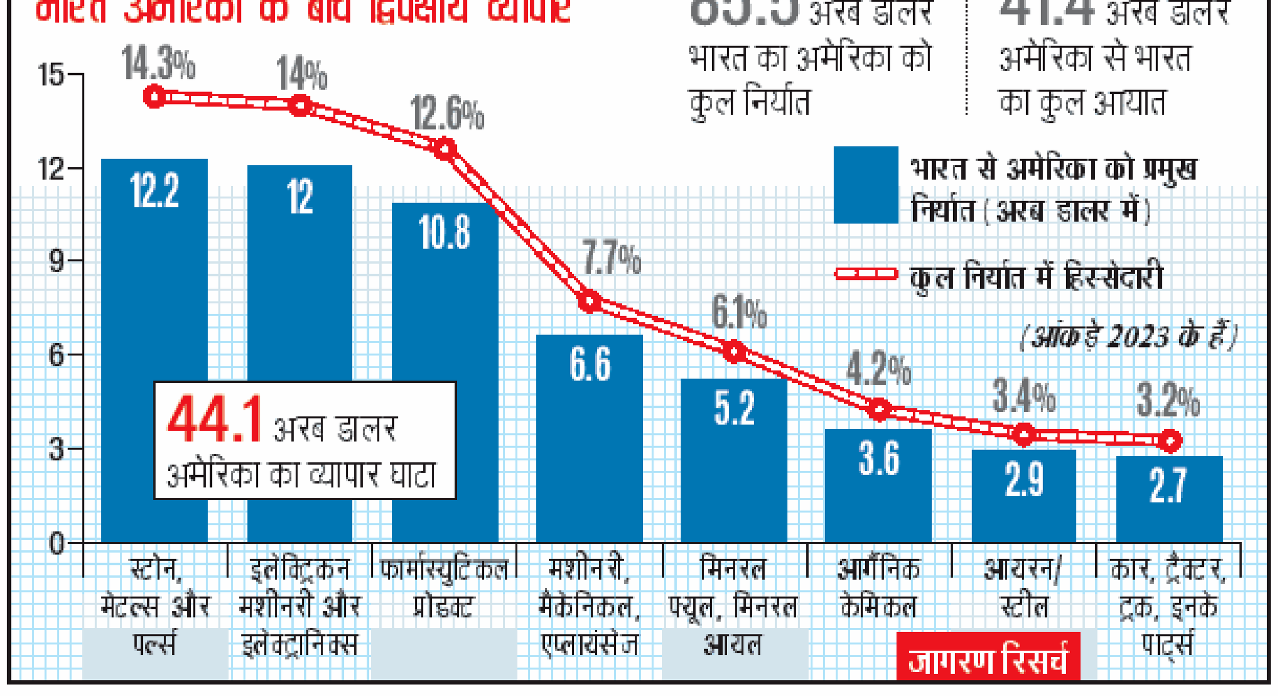

उत्पाद	निर्यात (अरब डालर)	कुल निर्यात में हिस्सेदारी
स्टोन, मेटल्स और पर्ल्स	12.2	14.3%
इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इलेक्ट्रानिक्स	12	14%
फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट	10.8	12.6%
मशीनरी, मैकेनिकल, एप्लायंसेज	6.6	7.7%
मिनरल फ्यूल, मिनरल आयल	5.2	6.1%
आर्गेनिक केमिकल	3.6	4.2%
आयरन/स्टील	2.9	3.4%
कार, ट्रैक्टर, ट्रक, इनके पार्ट्स	2.7	3.2%

वीडियो काल पर विशेषज्ञ से पूछकर खरीद सकेंगे एपल के उत्पाद

नई दिल्ली, प्रेट्र : आनलाइन खरीदारी करने वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आइफोन निर्माता कंपनी एपल ने बुधवार को ग्राहकों के लिए एक नई सेवा का एलान किया। यह सेवा ग्राहकों को व्यक्तिगत सलाह के लिए एक एपल विशेषज्ञ से वीडियो काल पर जुड़ने और उत्पाद खरीदते समय माडलों की तुलना करने में मदद करेगी।

भारत दूसरा ऐसा देश है, जहां पर यह सेवा शुरू की गई है। इस साल की शुरुआत में कंपनी ने भारत में ब्राउजिंग, खरीदारी और सहायता अनुभव के लिए एपल स्टोर एप लांच किया था। अंग्रेजी में उपलब्ध यह सेवा आइओएस और गैर आइओएस उपकरणों पर सहायता करेगी। कंपनी ने कहा, 'यह सेवा ग्राहकों को एक सुरक्षित और वन-वे वीडियो काल के माध्यम से एपल स्टोर टीम के सदस्यों से जोड़ती है ताकि वे आइफोन 16 सहित भविष्य में आने वाले एपल उत्पादों को ब्राउज कर सकेंगे।'

रुपये में तीन साल में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट, 89 पैसे टूटा

87.80 प्रति डालर के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ, यह गिरावट ट्रंप के 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा के बाद आई

मुंबई, प्रेट्र : बुधवार को डालर के मुकाबले रुपया 89 पैसे औंधे मुंह लुढ़ककर तीन साल से अधिक समय में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट के साथ 87.80 प्रति डालर के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ। यह गिरावट, अमेरिका द्वारा एक अगस्त की समयसीमा से पहले व्यापार समझौते के अभाव में भारतीय आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा के बाद आई है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि आयातकों की ओर से मासान्त की डालर मांग और विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी ने भी रुपये पर भारी दबाव डाला।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, डालर के मुकाबले 87.10 पर खुला। कारोबार के दौरान यह डॉलर के मुकाबले 87.05 के निचले स्तर पर पहुंचा। अंत में यह 87.80 प्रति डालर के अब तक के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव से 89 पैसे की बड़ी गिरावट है।

यह 24 फरवरी, 2022 के बाद से रुपये की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट थी, जब डालर के मुकाबले रुपये में 99 पैसे की गिरावट आई थी। रुपया मंगलवार को चार महीने से भी अधिक के निचले स्तर पर आ गया था। यह 21 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86.91 पर बंद हुआ था।

मिराए एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा, 'भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता के बीच हमें रुपये में और गिरावट की आशंका है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और विदेशी पूंजी की निकासी भी रुपये को दबाव में रख सकती है।'

देश में स्मार्टफोन की बिक्री जून तिमाही में आठ प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत का स्मार्टफोन बाजार अप्रैल-जून, 2025 तिमाही में मात्रा के लिहाज से सालाना आधार पर आठ प्रतिशत बढ़ा और थोक मूल्य के लिहाज से 18 प्रतिशत बढ़ा। इस दौरान एपल का आइफोन 16 माडल की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की गई। नए फोन माडल की पेशकश में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी, आक्रामक रणनीतियों और आकर्षक छूट से बिक्री को तेजी मिली।

काउंटरपाइंट के मुताबिक, मात्रा के लिहाज से वीवो 20 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर रहा जबकि सैमसंग (16 प्रतिशत), ओप्पो (13 प्रतिशत), रियलमी (10 प्रतिशत) और शाओमी (आठ प्रतिशत) उसके पीछे रहे। बिक्री मूल्य के लिहाज से सैमसंग और एपल ने 23-23 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ अग्रणी स्थान बनाया। इनके बाद वीवो (15 प्रतिशत), ओप्पो (10 प्रतिशत), रियलमी (छह प्रतिशत) और वनप्लस (चार प्रतिशत) रहे।

फार्च्यून 500 में रिलायंस का दबदबा कायम

- सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी के तौर पर अपना स्थान पिछले वर्ष की तरह बरकरार रखा
- सूची में भारत की नौ कंपनियां, शामिल, इसमें पांच सार्वजनिक और चार निजी क्षेत्र की

नई दिल्ली, प्रेट्र : अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2025 फार्च्यून ग्लोबल 500 सूची में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी के तौर पर अपना स्थान बरकरार रखा है। तेल से लेकर दूरसंचार और खुदरा क्षेत्र में काम करने वाली इस कंपनी को सूची में 88वें स्थान पर रखा गया है। हालांकि, 2024 में कंपनी 86वें स्थान पर थी। कंपनी ने पिछले चार सालों में 2021 के 155वें स्थान से 67 स्थानों की छलांग लगाई है। लगातार 22 सालों से रिलायंस ने प्रतिष्ठित फार्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में अपनी जगह कायम रखी हुई है।

वालमार्ट शीर्ष रैंक पाने वाली कंपनी बनी हुई है। उसके बाद एमेजोन का स्थान है। शीर्ष 10 में तीन चीनी कंपनियां हैं, जिसमें स्टेट ग्रिड तीसरे स्थान पर, चाइना नेशनल पेट्रोल पांचवें स्थान पर और तेल एवं गैस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी सिनोपेक ग्रुप छठे स्थान पर है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल निर्यातक कंपनी सऊदी अरामको चौथे और एपल आठवें स्थान पर है। फार्च्यून ग्लोबल 500 सूची 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले समाप्त हुए वित्त वर्षों के लिए कुल राजस्व के आधार पर कंपनियों को रैंक करती है।

एलआइसी पिछले साल की तरह 95वें स्थान पर बरकरार

इस साल फार्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में भारत की नौ कंपनियां शामिल हैं। इसमें पांच सार्वजनिक और चार निजी क्षेत्र की हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) पिछले साल की तरह 95वें स्थान पर है। इंडियन आयल कारपोरेशन (आइओसी) 2025 की रैंकिंग में 11 स्थान नीचे खिसककर 127वें स्थान पर आ गई है। देश का सबसे बड़ा ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) 15 स्थान ऊपर चढ़कर 163वें स्थान पर आ गया है, जबकि एचडीएफसी बैंक 48 स्थान ऊपर चढ़कर 258वें स्थान पर आ गया है। ओएनजीसी एक स्थान नीचे खिसककर 181वें स्थान पर आ गया है। सूची में शामिल अन्य भारतीय कंपनियों में टाटा मोटर्स 283वें स्थान पर (2024 से 12 स्थान नीचे), बीपीसीएल 285वें स्थान पर (27 स्थान नीचे) और आइसीआइसीआइ बैंक 464वें स्थान पर अपरिवर्तित हैं।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

राष्ट्रीय फलक

हजारों घर खरीदारों ने राहत पाने के लिए खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

प्रथम पृष्ठ से आगे

पीठ ने एजेंसी को विभिन्न बिल्डरों और बैंकों के खिलाफ छह प्रारंभिक जांचों को आगे बढ़ाने के लिए 22 नियमित मामलों में बदलने की अनुमति दी थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिल्डरों द्वारा ठगे गए तथा वित्तीय संस्थानों की कार्रवाइयों से पीड़ित हजारों घर खरीदारों ने राहत पाने के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

सीबीआइ ने कहा कि इस सिलसिले में एजेंसी ने 22 मामले दर्ज किए हैं और दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद आदि में 47 स्थानों पर छापेमारी की है। इस दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और कुछ डिजिटल इलेक्ट्रानिक साक्ष्य जब्त किए गए हैं। यह मामला बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा घर खरीदारों के लिए एक आर्थिक सहायता योजना पर केंद्रित है। इसके तहत स्वीकृत ऋण राशि सीधे डेवलपर को वितरित की जाती थी, जो खरीदारों को फ्लैट का कब्जा मिलने तक ईएमआइ का भुगतान करते के लिए बाध्य थे। लेकिन, डेवलपर द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किए जाने के चलते बैंकों ने खरीदारों से भुगतान की मांग शुरू कर दी।

धोखाधड़ी की गंभीरता को पहचानने में सीबीआइ की तत्परता की सराहना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजेंसी ने अपनी जांच के तहत एक हजार से अधिक व्यक्तियों से पूछताछ की और 58 परियोजना स्थलों का दौरा किया। शीर्ष अदालत ने उल्लेख किया कि सीबीआइ द्वारा दर्ज की गई सातवीं प्रारंभिक जांच सुपरटेक लिमिटेड को छोड़कर अन्य बिल्डरों की परियोजनाओं पर है। ये परियोजनाएं एनसीआर से बाहर मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मोहाली और इलाहाबाद में हैं और अभी चल रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट 1,200 से अधिक घर खरीदारों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने एनसीआर में सब्सिडी योजनाओं के तहत फ्लैट बुक किए थे। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि फ्लैटों का कब्जा नहीं मिलने के बावजूद वित्तीय संस्थान उन्हें ईएमआइ चुकाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

टाटा मोटर्स 38 हजार करोड़ में इटली की ट्रक बनाने वाली कंपनी को खरीदेगी

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक टाटा मोटर्स अब तक की अपनी सबसे बड़ी डील करने जा रही है। टाटा मोटर्स 3.8 अरब यूरोप (38,240 करोड़ रुपये) में इटली की ट्रक बनाने वाली कंपनी इवेको को खरीदने जा रही है। इवेको एग्नेली ग्रुप की कंपनी है। इससे पहले टाटा मोटर्स ने साल 2008 में जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) का अधिग्रहण किया था। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि बोर्ड की कार्यकारी समिति ने सभी नियामकीय, वैधानिक और अन्य सभी आवश्यक स्वीकृतियों के अधीन, पूर्ण नकद स्वैच्छिक निविदा प्रस्ताव (रक्षा व्यवसाय को छोड़कर) के माध्यम से इवेको ग्रुप एनवी के 100 प्रतिशत सामान्य शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।

****

आइआइटी मद्रास ने विकसित किया स्वदेशी ईवी चार्जिंग प्लेटफार्म

यह प्रत्येक चार्जर स्टेशन को कई नेटवर्क पर प्रदर्शित कर उसकी दृश्यता को बढ़ाता है

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मद्रास के स्टार्टअप फर्म प्लगजमार्ट ने एक स्वदेशी ईवी चार्जिंग प्लेटफार्म विकसित किया है, जो चार्जर को कई चार्जिंग मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस) नेटवर्क से जोड़ने की सुविधा देता है।

अपनी तरह का पहला रिले ईवी चार्जर को एक साथ कई सीएमएस से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि चार्जर अब किसी एक एप या नेटवर्क तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे कई प्लेटफार्म से रीयल टाइम में एक्सेस किया जा सकता है। वर्तमान में अधिकांश ईवी चार्जर एक सीएमएस से जुड़े हुए हैं, जिससे उस विशिष्ट ब्रांड के ग्राहकों के लिए चार्जर का उपयोग सीमित हो जाता है। यह प्लेटफार्म एक बीच का समाधान पेश कर इस बंधन से मुक्ति दिलाता है और एक ही चार्जर के लिए कई सीएमस कनेक्शन को सक्षम बनाता है।

प्लगजमार्ट के साफ्टवेयर बिजनेस यूनिट के निदेशक राघवेंद्र टीएस ने कहा कि ईवी अपनाने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक सार्वजनिक प्लेटफार्म पर चार्जर्स की सीमित उपलब्धता है। हमारा समाधान प्रत्येक स्थापित चार्जर को कई नेटवर्क पर प्रदर्शित कर उसकी दृश्यता को अधिकतम करता है। इससे जहां चार्जर का उपयोग बढ़ता है वहीं, ईवी उपयोगकर्ताओं को अधिक विकल्प मिलते हैं।

बदायूं में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष की हत्या

जागरण संवाददाता, बदायूं : भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र गुप्ता की मंगलवार रात डंडे से पीटकर व धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। रात में वह गांव में स्थित पानी की टंकी पर रखवाली करने जा रहे थे। अभी तक हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।

58 वर्षीय सुरेश चंद्र गुप्ता भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष के साथ ही भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) में जिला महासचिव भी थे। सुरेश चंद्र गुप्ता रात करीब 11 बजे पानी की टंकी पर रखवाली के लिए घर से निकले थे। छोटे भाई उमेश चंद्र गुप्ता की चाय की दुकान उनके घर के नजदीक है। वहां भी 10-15 मिनट बैठे थे। इसके बाद टंकी की ओर चले गए। स्वजन ने सोचा कि वह टंकी पर सो गए हैं। बुधवार सुबह लोग जागे तो उनका शव टंकी के गेट पर पड़ा देखा।

30 प्रतिशत कर अमेरिका वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप चीनी वस्तुओं पर लगाएगा, वहीं चीन अमेरिकी उत्पादों पर 10 प्रतिशत शुल्क वसूलने पर सहमति बनी है। चीन और अमेरिका फिलहाल एक-दूसरे पर टैरिफ नहीं बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं।

रूस में 8.8 तीव्रता का भूकंप, अमेरिका तक सुनामी

कामचटका प्रायद्वीप में करीब तीन मिनट तक हिलती रही धरती, सुनामी के असर से समुद्र से उठीं 10 मीटर ऊंची लहरें

लहरों से बंदरगाह और तटवर्ती क्षेत्रों को भारी नुकसान

- जापान के फुकुशीमा में परमाणु संयंत्र खाली कराए गए
- प्रशांत क्षेत्र के ज्यादातर देशों में सुनामी का दिखा असर

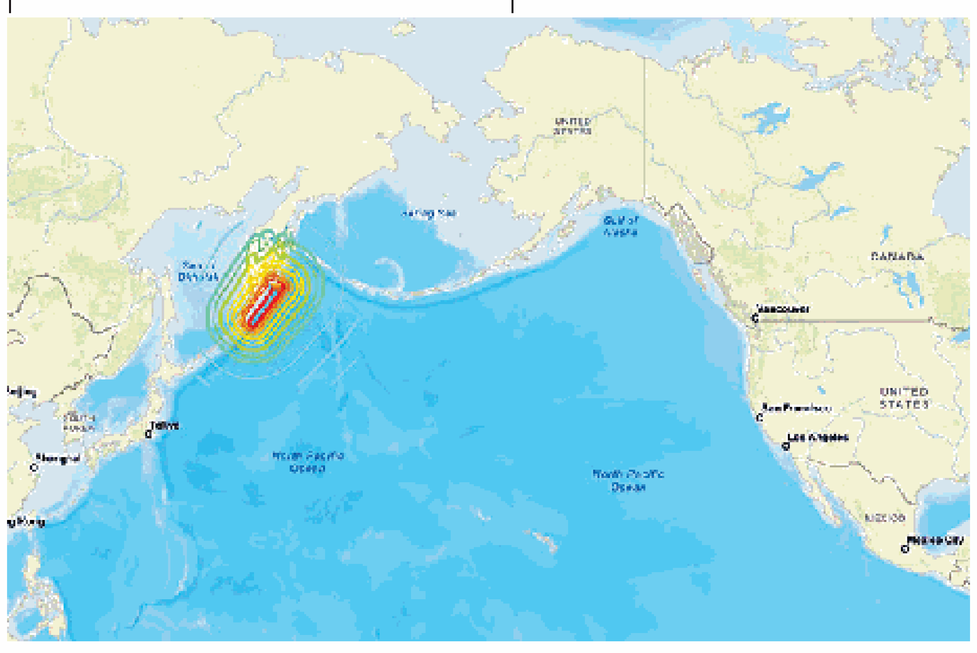
रूस में बुधवार को आए भूकंप का केंद्र। एएफपी

रूस में बुधवार को भूकंप के दौरान पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की में क्षतिग्रस्त एक स्कूल। एएफपी

रिंग आफ फायर : यहां आते हैं दुनिया के सबसे तगड़े भूकंप

रिंग आफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर का भौगोलिक क्षेत्र है, जो भूकंप व ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यह करीब 40 हजार किमी लंबा है। इसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, रूस, जापान, न्यूजीलैंड, चिली, पेरू, मेक्सिको और अमेरिका (अलास्का और कैलिफोर्निया) जैसे कई देश शामिल हैं। यह क्षेत्र कई टेक्टोनिक प्लेटों (जैसे प्रशांत प्लेट, नाजका प्लेट और फिलीपींस प्लेट) के मिलन स्थल पर है। दुनिया के 90 प्रतिशत भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं।

मास्को, रायटर : रूस के पूर्व में स्थित कामचटका प्रायद्वीप पर बुधवार सुबह 8.8 की तीव्रता वाला भूकंप आया। भूकंप के झटकों से कामचटका और उसके आसपास कुरील द्वीप समूह के भूभाग हिल गए। विश्व में आए सबसे तीव्र भूकंपों में शुमार इस दैवीय आपदा से भारी नुकसान और तमाम लोगों के घायल होने की सूचना है। इसके असर से प्रायद्वीप के समुद्र तटों से 10 मीटर (32 फीट) तक ऊंची सुनामी की लहरें टकराईं जिससे तटीय इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। भूकंप के बाद सुनामी के खतरे से जापान, चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, अमेरिका और प्रशांत महासागर के तटवर्ती देशों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत के सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर ने सुनामी से भारत को किसी तरह का खतरा न होने की बात कही है।

इससे पहले 2011 में नजदीक स्थित जापान में 9.0 तीव्रता का भूकंप आया था जिसमें फुकुशीमा परमाणु हादसा हुआ था। बुधवार को सतर्कता बरतते हुए सुनामी का अलर्ट जारी होते ही फुकुशीमा दाइची और दाइनी परमाणु संयंत्रों से लोगों को हटा दिया गया। दोनों ही संयंत्रों में बड़ी मात्रा में परमाणु मलबे का भंडार है। होकाइडो द्वीप का तटवर्ती इलाका भी खाली करा लिया गया है। भूकंप से प्रभावित रूसी प्रायद्वीप के पेत्रोपावलोव्स्क-कामचाटस्की शहर के लोगों के अनुसार भूकंप के झटकों से धरती कई मिनट तक हिलती रही, इससे घबराकर लोग घरों और कार्यस्थलों के बाहर आ गए। 1,65,000 की आबादी वाले इस शहर में करीब तीन मिनट तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके साथ समुद्र से उठी सुनामी की लहरों से तटवर्ती इलाकों में कामचटका बंदरगाह, फिश प्रोसेसिंग प्लांट और लंगर डाले जहाजों को नुकसान हुआ है। सुनामी के चलते तटवर्ती इलाकों में पानी भर गया है। इलाकों से लोगों को निकाला गया और स्वास्थ्यकर्मियों के दल भी चिकित्सा में जुट गए हैं। रूस के ओसियानोलाजी इंस्टीट्यूट ने कामचटका के कुछ हिस्सों में समुद्र से उठी 10 मीटर ऊंची लहरें तट से टकराने की जानकारी दी है। जबकि रूसी विज्ञानियों ने बताया है कि क्षेत्र में 1952 के बाद आया यह सबसे तेज भूकंप था। अमेरिका के जियोलाजिकल सर्वे ने बताया है कि भूकंप का केंद्र कामचटका प्रायद्वीप के पेत्रोपावलोव्स्क-कामचाटस्की शहर के पूर्व-दक्षिण भाग में जमीन के 19.3 किलोमीटर गहराई में था।

अमेरिका के हवाई द्वीप में समुद्र से उठी 1.7 मीटर (5.5 फीट) ऊंची लहरें तट से टकराई हैं। प्रशांत क्षेत्र के सुनामी वार्निंग सेंटर ने कुछ घंटों में समुद्र तटीय देशों को सुनामी की चेतावनी दी है लेकिन इसका असर गंभीर न होने की बात भी कही है। बावजूद इसके अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने तटवर्ती इलाकों की इमारतें खाली करा दी हैं और जहाजों को बंदरगाह क्षेत्र से दूर रहने के लिए कहा है। इस चेतावनी के चलते होनोलूलू एयरपोर्ट पर विमानों का आवागमन प्रभावित हुआ है। कैलिफोर्निया, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत और प्रशांत महासागर क्षेत्र के देशों में भी सतर्कता बरती जा रही है। जापान में निसान मोटर कंपनी ने अपने कई कारखानों में काम रोक दिया है। जापान के समुद्र में हाल के घंटों में 1.3 मीटर ऊंची लहरें उठती हुई देखी गई हैं।

इजरायल-फलस्तीन पर भारत ने द्वि-राष्ट्र समाधान के लिए दोहराया समर्थन

- संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश ने 'उद्देश्यपूर्ण संवाद और कूटनीति' का आग्रह किया
- कहा- कागजी समाधानों से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, व्यावहारिक समाधानों को प्राप्त करने का प्रयास हो

पर्वतनेनी हरीश। फाइल

न्यूयार्क, प्रेट्र : संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने इजरायल-फलस्तीन संघर्ष के लिए द्वि-राष्ट्र समाधान की आवश्यकता पर जोर देते हुए दोनों पक्षों को एक साथ लाने हेतु उद्देश्यपूर्ण संवाद और कूटनीति का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि हमें केवल कागजी समाधानों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यावहारिक समाधानों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

बुधवार को न्यूयार्क में "फलस्तीन समस्या का शांतिपूर्ण समाधान और द्वि-राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन" विषय पर आयोजित उच्च-स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में हरीश ने कहा कि मानवीय सहायता राजनीति और संघर्षों से परे है। उन्होंने तत्काल युद्धविराम की वकालत करते हुए कहा कि वैश्विक प्रयासों को अब "उद्देश्यपूर्ण संवाद और कूटनीति" के माध्यम से इजरायल-फलस्तीन संघर्ष के द्वि-राष्ट्र समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। हरीश ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय का मानना है कि द्वि-राष्ट्र समाधान का कोई विकल्प नहीं है। यह सम्मेलन द्वि-राष्ट्र समाधान के माध्यम से शांति प्राप्त करने की दिशा में अब तक तय किए गए मार्ग पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा, "अब हमारे प्रयास इस बात पर केंद्रित होने चाहिए कि उद्देश्यपूर्ण संवाद और कूटनीति के माध्यम से द्वि-राष्ट्र समाधान कैसे लाया जाए और संघर्षरत पक्षों को एक-दूसरे के साथ सीधे संवाद करने के लिए कैसे लाया जाए। समर्थन की प्रतिबद्धता ऐसे कार्रवाई योग्य कदमों के रूप में होनी चाहिए जो द्वि-राष्ट्र समाधान का मार्ग प्रशस्त करें। ऐसे कदमों की पहचान और उनके कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर हमारा सामूहिक ध्यान और प्रयास जरूरी है।" इस तीन दिवसीय (28-30 जुलाई) उच्च-स्तरीय सम्मेलन की सह-अध्यक्षता सऊदी अरब और फ्रांस कर रहे हैं। 'फलस्तीन सवाल के शांतिपूर्ण समाधान और द्वि-राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन पर न्यूयार्क घोषणा' शीर्षक वाले 25-पृष्ठ के परिणाम दस्तावेज में कहा गया कि गाजा में युद्ध अब समाप्त होना चाहिए और हमास को सभी बंधकों को रिहा करना होगा। गाजा में युद्ध समाप्त करने के संदर्भ में हमास को गाजा में शासन समाप्त करना होगा व हथियार फलस्तीनी अधिकारियों को सौंपने होंगे।"

आस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यूट्यूब भी नहीं देख सकेंगे

- आयु प्रतिबंध 10 दिसंबर से प्रभावी होंगे, कदम न उठाने वाले प्लेटफार्म पर लगेगा भारी जुर्माना

प्रतीकात्मक

सिडनी, एपी : आस्ट्रेलियाई सरकार ने घोषणा की है कि यूट्यूब उन इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म में शामिल होगा, जिन्हें दिसंबर से यह सुनिश्चित करना होगा कि यूजर्स की उम्र कम से कम 16 वर्ष हो। यूट्यूब को पिछले साल नवंबर में एक अपवाद के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जब संसद ने दुनिया का पहला ऐसा कानून पारित किया था जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटाक और एक्स जैसे प्लेटफार्म पर प्रतिबंधित कर देंगे।

आयु प्रतिबंध 10 दिसंबर से प्रभावी होंगे और कम उम्र के यूजर्स को बाहर करने के लिए जिम्मेदार कदम उठाने में विफल रहने पर प्लेटफार्म पर पांच करोड़ आस्ट्रेलियाई डालर तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये कदम अभी तक परिभाषित नहीं किए गए हैं। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि बच्चों पर आनलाइन प्लेटफार्मों का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और इंटरनेट मीडिया को उनकी सामाजिक जिम्मेदारी की याद दिलाता हूं। वह चाहते हैं कि आस्ट्रेलियाई माता-पिता जानें कि हम उनके साथ हैं। यूट्यूब का कहना है कि इसे 13 से 15 वर्ष के लगभग तीन-चौथाई आस्ट्रेलियाई उपयोग करते हैं और इसे इंटरनेट मीडिया के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी मुख्य गतिविधि वीडियो होस्ट करना है। यूट्यूब के एक प्रवक्ता ने कहा, "यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफार्म है जिसमें मुफ्त, उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की लाइब्रेरी है। यह इंटरनेट मीडिया नहीं है।"

पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय का 70 साल पुराना मस्जिद ध्वस्त

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला जिले में पुलिस ने अल्पसंख्यक अहमदिया समुदाय के एक 70 साल पुराने मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। जमात-ए-अहमदिया पाकिस्तान (जेएपी) ने कहा, "धार्मिक चरमपंथियों के दबाव में पुलिस ने न केवल 70 साल पुराने मस्जिद के मेहराब को ध्वस्त किया, बल्कि दो अहमदिया कब्रों के पत्थर तोड़कर उन्हें अपवित्र भी किया।"

जेएपी के प्रवक्ता अमीर महमूद ने कार्रवाई की कड़ी निंदा की। प्रवक्ता ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से घटना का संज्ञान लेने और यह तय करने का आह्वान किया कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाने और अहमदिया कब्रों को अपवित्र करने के लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाए। वहीं, एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि अहमदिया समुदाय को मस्जिद के प्रार्थना कक्ष और कब्रों के मकबरों को तोड़ने के लिए कहा गया है, क्योंकि उन पर इस्लामी आयतें खुदी थीं।

पाक को करारा झटका, पहलगाम हमले में टीआरएफ का नाम

जयप्रकाश रंजन ● जागरण

- यूएनएससी की रिपोर्ट में लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन को वारदात के लिए ठहराया गया जिम्मेदार
- रिपोर्ट में कहा गया- लश्कर और टीआरएफ में गहरा जुड़ाव, लश्कर के बिना संभव नहीं था आतंकी हमला

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। फाइल

नई दिल्ली : अमेरिका के बाद अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की एक रिपोर्ट में भी पहलगाम आतंकी हमले के दोषी आतंकी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) की भूमिका का राजफाश किया गया है। यूएनएससी द्वारा आतंकी गतिविधियों की निगरानी करने के लिए गठित एक मानिटरिंग टीम की रिपोर्ट में लश्कर के इस मुखौटा संगठन का उल्लेख किया गया है। यह रिपोर्ट ऐसे वक्त आई है जब यूएनएससी का अस्थाई सदस्य पाकिस्तान इस संगठन की अध्यक्षता कर रहा है।

रिपोर्ट में पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा गया है -' यूएनएससी के एक सदस्य ने टीआरएफ के लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के साथ संबंधों को खारिज किया और कहा कि एलईटी अब निष्क्रिय है।' इस बीच विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि यह एक पंक्ति पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को उजागर करने के लिए पर्याप्त है। इसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने टीआरएफ को अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन घोषित किया था। यूएनएससी 1267 (आइसीआइएस, अलकायदा) प्रतिबंध समिति की इस रिपोर्ट को 21 जुलाई को अंतिम रूप दिया गया और इसे बुधवार को सार्वजनिक किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है - ' 22 अप्रैल को पांच आतंकियों ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक पर्यटक स्थल पर हमला किया, जिसमें 26 नागरिक मारे गए। उसी दिन टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली और हमले के स्थल की एक तस्वीर प्रसारित की। अगले दिन जिम्मेदारी का दावा दोहराया गया, लेकिन 26 अप्रैल को टीआरएफ ने अपनी जिम्मेदारी के दावे को वापस ले लिया। इसके बाद टीआरएफ की ओर से कोई और संचार नहीं हुआ। किसी अन्य समूह ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। क्षेत्रीय स्तर पर तनाव बना हुआ है और आतंकी समूह इन तनावों का फायदा उठा सकते हैं। एक सदस्य देश ने कहा कि यह हमला लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के समर्थन के बिना नहीं हो सकता था और टीआरएफ और एलईटी के बीच संबंध है। एक अन्य सदस्य देश ने कहा कि हमला टीआरएफ ने किया जो लश्कर के समान है। हालांकि, एक सदस्य देश ने इन विचारों को खारिज करते हुए कहा कि एलईटी अब अस्तित्व में नहीं है।'

इस रिपोर्ट में टीआरएफ का उल्लेख सीधे तौर पर पाकिस्तान की कूटनीतिक हार है, खासकर तब जबकि वह यूएनएससी का सदस्य है और इस महीने इस संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि वर्ष 2019 के बाद पहली बार मानिटरिंग समिति की रिपोर्ट में पाकिस्तान के आतंकी संगठन का उल्लेख किया गया है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने संसद में यह दावा किया था कि पहलगाम हमले के बाद यूएनएससी की तरफ से जारी बयान में टीआरएफ का नाम हटाने में उन्हें सफलता मिली है।

भारत की खुफिया एजेंसियों के अनुसार, यूएनएससी रिपोर्ट ने टीआरएफ की आड़ में भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की पाक सेना के मंसूबों को सामने ला दिया है। पाकिस्तान ने सोच-समझकर एलईटी और जैश के आतंकियों को मिलाकर टीआरएफ और पीपुल अगेंस्ट फासिस्ट फ्रंट जैसे नाम वाले संगठनों का गठन किया है। इनका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं को स्थानीय रूप देना है। भारत का विदेश मंत्रालय 2023 से ही टीआरएफ को लेकर वैश्विक बिरादरी को सतर्क कर रहा है। मई 2024 में भारत के अधिकारियों ने यूएनएससी सदस्यों के समक्ष टीआरएफ की गतिविधियों पर जानकारी दी थी।

रूसी मिसाइल ने यूक्रेनी सेना के प्रशिक्षण केंद्र को बनाया निशाना, तीन सैनिक मारे गए

- हालांकि, रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, हमले में 200 यूक्रेनी सैनिक मारे गए या घायल हुए
- चेर्निहिव क्षेत्र में 169वें प्रशिक्षण केंद्र पर दो इस्कंदर मिसाइलों से बोला गया हमला

यूक्रेन के खार्कीव में बुधवार को एक खाद्य गोदाम में रूसी हमले के बाद उठता धुएं का गुबार। रायटर

कीव, एपी : रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए हैं। इस हमले में यूक्रेनी सेना के एक प्रशिक्षण केंद्र पर हमला किया गया, जिसमें तीन सैनिकों की मृत्यु हो गई और 18 अन्य घायल हुए। हालांकि, रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि हमले में 200 यूक्रेनी सैनिक मारे गए या घायल हुए। मंत्रालय ने कहा कि चेर्निहीव क्षेत्र में होन्चारिवस्के के पास यूक्रेन के 169वें प्रशिक्षण केंद्र पर दो इस्कंदर मिसाइलों से हमला बोला गया।

इस बीच, रूस ने यूक्रेनी नागरिक ठिकानों के खिलाफ भी अपने हवाई अभियान को तेज कर दिया है। यूक्रेनी वायु सेना ने बुधवार को कहा कि रात भर के दौरान 78 ड्रोन से हमला बोला गया, जिनमें आठ नए विकसित जेट-संचालित ड्रोन शामिल थे। पांच लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र मिशन का कहना है कि इस वर्ष रूसी हमलों में नागरिक हताहतों की संख्या में वृद्धि हुई है, 2025 की पहली छमाही में 6,754 नागरिक मारे गए या घायल हुए हैं, जो 2024 की इसी अवधि की तुलना में 54 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

रूसी आक्रमण के इस नए चरण ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ा दी है और इससे क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने को लेकर ट्रंप ने फिर दी मास्को को चेतावनी

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने को लेकर एक बार फिर मास्को को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि मास्को यूक्रेन में युद्ध समाप्त नहीं करता है, तो आज से दस दिन बाद रूस पर टैरिफ और अन्य प्रतिबंध लागू करना शुरू कर देंगे। ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में मास्को को चेतावनी दी थी कि अगर रूस 50 दिनों के भीतर शांति समझौते पर सहमत नहीं हुआ तो अमेरिका बेहद कड़े टैरिफ लगाएगा, लेकिन मंगलवार को उन्होंने कहा कि इस समय-सीमा को अब कम कर रहे हैं।

आस्ट्रेलिया में बना पहला राकेट 14 सेकंड की उड़ान के बाद दुर्घटनाग्रस्त

लिंटन, एपी : आस्ट्रेलियाई में निर्मित पहला राकेट बुधवार को 14 सेकंड की उड़ान के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गिल्मर स्पेस टेक्नोलाजीज द्वारा प्रक्षेपित एरिस राकेट आस्ट्रेलिया द्वारा डिजाइन और निर्मित पहला कक्षीय प्रक्षेपण यान था। इसे क्वींसलैंड के बोवेन के पास एक अंतरिक्ष केंद्र से स्थानीय समयानुसार बुधवार सुबह प्रक्षेपित किया गया। यह राकेट 75 फुट लंबा था और छोटे उपग्रहों को कक्षा में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। कंपनी ने फेसबुक पोस्ट में प्रक्षेपण को सफल बताया और कहा कि सभी चार हाइब्रिड-प्रोपेल्ड इंजन प्रज्वलित हुए और पहली उड़ान में 23 सेकंड का इंजन बर्न टाइम और 14 सेकंड की उड़ान शामिल थी।

देश-दुनिया की अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

बांग्लादेश में आगामी चुनाव लड़ेंगी बीएनपी अध्यक्ष और पूर्व पीएम खालिदा जिया

खालिदा जिया। फाइल

ढाका, आइएएनएस : बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के उपाध्यक्ष अब्दुल अवल मिंटू ने बुधवार को घोषणा की कि बीएनपी की अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया आगामी चुनाव लड़ेंगी।

फेनी जिले में एक कार्यक्रम के दौरान उपाध्यक्ष ने कहा, "जिले में चुनावों को लेकर कोई चिंता नहीं है। हमारी नेता खालिदा जिया अब स्वस्थ हैं। वह चुनाव लड़ेंगी। फेनी को लेकर कोई चिंता नहीं है।" बीएनपी की जीत का भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा, "अगर निष्पक्ष चुनाव हुए, तो फेनी में बीएनपी निश्चित रूप से जीतेगी, क्योंकि इस जिले का चुनावी इतिहास काफी चर्चित रहा है। पार्टी ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है।"

उन्होंने कहा, 'देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए चुनाव पहले भी हो सकते हैं। ऐसा भी संभव है कि जनवरी में हो जाए। कार्यवाहक सरकार से संबंधित एक मामला वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अगर न्यायालय कार्यवाहक व्यवस्था को बहाल करने की अनुमति देता है, तो यह अंतरिम सरकार कार्यवाहक सरकार के रूप में कार्य करेगी।

संविधान के अनुसार, कार्यवाहक सरकार के तहत 90 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि बीएनपी को अंतरिम सरकार और पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान के बीच लंदन में हुई बैठक के दौरान बनी सहमति पर भरोसा है।

बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने एक और मुक्ति संग्राम अपराधी की मौत की सजा को पलटा

ढाका, आइएएनएस : बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निष्कासित अवामी लीग के नेता मुबारक हुसैन को युद्ध अपराध के एक मामले में बरी कर दिया। कोर्ट ने देश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा 2014 में दी गई मौत की सजा को पलट दिया। 2014 में मुबारक पर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगाए गए थे।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सात दिन की रिमांड पर भेजा : बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एबीएम खैरुल हक को न्यायिक जालसाजी के आरोपों पर दर्ज मामले में बुधवार को ढाका की कोर्ट ने सात दिन की रिमांड पर भेज दिया है। मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट में दायर याचिका में 10 दिन की रिमांड की मांग की गई थी।

उम्मीद

एजोस्पर्मिया से पीड़ित पुरुषों के लिए उम्मीद की नई किरण बना स्टार सिस्टम, एआइ आधारित स्टार सिस्टम ने वीर्य के सैंपल से खोज निकाले दुर्लभ शुक्राणु

15 बार की नाकामी से मायूस दंपती को एआइ ने दी 'औलाद की सौगात'

जेएनएन, नई दिल्ली

स्पर्म ट्रैक एंड रिकवरी (स्टार) सिस्टम की मदद ली। फाइल

बच्चे दंपति के वैवाहिक जीवन को पूर्ण बनाते हैं। यह बात भारत ही नहीं, उन देशों के लिए भी सही है, जहां परिवार नाम की संस्था उतनी मजबूत नहीं है। अमेरिका में एक दंपति को बच्चे नहीं हो रहे थे। उन्होंने आइवीएफ का सहारा लिया, लेकिन एक के एक बाद 15 बार प्रयास विफल रहा। इस दरम्यान 19 वर्ष बीत गए। हर तरफ से निराश दंपति के जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) एक चमत्कार बन कर आया। डाक्टरों ने स्पर्म ट्रैक एंड रिकवरी (स्टार) सिस्टम की मदद ली और महिला इस वर्ष मार्च में गर्भवती हो गई।

टाइम मैगजीन के अनुसार, महिला के पति को एजोस्पर्मिया की समस्या थी। यह ऐसी मेडिकल कंडीशन है, जिसमें वीर्य में काउंट किए जाने लायक शुक्राणु नहीं होते हैं। एजोस्पर्मिया कंडीशन वाले सैंपल में लैब टेक्नीशियन शुक्राणु नहीं खोज पाते हैं।

यह कुछ ऐसा है भूसे के ढेर से सुई खोजना। इस समस्या का समाधान किया स्टार ने। जिस तरह एस्ट्रोफिजिस्ट्स नए तारों का पता लगाने के लिए एआइ का इस्तेमाल करते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी फर्टिलिटी सेंटर के शोधकर्ताओं ने बेहद दुर्लभ स्पर्म को डिटेक्ट करने के लिए स्टार सिस्टम विकसित किया। स्टार डेवलपर और फर्टिलिटी सेंटर के डायरेक्टर डा. डेव विलियम्स ने बताया 'स्टार ने कुछ घंटों में स्पर्म डिटेक्ट कर लिया।' इससे दुनिया के काफी लोगों को उम्मीद बंधी है।

एआइ ने ऐसे डिटेक्ट किया शुक्राणु

विलियम्स और उनकी टीम ने स्पर्म का पता लगाने वाले एआइ एल्गोरिद्म का इस्तेमाल करते हुए स्टार सिस्टम को सटीक बनाया। स्पर्म का पता लगाने के लिए तरल चिप द्वारा वीर्य के नमूने को प्लास्टिक चिप पर लगी एक छोटी नली में प्रवाहित किया जाता है। एआइ जब एक बार स्पर्म की मौजूदगी की पुष्टि कर देता है, तो वीर्य के उस हिस्से को एक अलग नली में डाल दिया जाता है। नमूने में जो भी शुक्राणु बचे हैं, उन्हें इस तरह से अलग किया जा सकता है और या तो अंडे को निषेचित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या बाद में उपयोग के लिए फ्रीज किया जा सकता है। विलियम्स और उनकी टीम ने दंपति के लिए यही किया।

एजोस्पर्मिया से पीड़ित पुरुषों के लिए बड़ी घटना

पति के शुक्राणु कलेक्ट करने के दो घंटे बाद ही उन्हें पता चला कि पत्नी के अंडों का सफलतापूर्वक निषेचन हो चुका है। पत्नी अब चार महीने की गर्भवती है और मां और भ्रूण दोनों स्वस्थ हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी फर्टिलिटी सेंटर का कहना है कि स्टार सिस्टम एजोस्पर्मिया से पीड़ित पुरुषों के लिए एक बड़ी घटना है। यह कटिंग एज एआइ, हाई स्पीड इमेजिंग और रोबोटिक्स का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ शुक्राणुओं की कम संख्या को डिटेक्ट कर सकता है बल्कि उनको वीर्य से अलग भी कर सकता है। स्टार ऐसा किसी केमिकल या लेजर के इस्तेमाल के बिना कर सकता है।

इसलिए दूसरे डिटेक्शन सिस्टम से एडवांस है स्टार

स्टार दूसरे एआई डिटेक्शन सिस्टम से इसलिए एडवांस है क्योंकि यह पुरुष बांझपन के मामलों में वीर्य के सैंपल से शुक्राणुओं को सफलतापूर्वक अलग कर सकता है। विलियम्स ने कहा ' परीक्षण के तौर पर, हमने उन सैंपल को इस प्रणाली के जरिये आगे बढ़ाने का फैसला किया जहां भ्रूणविज्ञानियों को कोई शुक्राणु नहीं मिल पा रहा था। भ्रूणविज्ञानियों ने शुक्राणु खोजने के लिए कड़ी मेहनत की, क्योंकि वे किसी मशीन से पीछे नहीं रहना चाहते थे। एक सैंपल का उन्होंने दो दिन तक विश्लेषण किया और कोई शुक्राणु नहीं मिला। वहीं, स्टार ने एक घंटे में 44 शुक्राणु खोज निकाले।"

गाजा में खाना लेने आए 32 और लोग फायरिंग में मारे गए

- इजरायल के हवाई हमलों में भी 16 लोग मरे
- गाजा के हिस्से पर कब्जा कर सकता है इजरायल

यरुशलम, एपी : गाजा में बुधवार को इजरायली सैनिकों ने फिर से खाद्य सामग्री के लिए एकत्रित लोगों पर फायरिंग की और 32 लोग मार डाले। फायरिंग की इस घटना में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। गाजा के विभिन्न इलाकों में हुए इजरायली हमलों में 16 लोग मारे गए हैं। इस बीच इजरायल सरकार ने गाजा के कुछ हिस्से पर स्थायी नियंत्रण के संकेत दिए हैं।

इजरायली सेना ने राहत सामग्री लेने आए लोगों पर फायरिंग की घटना में जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। कहा है कि उसने केवल लड़ाकों को निशाना बनाया है। अगर नागरिक मारे गए हैं तो उसके लिए हमास जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि हमास आमजनों को ढाल बनाकर अपना बचाव और इजरायली सेना पर हमले कर रहा है। गाजा में ये मौतें ब्रिटेन का वह बयान आने के बाद हुई हैं जिनमें उसने गाजा की स्थिति को भयावह बताया है। फ्रांस के बाद ब्रिटेन ने भी सितंबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन के दौरान स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र को मान्यता देने का संकेत दिया है। इजरायल ने ब्रिटेन के इस बयान को खारिज कर दिया है। बुधवार को इजरायल सरकार की कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति के सदस्य मंत्री जीव एल्किन ने संकेत दिया कि इजरायल गाजा के कुछ हिस्से का स्थायी रूप से नियंत्रण ले सकता है। राहत सामग्री लेने के लिए आए लोगों पर गाजा सिटी और खान यूनिस शहरों के नजदीक फायरिंग हुई। 12 लोग गाजा सिटी में जबकि 16 लोग खान यूनिस में और चार लोग नुसीरत में मारे गए हैं। इजरायल के हवाई हमलों में दीर अल-बलाह और जबालिया शरणार्थी क्षेत्र में लोग मारे गए हैं।

****

चोट और कार्यभार प्रबंधन के कारण कप्तान स्टोक्स, आर्चर और कार्स बाहर | भारत के लिए | आज से शुरू हो रहे ओवल टेस्ट को जीतने की राह हुई आसान

आखिरी बार, आखिरी वार

अभिषेक त्रिपाठी
लंदन से

चोट और कार्यभार प्रबंधन से जूझ रही इंग्लिश टीम पर भारतीय टीम को एक आखिरी वार करना होगा। अगर यह वार सटीक बैठता है तो भारतीय टीम गुरुवार से शुरू होने वाले पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले को ही नहीं जीतेगी बल्कि इस सीरीज को भी 2-2 से बराबर कर लेगी। इस सीरीज में अभी तक भारतीय टीम चोट की समस्याओं से जूझ रही थी। उनके कई खिलाड़ियों को चोट के कारण कुछ टेस्ट मैचों से बाहर होना पड़ा तो नीतीश कुमार रेड्डी सीरीज से ही बाहर चले गए। कार्यभार प्रबंधन के तहत जसप्रीत बुमराह ने इस सीरीज में तीन ही मैच खेले हैं और उनका अगला टेस्ट खेलना नामुमकिन लग रहा है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स कंधे की चोट के कारण इस टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। आठ साल बाद टेस्ट में वापसी करके दो मैच खेलने वाले जोफ्रा आर्चर भी चोट के कारण अंतिम एकादश में नहीं चुने गए हैं। एक और तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स चार मैच खेलने के बाद आराम करेंगे। बशीर की जगह शामिल हुए स्पिनर लियाम डासन नहीं खेलेंगे। उनकी जगह स्पिन आलराउंडर जैकब बेथल को जगह दी गई है।

भारत का संयोजन: भारतीय टीम पिछले कुछ मैचों में आठवें नंबर तक की लंबी बल्लेबाजी वाले फार्मूले पर फिर चल सकती है। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, कप्तान शुभमन गिल शीर्ष क्रम की जिम्मेदारी संभालेंगे। साई सुदर्शन या करुण नायर में से कोई एक नंबर तीन पर उतर सकता है। करुण अभ्यास सत्र में नंबर तीन पर खेलते नजर आए। चोटिल रिषभ पंत की जगह उत्तर प्रदेश के विकेटकीपर ध्रुव जुरैल खेलेंगे जबकि पिछले मैच में शतक जड़कर टेस्ट ड्रा कराने वाले स्पिन आलराउंडर रवींद्र जडेजा व वाशिंगटन सुंदर यहां भी बल्लेबाजी क्रम को लंबा करते हुए नजर आएंगे। शार्दुल को इस सीरीज में तेज गेंदबाजी आलराउंडर के तौर पर खिलाया गया लेकिन ज्यादा ओवर नहीं दिए गए। हरी-भरी पिच को देखते हुए कुलदीप यादव के मुकाबले उनका पलड़ा भारी दिख रहा है। भारतीय टीम के पास उनके अलावा दूसरा तेज गेंदबाजी आलराउंडर नहीं है। तेज गेंदबाजी लाइनअप में मोहम्मद सिराज लगातार पांचवां टेस्ट खेलते नजर आ सकते हैं जबकि बुमराह की जगह आकाश दीप की वापसी होगी। पिछले मैच में काफी धीमी गेंदबाजी करके पदार्पण करने वाले अंशुल कंबोज की जगह तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह या प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिल सकता है। अगर अर्शदीप को मौका मिलता है तो यह उनका पहला टेस्ट होगा।

स्टोक्स के बिना इंग्लैंड की हालत खराब: स्टोक्स की अनुपस्थिति में ओली पोप इंग्लिश टीम की कमान संभालेंगे जबकि बेथल छठे नंबर पर उतरेंगे। स्टोक्स, आर्चर और कार्स की जगह तेज गेंदबाज गस एटकिंसन, जोश टंग और जेमी ओवरटन को शामिल किया गया है। चार टेस्ट खेल चुके क्रिस वोक्स जगह बरकरार रखेंगे। स्टोक्स ओल्ड ट्रैफर्ड में ड्रा हुए चौथे टेस्ट के अंतिम तीन दिन संघर्ष करते दिखे थे। उन्होंने भारत की पहली पारी में 24 ओवर और दूसरी पारी में केवल 11 ओवर फेंके थे। पांचवें दिन उनके दाहिने कंधे में तकलीफ देखी गई थी। सीरीज में दो बार प्लेयर आफ द मैच रहे और अब तक सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे स्टोक्स के शानदार फार्म को देखते हुए यह मेजबान टीम के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने मैनचेस्टर में भारत की पहली पारी में 72 रन देकर पांच विकेट लिए और फिर 141 रन बनाए। वह एक ही टेस्ट मैच की पारी में पांच विकेट लेने और शतक बनाने वाले इंग्लैंड के चौथे खिलाड़ी बने थे। इन बदलावों से इंग्लैंड का तेज गेंदबाजी आक्रमण थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है। टंग ने पहले दो टेस्ट मैचों में 11 विकेट लिए थे। वोक्स अब तक सीरीज में 10 विकेट ही ले पाए हैं जबकि ओवरटन ने 2022 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध केवल एक टेस्ट खेला है। एटकिंसन भी चोट से उबरकर इस सीरीज में पहली बार खेल रहे हैं। मई में जिंबाब्वे के विरुद्ध एकमात्र टेस्ट मैच के दौरान उन्हें हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी। स्पिन आक्रमण की बात करें तो बेथल और रूट पार्टटाइम स्पिनर हैं।

722 रन बना चुके हैं भारतीय कप्तान शुभमन गिल। वह एक सीरीज में किसी भारतीय द्वारा बनाए गए सुनील गावस्कर के सबसे ज्यादा रन के रिकार्ड से सिर्फ 52 रन दूर हैं। यही नहीं उन्हें किसी टेस्ट सीरीज में भारतीय कप्तान द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन के गावस्कर के रिकार्ड से 11 रन दूर हैं। गावस्कर ने 1978-79 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध यह रिकार्ड बनाया था

32 रन और चाहिए शुभमन गिल को 6000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने के लिए सभी प्रारूपों में, गिल ने 112 मैचों में 46.62 की औसत और 79.92 की स्ट्राइक रेट 5968 रन बनाए हैं। इनमें 25 अर्धशतक और 18 शतक शामिल हैं

अभ्यास से पहले पिच का निरीक्षण करते भारतीय कप्तान शुभमन गिल ● रायटर

घास होगी खास

भारतीय कोच गौतम गंभीर और सरे काउंटी के मैदानकर्मियों के प्रमुख ली फोर्टिस के बीच मंगलवार को गर्मागर्म बहस हुई थी और बुधवार को जब गंभीर पिच देखने पहुंचे तो उसमें काफी घास नजर आ रही थी। हेडिंग्ले, एजबेस्टन, लार्ड्स और ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच के मुकाबले यहां पर ज्यादा घास है। पांचों दिन अधिकतर समय आसमान में बादल भी छाए रहने की संभावना है। इसको देखते हुए स्पिनर कुलदीप यादव और तेज गेंदबाजी आलराउंडर शार्दुल ठाकुर में से किसे चुना जाएगा इस पर संशय बरकरार है। बुधवार को जब भारतीय टीम अभ्यास के लिए आई थी तो वर्षा होने लगी थी।

गिल-राहुल पर भरोसा

इस मैच में इंग्लिश टीम का गेंदबाजी आक्रमण भले ही कमजोर हो लेकिन हरी पिच को देखते हुए भारतीय टीम को सतर्क रहना होगा। चार शतक ठोकने वाले कप्तान गिल और 511 रन बना चुके केएल राहुल को फिर एक बड़ी पारी खेलनी होगी। यशस्वी को भी दम दिखाना होगा।

ओली पोप ● प्रेट्र

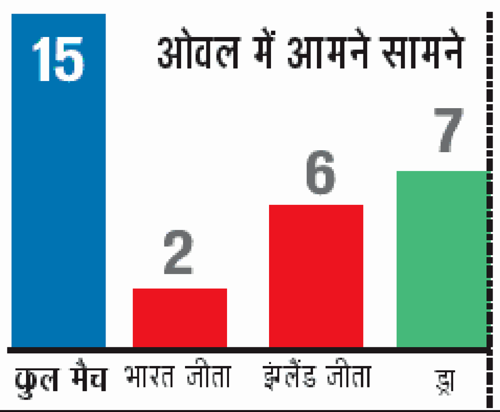

टीमें

इंग्लैंड की एकादश: जैक क्राउली, बेन डकेट, ओली पोप (कप्तान), जो रूट, हैरी ब्रूक, जैकब बेथल, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), क्रिस वोक्स, गस एटकिंसन, जेमी ओवरटन, जोश टंग।

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी, केएल राहुल, करुण नायर, रवींद्र जडेजा, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, ध्रुव जुरैल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, कुलदीप यादव, अंशुल कंबोज, अर्शदीप सिंह, एन जगदीशन (विकेटकीपर)।

कोच गंभीर को पिच देखने का पूरा अधिकार : गिल

विशेष संवाददाता ● जागरण

लंदन: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने ओवल के मुख्य क्यूरेटर ली फोर्टिस से तीखी बहस के बाद गौतम गंभीर का बचाव करते हुए कहा कि भारतीय कोच को पिच का मुआयना करने का पूरा अधिकार था। गिल से पांचवें और आखिरी टेस्ट से पहले जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो कल हुआ, वह गैर जरूरी था। उन्होंने कहा कि कोच को विकेट देखने का पूरा अधिकार है। समझ में नहीं आया कि क्यूरेटर इसकी अनुमति क्यों नहीं देगा। अगर आपने रबर के स्पाइक्स पहन रखे हैं या नंगे पैर हैं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पता नहीं उन्होंने क्यों रोका। पिछले चार मैचों में तो ऐसा कोई मसला नहीं हुआ था।

गिल ने कहा कि मौजूदा पांच मैचों की लंबी सीरीज के लिए मैचों के बीच में तीन दिन का अंतर बहुत कम है। खासकर गेंदबाजों के भारी वर्कलोड को देखते हुए। पहले टेस्ट (लीड्स) और तीसरे टेस्ट (लार्ड्स) के बीच एक हफ्ते का अंतर था, लेकिन दूसरे और तीसरे मैच के बीच तथा चौथे और पांचवें मैच के बीच केवल तीन दिन का ब्रेक रहा।

भारतीय टीम के साथ फिर टोकाटाकी करते नजर आए फोर्टिस

लंदन: ओवल स्टेडियम के मैदानकर्मियों ने भारतीय टीम के साथ लगातार दूसरे दिन टोकाटोकी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मंगलवार को यहां के ग्राउंड्समैन हेड ली फोर्टिस और कोच गौतम गंभीर के साथ विवाद हुआ था। बुधवार को जैसे ही भारतीय टीम अभ्यास करने आई तो फोर्टिस थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट नुवान को टोकते नजर आए। फिर जब कोच गंभीर, कप्तान शुभमन गिल, मुख्य चयनकर्ता अजित आगरकर और बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक पिच के पास अंतिम 11 चुनने को लेकर बात कर रहे थे तो फोर्टिस उन्हें वहां से थोड़ा हटने को कहते नजर आए। हालांकि इस दौरान गंभीर ने फोर्टिस को पूरी तरह नजरअंदाज किया। चारों लोग पिच के किनारे से हटकर पिच के ऊपर आ गए। इसके बाद जब बल्लेबाज साई सुदर्शन मैदान में एक किनारे फिटनेस ड्रिल कर रहे थे तो कुछ मैदानकर्मी आए और उनसे वहां से हटकर दूसरी तरफ जाने को कहा। यहां की सरे काउंटी से खेल चुके साई दूसरी तरफ चले गए।

मैदान पर उतरना काफी जोखिम भरा होता : स्टोक्स

लंदन, प्रेट्र: बेन स्टोक्स ने भारत के विरुद्ध शुरुआती चार टेस्ट मैच में इंग्लैंड के लिए महत्वपूर्ण ओवरों में गेंदबाजी करते हुए अपने चोटिल शरीर की परवाह नहीं की, लेकिन उनका कहना है कि सीरीज में आखिरी बार मैदान पर उतरना काफी जोखिम भरा होता। स्टोक्स ने कहा कि जोखिम इतना अधिक था कि इसे मौजूदा स्थिति से और अधिक नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। मैं ऐसा नहीं चाहता था और मैं किसी भी खिलाड़ी को इस तरह की चोट के जोखिम में डालने की उम्मीद नहीं करता। मैं रिहैबिलिटेशन शुरू करूंगा और आगे जो कुछ भी करना है उस पर ध्यान केंद्रित करूंगा। बहुत निराश हूं लेकिन मुझे इस तरह के फैसले लेने के लिए सामान्य से थोड़ा अधिक समय चाहिए था।

खेल डायरी

हेड को पछाड़ नंबर एक बल्लेबाज बने अभिषेक

दुबई, प्रेट्र: अभिषेक शर्मा ने आस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को पछाड़ कर पहली बार आइसीसी टी-20 रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। वह विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव के बाद यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय हैं। वहीं आइसीसी टेस्ट रैंकिंग में रवींद्र जडेजा ने आलराउंडरों की सूची में शीर्ष स्थान कायम रखते हुए 117 रेटिंग अंकों की बढ़त बना ली है। टेस्ट आलराउंडरों की सूची में वाशिंगटन सुंदर आठ पायदान चढ़कर 65वें स्थान पर हैं। टेस्ट क्रिकेट में जो रूट शीर्ष बल्लेबाज हैं जबकि न्यूजीलैंड के केन विलियम्सन दूसरे और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स तीसरे स्थान पर है। गेंदबाजों में जोफ्रा आर्चर 38 पायदान चढ़कर 63वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

आस्ट्रेलिया के विरुद्ध अंडर-19 टीम घोषित

मुंबई, प्रेट्र : भारत ने सितंबर-अक्टूबर में आस्ट्रेलिया के विरुद्ध होने वाली अंडर-19 सीरीज के लिए कप्तान आयुष म्हात्रे, उप कप्तान विहान मल्होत्रा और वैभव सूर्यवंशी सहित कई प्रमुख खिलाड़ियों को टीम में बरकरार रखा है। आस्ट्रेलियाई अंडर-19 टीम के विरुद्ध भारत तीन वनडे और चार दिवसीय दो मैच खेलेगा। सीरीज की शुरुआत 21 सितंबर से होगी और 10 अक्टूबर को समाप्त होगी। टीम : आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, राहुल कुमार, अभिज्ञान कुंडू, हरवंश सिंह, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, नमन पुष्पक, हेनिल पटेल, डी दीपेश, किशन कुमार, अनमोलजीत सिंह, खिलान पटेल, उद्धव मोहन और अमन चौहान।

एशियाई चैंपियनशिप में उतरेंगे 40 मुक्केबाज

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत ने बैंकाक में बुधवार से शुरू हो रही एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए 40 सदस्यीय टीम भेजी है। टूर्नामेंट में 26 देशों के 396 मुक्केबाज भाग लेंगे। एशियाई मुक्केबाजी इसका आयोजन विश्व मुक्केबाजी और थाईलैंड मुक्केबाजी संघ के साथ मिलकर कर रही है। इसमें दो आयुवर्ग अंडर 19 और अंडर 22 में स्पर्धाएं होंगी। महिला और पुरुष मुक्केबाज ओलिंपिक मुक्केबाजी नियमों के तहत खेलेंगे। भारतीय टीम की अगुवाई तीन बार के एशियाई चैंपियन और दो बार के राष्ट्रीय चैंपियन विश्वनाथ सुरेश करेंगे। उनके साथ राष्ट्रीय चैंपियनशिप पदक विजेता सागर, प्रीत मलिक और सुमन कुमारी भी होंगी।

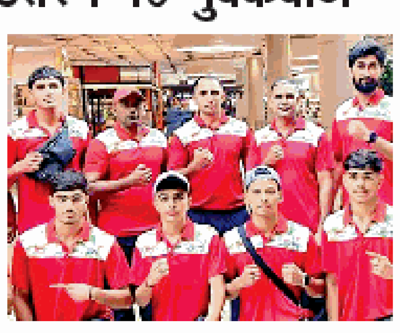

एलएसजी के गेंदबाजी कोच बने भरत अरुण

लखनऊ, प्रेट्र: कोलकाता नाइट राइडर्स से अलग हुए पूर्व भारतीय गेंदबाजी कोच भरत अरुण को लखनऊ सुपरजायंट्स (एलएसजी) ने इसी पद पर टीम से जोड़ा है। फ्रेंचाइजी के सूत्र ने बताया कि अरुण एलएसजी में शामिल हो गए हैं और जल्द ही औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद है। अरुण पिछले कुछ साल से केकेआर से जुड़े थे लेकिन 2025 में टीम के आठवें स्थान पर रहने के बाद शाहरुख खान के स्वामित्व वाली यह फ्रेंचाइजी अपने कोचिंग स्टाफ में बदलाव कर रही है। इसी तरह पिछले सत्र में सातवें स्थान पर रहने के बाद एलएसजी भी अपने सहयोगी स्टाफ में बदलाव कर रही है। राष्ट्रीय टीम के अब तक के सबसे बेहतरीन गेंदबाजी कोचों में से एक अरुण अपनी रणनीतिक कुशलता के साथ प्रतिभाशाली तेज गेंदबाजों को निखारने के लिए भी मशहूर हैं।

सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान से नहीं खेलेगी इंडिया चैंपियंस

बर्मिंघम, प्रेट्र: भारत ने गुरुवार को विश्व चैंपियनशिप आफ लीजेंड्स (डब्ल्यूसीएल) के सेमीफाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के विरुद्ध खेलने से इन्कार कर दिया। शिखर धवन, इरफान पठान, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सुरेश रैना जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की मौजूदगी वाली भारतीय टीम पहले ही पहलगाम आंतकी हमले के विरोध में पाकिस्तान के विरुद्ध ग्रुप चरण में भी नहीं खेलने का निर्णय किया था।

भारत को गुरुवार को एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान से खेलना था। लीग के शीर्ष प्रायोजक ईजमाईट्रिप ने भारत-पाक मैच पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। कंपनी के सह संस्थापक निशांत पिट्टी ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान के विरुद्ध आगामी सेमीफाइनल कोई सामान्य मैच नहीं है। आतंकवाद और क्रिकेट साथ-साथ नहीं चल सकते। इस मुद्दे पर हम भारत के साथ खड़े हैं।

लक्ष्य-आयुष दूसरे दौर में

लक्ष्य सेन ● बैडमिंटन फोटो

मकाऊ, प्रेट्र: भारत के लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और तरुण मन्नेपल्ली ने मकाऊ ओपन बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग के दूसरे दौर में प्रवेश किया। राष्ट्रमंडल खेल चैंपियन लक्ष्य ने कोरिया के जियोन हियोक जिन को 21-8, 21-14 से हराया। वहीं, विश्व के 31वें नंबर के खिलाड़ी शेट्टी ने 66वीं रैंकिंग वाले चीनी ताइपे के हुआंग यू केइ को केवल 31 मिनट में 21-10, 21-11 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। लक्ष्य का सामना इंडोनेशिया के चिको औरा द्वि वार्दोयो और रित्विक संजीवी सतीश कुमार के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। मिक्स्ड डबल्स में विश्व में यहां पांचवीं वरीयता प्राप्त ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्तो की जोड़ी ने थाईलैंड के रत्चपोल मक्कासितोर्न और नट्टामोन लाइसुआन को 26 मिनट तक चले मुकाबले में 21-10, 21-15 से हराया। पुरुष सिंगल्स में सतीश कुमार करुणाकरण को मलेशिया के जस्टिन होह से 19-21, 12-21 से हार का सामना करना पड़ा। एच एस प्रणय को इंडोनेशिया के योहानेस एस मार्शेलिनो ने 21-18, 15-21, 15-21 से हराया।

विश्व कप विजेता दिव्या का भव्य स्वागत

नागपुर, प्रेट्र : महिला शतरंज विश्व कप 2025 की चैंपियन दिव्या देशमुख बुधवार को जब अपने गृहनगर नागपुर पहुंचीं, तो एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। प्रशंसक, परिवार और महाराष्ट्र शतरंज संघ के अध्यक्ष परिणय फुके की मौजूदगी ने इस लम्हे को खास बना दिया। 19 वर्षीय दिव्या ने सोमवार को जार्जिया के बाटुमी में खेले गए फाइनल में अनुभवी कोनेरू हंपी को टाईब्रेकर में हराकर इतिहास रच दिया था। वह यह खिताब जीतने वाली सबसे युवा महिला खिलाड़ी बन गई हैं।

एयरपोर्ट पर स्वागत से गदगद दिव्या ने कहा, इतना प्यार पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। इतने लोग मुझे रिसीव करने आए, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं बेहद खुश हूं। अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने अपने परिवार, खासकर बहन और अपने पहले कोच राहुल जोशी को दिया। दिव्या ने कहा, मेरे पहले कोच की इच्छा थी कि मैं एक दिन ग्रैंडमास्टर बनूं। यह जीत मैं उन्हें समर्पित करती हूं।

नागपुर एयरपोर्ट पर विश्व कप ट्राफी के साथ दिव्या देशमुख ● प्रेट्र

फर्नांडीज पहले दौर में हारीं, गफ आगे बढ़ीं

लेयला फर्नांडीज ● एएफपी

टेनिस डायरी

मांट्रियल, एपी: पिछले सप्ताह वाशिंगटन में डीसी ओपन का खिताब जीतने वाली स्थानीय खिलाड़ी लेयला फर्नांडीज नेशनल बैंक ओपन के पहले ही दौर में बाहर हो गईं। फर्नांडीज को आस्ट्रेलिया की माया जाइंड ने केवल एक घंटे 15 मिनट में 6-4, 6-1 से हरा दिया। विश्व की 24वें नंबर की इस खिलाड़ी ने रविवार को वाशिंगटन में अपने करियर का चौथा डब्ल्यूटीए खिताब जीता था और वह मांट्रियल में कोर्ट पर वापसी से पहले अतिरिक्त आराम की उम्मीद कर रही थीं, इसलिए उन्होंने हार के बाद इस टूर्नामेंट के कार्यक्रम की आलोचना भी की। फर्नांडीज ने कहा कि उन्हें कई वादे मिले थे कि वह मंगलवार की रात के सत्र में खेलेंगी, जिससे उन्हें दोनों टूर्नामेंटों के बीच अधिक समय मिल सके, लेकिन रविवार को यात्रा के दौरान उन्हें पता चला कि ऐसा नहीं होगा। यह मेरे लिए दुखद था क्योंकि मैं रात में खेलने के लिए बहुत उत्सुक थी।

अन्य मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त अमेरिका की कोको गफ ने तीन सेट तक चल कड़े मुकाबले में जीत दर्ज करके अगले दौर में जगह बनाई। गफ ने हमवतन अमेरिकी डेनियल कोलिंस के विरुद्ध 23 डबल फाल्ट किए लेकिन वह अंत में 7-5, 4-6, 7-6 (2) से जीत प्राप्त करने में सफल रहीं, जो फ्रेंच ओपन फाइनल के बाद उनकी पहली जीत है।

मुसेती और रुने अगले दौर में पहुंचे

टोरंटो: तीसरी वरीयता प्राप्त लोरेंजो मुसेती और पांचवीं वरीयता प्राप्त होल्गर रुने ने सीधे सेटों में जीत दर्ज करके नेशनल बैंक ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अगले दौर में जगह बनाई। मुसेती ने आस्ट्रेलियाई क्वालीफायर जेम्स डकवर्थ को 7-5, 6-1 से, जबकि रुने ने जियोवानी एमपेट्शी पेरीकार्ड को 7-6 (7), 6-3 से हराया। इस मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में सभी वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों को पहले दौर में बाई मिली थी। आठवीं वरीयता प्राप्त कैस्पर रूड, 11वीं वरीयता प्राप्त करेन खाचानोव, 14वीं वरीयता प्राप्त फ्रांसिस्को सेरुंडोलो और गत विजेता एलेक्सी पोपिरिन भी अपने-अपने मैच जीतने में सफल रहे।

****

आइपीएल की चार टीमों ने द हंड्रेड फ्रेंजाइजियों में खरीदी हिस्सेदारी

लंदन, प्रेट्र: आइपीएल की चार फ्रेंचाइजी के मालिकों को बुधवार को ईसीबी ने द हंड्रेड की टीमों के लिए रणनीतिक साझेदार के रूप में पुष्टि की है, जिन्हें इस साल एक अक्टूबर तक परिचालन नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। इंग्लैंड में खेल की शासी संस्था ने कहा कि इन साझेदारों में भारत की जीएमआर (दिल्ली कैपिटल्स), सन टीवी (सनराइजर्स हैदराबाद), आरपीएसजी समूह (लखनऊ सुपरजायंट्स) और रिलायंस समूह (मुंबई इंडियंस) शामिल हैं। ईसीबी ने कहा कि इन समझौतों से खेल के विकास के लिए करोड़ों पाउंड प्राप्त होंगे। ईसीबी ने कहा कि दो और साझेदार (ओवल इनविंसिबल्स में हिस्सेदारी के लिए रिलायंस समूह शामिल) की बाद में औपचारिक रूप से पुष्टि हो जाएगी। दिल्ली के मालिक जीएमआर ने सदर्न ब्रेव्स में 49 प्रतिशत, सनराइजर्स हैदराबाद ने नार्दर्न सुपर चार्जर्स में 100 प्रतिशत, लखनऊ सुपरजायंट्स ने मैनचेस्टर ओरिजनल्स में 70 प्रतिशत और मुंबई इंडियंस ने ओवल इनविंसिबल में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है।

मार्शां ने 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले में तोड़ा विश्व रिकार्ड

1:52.61
सेकेंड का समय विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में निकाल कर अमेरिकी तैराक रेयान लोकटी का रिकार्ड तोड़ा

फ्रांस के तैराक लियोन मार्शां ● रायटर

सिंगापुर, एपी : फ्रांस के तैराक लियोन मार्शां ने बुधवार को सिंगापुर में चल रही विश्व तैराकी चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। उन्होंने 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले एक मिनट 52.61 सेकेंड का समय निकालते हुए नया विश्व रिकार्ड बना दिया। उन्होंने अमेरिका के रयान लोकटी द्वारा 2011 में बनाए गए 1:54.00 सेकेंड के रिकार्ड को तोड़ा। यह रिकार्ड उन्होंने सेमीफाइनल रेस में स्थापित किया।

मार्शां ने पिछले साल पेरिस ओलिंपिक में चार स्वर्ण पदक जीतकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाई थी। अब सभी की निगाहें रविवार को होने वाले 400 मीटर व्यक्तिगत मेडले इवेंट पर टिकी हैं, जो इस चैंपियनशिप का अंतिम दिन होगा। इस इवेंट में भी मार्शां ही वर्तमान विश्व रिकार्ड धारक हैं। उन्होंने यह रिकार्ड 2023 में जापान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 4:02.50 सेकेंड में रेस पूरी करके बनाया था।

क्रिकेट और स्पोर्ट्स की अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

दैनिक जागरण सप्तरंग
तकनीक की दुनिया का
गुरुवार, 31 जुलाई, 2025

इन दिनों

एआइ से टेक्स्ट, रिव्यूज में छेड़छाड़, किसी की आवाज का क्लोन या फिर डीपफेक वीडियो के जरिए ठगी को अंजाम, ऐसे मामले आए दिन चर्चा में रहते हैं। सच जैसे दिखने वाले इस भ्रम को जानने-पहचानने का क्या है तरीका, बता रहे हैं ब्रह्मानंद मिश्र...

फोटो : प्रतीक

इंटेलिजेंस की फेक दुनिया

बीते दिनों इंटरनेट मीडिया पर असम के डिब्रूगढ़ की रहने वाली एक युवती की फोटो और वीडियो वायरल हुईं। इंस्टाग्राम पर कुछ ही दिनों में उसके फालोअर्स की संख्या लाखों में पहुंच गई। गूगल सर्च से लेकर मीम्स और फैन पेज की बाढ़ आ गई, मगर वास्तव में ऐसी कोई युवती थी ही नहीं। यह सब प्रतिम बोरा नाम के एक व्यक्ति द्वारा बदला लेने की भावना से पूर्व प्रेमिका की एआइ से फेक प्रोफाइल बनाकर किया जा रहा था। एआइ से तैयार डीपफेक के शिकार रश्मिका मंदाना, आमिर खान, विराट कोहली जैसी अनेक हस्तियां भी हो चुकी हैं। दरअसल, एडवांस एआइ टूल्स से आज टेक्स्ट, फोटो, आडियो, वीडियो में छेड़छाड़ करना ही आसान नहीं हुआ है, बल्कि उन्हें वास्तविक जैसा बना देना भी सहज हो गया है। एआइ जिस तेजी से सुविधाएं बढ़ा रहा है, उतनी ही तेजी से व्यक्तिगत, व्यवसायों और दुनियाभर में सरकारों के लिए सिरदर्द भी बन रहा है।

इंटरनेट मीडिया और एआइ का दुरुपयोग : इंटरनेट मीडिया समेत सभी कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफार्म्स के लिए आइटीयू (इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन) ने ऐसे डिजिटल वेरिफिकेशन टूल्स के प्रयोग की अनिवार्यता पर बल दिया है, जो किसी भी तरह के कंटेंट के साझा होने से पहले उसकी जांच कर सकें। एआइ कंटेंट की बाढ़ में लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन सा कंटेंट असली है और कौन सा नकली। इंटरनेट मीडिया पर फीड्स को स्क्राल करते हुए अक्सर सवाल उठता है कि क्या हम इस पोस्ट पर विश्वास कर सकते हैं।

एआइ का दूसरा पक्ष अधिक खतरनाक : आज हर स्तर पर एआइ का प्रयोग बढ़ रहा है, पर इसके संभावित खतरों, एआइ जेनरेटेड डीपफेक, अफवाहों को लेकर भी सतर्क होने की आवश्यकता है। आज हम उस युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां एक फर्जी फोटो या वीडियो किसी कंपनी को मिनटों में डुबा सकती है। भारत में वाट्सएप के जरिए फर्जी खबरों, फोटो और वीडियो को साझा कर साइबर अपराधों को अंजाम देना बहुत ही आम होता जा रहा है। वहीं वाइस क्लोनिंग के जरिए धोखाधड़ी के मामलों में बेशुमार वृद्धि हुई है।

5 तरीकों से जानें एआइ जेनरेटेड वीडियो के बारे में

1. **फेशियल और लिपसिंकिंग :** एआइ से तैयार किसी डीपफेक वीडियो को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि बोले गए शब्दों और होठों के बीच तालमेल नहीं होता। यह बिल्कुल अंग्रेजी में ओवरडब आडियो ट्रैक की तरह प्रतीत होता है। अगर किसी वीडियो में मिसमैच दिखता है, तो इसके एआइ कापी होने का अंदेशा प्रबल हो जाता है।
2. **पलकें झपकने और चेहरे का हाव-भाव :** एआइ जेनरेटेड वीडियो में पलकों का झपकना थोड़ा असामान्य होता है। बात करते हुए पलकों का एक तरह का अनियमित एक्सप्रेशन दिखता है। इसी तरह एआइ वीडियो में चेहरे का हाव-भाव स्मूथ और सीमित होता है।
3. **एआइ वीडियो डिटेक्शन टूल्स :** एआइ वीडियो को जांचने के लिए डीपफेकर, वीवेरिफाई जैसे टूल्स की मदद ली जा सकती है, जो डीपफेक वीडियो का फ्रेम-बाय-फ्रेम एनालिसिस करके चेहरे के हावभाव की अनियमितता को पकड़ते हैं।
4. **बैकग्राउंड शोर और छेड़छाड़ :** एआइ प्लेटफार्म किसी वीडियो के बैकग्राउंड और शोर को पूरी तरह हटाने में सक्षम नहीं होते। इससे बैकग्राउंड शोर, रंग और दृश्यता में एक तरह का फर्क नजर आ जाता है। हालांकि, अब एआइ टूल्स इस मामले में बेहतर होते जा रहे हैं।
5. **भावनात्मक असंगति :** एआइ में अभी अपने वीडियो में सूक्ष्म रूप से अटपटे संवाद, अटपटे हाव-भाव और अप्राकृतिक सूक्ष्म हाव-भाव मिश्रित करने जैसी अनियमितताएं हैं। ये छोटी-छोटी गलतियां मिलकर बोले गए शब्दों के भावनात्मक लहजे और प्रदर्शित प्रतिक्रियाओं के बीच असंगति पैदा करती हैं।

एआइ को लेकर बढ़े सतर्कता

अब वास्तविक और एआइ जेनरेटेड कंटेंट के बीच फर्क करना आसान नहीं है, पर यह असंभव भी नहीं है। एआइ टेक्स्ट की भाषा अत्यधिक परिष्कृत और कई बार भावनाहीन होती है। इसमें गहराई, भाव या प्रासंगिक समझ का अभाव दिखता है। यह पढ़ने-सुनने में ठीक तो लगता है लेकिन भावहीन होता है। इसी तरह एआइ जनित आडियो प्राकृतिक ढंग से लय पूर्ण नहीं होता। इसका टोन सपाट, सांसों का अभाव या आवाज की गति अप्राकृतिक होती है। वीडियो की बात करें, तो ध्यान से देखने पर चेहरे के हाव-भाव में असमानता दिखती है, साथ ही वीडियो में आंखों और होठों का मूवमेंट असामान्य दिखता है। इस तरह के सूक्ष्म संकेत सही-गलत के भ्रम को दूर कर सकते हैं। लेकिन, सच यह भी है कि जेनरेटिव तकनीक के विकास के साथ इस तरह के संकेत तेजी से खत्म हो रहे हैं। डिटेक्शन टूल्स उपयोगी हैं, पर ये मानवीय समझ का स्थान नहीं ले सकते। इंटेलिजेंट फेक की दुनिया में सतर्कता भरा सोच आपका सबसे बड़ा डिफेंस है। विश्वास करने से पहले ठहरना और साझा करने से पहले वेरिफाई करना जरूरी है!

यशराज भारद्वाज
सीएमओ एवं सीओओ, पेटोनिक एआइ

एआइ जेनरेटेड टेक्स्ट को जांचने का तरीका

वाक्यांशों में दोहराव : एआइ से तैयार कंटेंट में अक्सर वाक्यांशों और तथ्यों में दोहराव दिखता है। अक्सर यूजर द्वारा दिए प्राम्प्ट का कई बार प्रयोग दिखता है।
गहराई का अभाव : किसी विषय पर गहराई में जाने के बजाय एआइ उसका सारांश देता है। कई बार तो हैलुसिनेशन के चलते गलत तथ्य भी जेनरेट कर देता है।
पूर्वानुमान दिखना : इस तरह के टेक्स्ट का प्रवाह बहुत ही सामान्य तरह का होता है या फिर बहुत ही जटिल प्रकार का।
संभावित परिवर्तन : एआइ जेनरेटेड कंटेंट मूल से अलग दिखने के लिए कई बार उसमें अनावश्यक परिवर्तन दिखाता है। वाक्य की संरचना असामान्य होती है।

आडियो को ऐसे जांचें

सामान्य ठहराव का अभाव : अक्सर एआइ से तैयार आडियो और वीडियो में सामान्य ठहराव नहीं दिखता। एआइ जेनरेटेड पाडकास्ट में इस तरह की खामियां देखी जा सकती हैं। हालांकि, नए और एडवांस माडल में इस तरह की समस्या कम पाई जा रही है।
आवाज में अनियमित अशुद्धियां : यदि आप ध्यान से सुनें तो आवाज की गड़बड़ियों और अन्य त्रुटियों को नोटिस कर सकते हैं।
स्पीड प्ले पर अधिक स्पष्टता : किसी आडियो की स्पीड को बढ़ाकर सुनने पर एआइ जेनरेटेड वाइस अधिक स्पष्ट हो जाती है।
अत्यधिक भावुकता : एआइ की आवाजें बहुत अधिक भावुक होती हैं। उदाहरण के लिए, वे अपनी उत्तेजना को इतना बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं कि अक्सर वह बनावटी लगती है।

गैजेट रिव्यू

मोटो जी96

हल्का, स्लीक और आकर्षक वीगन लेदर डिजाइन के साथ मोटो जी96 उन यूजर्स के लिए एक शानदार आप्शन है, जो 20 हजार से कम में प्रीमियम लुक वाले स्मार्टफोन की तलाश में हैं।

डिजाइन एवं डिस्प्ले : वीगन लेदर फिनिश में जी96 का बैक पैनल और कर्व्ड डिस्प्ले अलग तरह का ग्लैमर देता है। मात्र 178 ग्रा. हल्का और 7.9 एमएम पतला होने से इसे लंबे समय तक होल्ड रखने में असहजता नहीं होती। फोन में आइपी68 वाटर प्रोटेक्शन और कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन है। हालांकि, डिस्प्ले को स्क्रैच से बचाने के लिए सतर्कता जरूरी है। फोन में 144 हट्र्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.67 इंच कर्व्ड पीओलेड डिस्प्ले, 1600 निट्स ब्राइटनेस है।

परफार्मेंस एवं साफ्टवेयर : एज60 स्टाइलस की तरह इसमें भी स्नैपड्रैगन 7एस जेन2 प्रोसेसर है। फोन 8जीबी रैम के साथ 128 और 256 स्टोरेज वैरिएंट में आता है। रोजाना के प्रयोग के लिए बेहतर है, पर गेमिंग, एंटरटेनमेंट में इसकी परफार्मेंस सीमित है। हैंडसेट एंड्रायड 15 हेलो यूआइ आधारित होने से कई सारे कार्यों में यूजर उपयोगी है। फोन में गूगल सूइट के जरिए एआइ फीचर्स मिलते हैं। रोजाना के कार्यों में जेश्चर आधारित प्रयोग आकर्षक हैं।

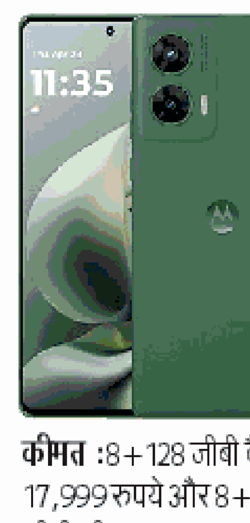

कीमत : 8+128 जीबी वैरिएंट 17,999 रुपये और 8+256 जीबी कीमत 19,999 रुपये

कैमरा : 50एमपी का सोनी लिटिया 700सी मेन कैमरा नेचुरल लाइट में काफी डिटेल्स कैप्चर करता है। वहीं आठ एमपी अल्ट्रावाइड लेंस लगभग 120 डिग्री तक व्यूज को कवर करता है। 32 एमपी का सेल्फी कैमरा शार्प इमेज लेता है।

बैटरी एवं चार्जिंग : 33 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ 5500 एमएएच की बैटरी लगभग एक घंटे में फुल चार्ज हो जाती है।

वर्डिक्ट : डिजाइन, बनावट, आइपी68 रेटिंग, 144 हट्र्ज रिफ्रेश रेट 20 हजार से कम बजट में एक बेहतर आप्शन है, पर ओएस अपग्रेड, इंटेंसिव गेमिंग, मल्टीटास्किंग में प्रदर्शन सामान्य है।

ब्रह्मानंद मिश्र

इंटरनेट मीडिया

इंस्टाग्राम ने बढ़ाई टीन अकाउंट की सेफ्टी

टीन अकाउंट की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम नए सेफ्टी फीचर्स ला रहा है, जिससे कोई अनजान यूजर टीनएजर को डीएम यानी मैसेज नहीं कर सकेगा। अगर कोई 18 वर्ष से कम आयु का यूजर है तो उसे ऐसा व्यक्ति मैसेज नहीं कर सकेगा, जिसे वह फालो नहीं कर रहा है। इसमें वेरिफाइड यूजर्स, ब्रांड्स इन्फ्लुएंशर या आपके सर्कल से बाहर का कोई भी यूजर हो सकता है। इससे पहले यूजर बिना फोटो या वीडियो का सिंगल मैसेज रिसीव कर सकता था। अब यह पूरी तरह बंद हो जाएगा, जब तक कि दोनों एक दूसरे को फालो नहीं करते। इससे स्पैम, साइबर खतरों आदि से राहत मिलेगी। इंस्टाग्राम अब किशोरों के नए अकाउंट को डिफाल्ट प्राइवेट प्रोफाइल बना रहा है।

टेक अपडेट

सेफ्टी या साउंड कैसे चुनें ईयरबड्स

बाजार में दो तरह के ईयरबड्स देखने को मिलते हैं- एक इन-ईयर ईयरबड्स और दूसरे ओपन-ईयर ईयरबड्स। इन दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर आप नए ईयरबड्स खरीदने का सोच रहे हैं, तो इनके फायदे और नुकसान देख लीजिए, ताकि बेहतर आप्शन का चुनाव कर सकें....

इन-ईयर ईयरबड्स वे होते हैं, जो कान के अंदर (कैनाल) में अच्छे से फिट हो जाते हैं। इनमें सिलिकान या फोम टिप्स होते हैं, जो कान को सील कर देते हैं। इससे बाहर का शोर कम होता है और साउंड की क्वालिटी बढ़िया मिलती है। वहीं ओपन ईयरबड्स कान के अंदर नहीं जाते। ये कान को पूरी तरह बंद नहीं करते हैं, इसलिए आप आसपास की आवाजें सुन सकते हैं। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बने हैं, जो बाहर की दुनिया से कनेक्टेड रहना चाहते हैं।

ओपन-ईयर ईयरबड्स के फायदे: ओपन-ईयर ईयरबड्स कान को ब्लाक नहीं करते। आप आसपास की आवाजें, जैसे- गाड़ियों के हार्न, लोगों की बातचीत या आफिस में दूसरों की आवाजें सुन सकते हैं। ये साइकिलिंग, रनिंग या सड़क पर चलते समय सुरक्षा के लिहाज से भी अच्छे हैं। इन्हें घंटों पहनना आसान है। साथ ही, कोई दबाव या दर्द भी नहीं होता है। कान खुला रहने से नमी जमा नहीं होती, जिससे इन्फेक्शन का खतरा भी कम होता है। कुछ माडल्स में बोन कंडक्शन टेक्नोलाजी होती है, जो साउंड को हड्डियों के जरिए सीधे आपके कान तक पहुंचाती है। ये खास तौर पर रनर्स और आउटडोर स्पोर्ट्सपर्संस के लिए बनाए जाते हैं। ज्यादातर ओपन-ईयर ईयरबड्स आइपीएक्स5 या आइपीएक्स6 रेटिंग के साथ आते हैं, जो इन्हें पसीने और बारिश से सुरक्षित बनाता है। चूंकि इनमें एएनसी जैसे फीचर्स नहीं होते, इसलिए बैटरी 8-10 घंटे चल सकती है।

ओपन-ईयर ईयरबड्स के नुकसान: कान खुला होने की वजह से साउंड क्वालिटी इन-ईयर ईयरबड्स जितनी अच्छी नहीं होती है। बास कमजोर हो सकता है और साउंड की गहराई कम हो सकती है। अगर आप म्यूजिक में बास और डिटेल्स को अहमियत देते हैं, तो ये आपको निराश कर सकते हैं। इनमें एएनसी नहीं होता है, जिससे शोरगुल वाले माहौल में आवाज साफ नहीं सुनाई देती है। मेट्रो, बस या बाजार जैसी जगहों पर बाहर का शोर आपकी आवाज को दबा सकती है। ओपन-ईयर ईयरबड्स कान के बाहर टिके रहते हैं, जिससे तेज मूवमेंट (जैसे जंपिंग या हाइ-इंटेंसिटी वर्कआउट) में गिर सकते हैं। कुछ माडल्स में हुक डिजाइन होता है, जो इसे थोड़ा बेहतर बनाता है, लेकिन फिर भी ये इन-ईयर जितने टाइट नहीं होते हैं। कान खुला होने से साउंड बाहर लीक हो सकता है। इससे आसपास के लोग म्यूजिक या काल सुन सकते हैं, जो गोपनीयता के लिए अच्छा नहीं है। इनमें टच कंट्रोल्स, इक्वलाइजर या वाइस असिस्टेंट जैसे फीचर्स कम होते हैं। ज्यादातर ओपन-ईयर ईयरबड्स बेसिक फंक्शंस पर फोकस करते हैं, जैसे- म्यूजिक और काल्स।

इन-ईयर ईयरबड्स के फायदे

इन-ईयर ईयरबड्स साउंड को सीधे कान तक पहुंचाते हैं, जिससे बास, मिड्स और ट्रेबल साफ सुनाई देते हैं। ये हाइ-रिजाल्यूशन आडियो सपोर्ट करते हैं, जो 24-बिट/96किलोहट्र्ज की साउंड क्वालिटी देता है। वहीं एक्टिव नाइज कैंसिलेशन बाहर के शोर, जैसे- ट्रैफिक या भीड़ की आवाज को कम कर देता है। ये कान में टाइट फिट होते हैं, इसलिए जिम, रनिंग या ट्रैवल में गिरते नहीं है। ये छोटे, हल्के और जेब में आसानी से रखे जा सकते हैं।

इन-ईयरबड्स के नुकसान

कुछ लोगों को इन-ईयर ईयरबड्स को लंबे समय तक पहनने में दिक्कत होती है। सिलिकान टिप्स से कान में दबाव पड़ सकता है, जिससे दर्द, खुजली या थकान हो सकती है। कान के अंदर नमी जमा होने से बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। इससे कान में इन्फेक्शन का खतरा रहता है। एएनसी की वजह से आप बाहर की जरूरी आवाजें (जैसे गाड़ी का हार्न) नहीं सुन पाते। ट्रांसपेरेंसी मोड इस समस्या को कुछ हद तक हल करता है। एएनसी और हाइ-क्वालिटी साउंड की वजह से बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है। ज्यादातर इन-ईयरबड्स 4-6 घंटे की बैटरी लाइफ देते हैं और केस के साथ 20-24 घंटे तक चलते हैं, लेकिन एएनसी आन रखते हैं, तो यह और कम हो सकती है।

दोनों में से कौन-सा चुनें?

अगर आप बेहतरीन साउंड क्वालिटी, गहरा बास, नाइज कैंसिलेशन और गोपनीयता चाहते हैं, तो इन-ईयर ईयरबड्स जिम, ट्रैवल या लंबी काल्स के लिए बेस्ट हैं। अगर बाहर की आवाजें सुनना चाहते हैं, आराम और कान की सेहत को प्राथमिकता देते हैं, तो ओपन-ईयर ईयरबड्स सही हैं।

संतोष आनंद

इस पेज के बारे में अपनी राय और सुझाव भेजें- feature@jagran.com

आज का भविष्यफल : 31 जुलाई, 2025 गुरुवार

पं. के.ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति
श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी का राशिफल।
आज का राहुकाल : दोपहर 01 बजकर 30 मिनट से 03 बजे तक।
आज का दिशाशूल : दक्षिण
विशेष : गोस्वामी श्री तुलसीदास जयंती

कल 01 अगस्त, 2025 का पंचांग

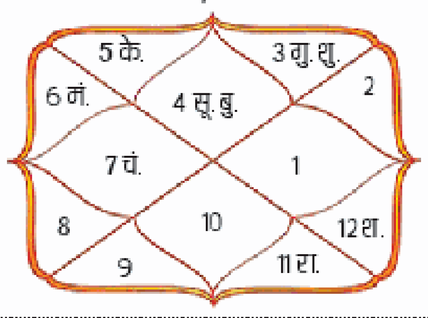

कल का दिशाशूल : पश्चिम
विशेष : लोकमान्य तिलक पुण्य तिथि, अष्टमी तिथि वृद्धि
कल की भद्रा : प्रात: 05 बजे से सायं 06:10 बजे तक।
विक्रम संवत 2082 शके 1947 दक्षिणायण, उत्तरगोल, वर्षा ऋतु श्रावण मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी 29 घंटे 28 मिनट तक, स्वाति नक्षत्र 27 घंटे 41 मिनट तक, तत्पश्चात विशाखा नक्षत्र शुभ योग 29 घंटे 28 मिनट तक, तुला में चंद्रमा।

मेष : जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे।
वृष : स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। भाई-बहन से तनाव मिल सकता है। राजनीतिक सहयोग मिलेगा।
मिथुन : चल या अचल संपत्ति के मामलों में समस्या आ सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है।
कर्क : पारिवारिक तनाव मिल सकता है। निजी सुख में व्यवधान रहेगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।
सिंह : जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। मन अशांत रहेगा।
कन्या : आर्थिक मामलों में सुधार होगा लेकिन क्रोध और भावुकता पर नियंत्रण रखें। मंगल आपके लिए कष्टदायी है।
तुला : रुपये-पैसे के मामलों में सावधानी बरतें। धनहानि की आशंका है। लाल वस्तुओं का दान करें।
वृश्चिक : पिता या धर्म गुरु से व्यर्थ का विवाद हो सकता है। वाणी पर संयम रखें, वही हितकर होगा।
धनु : शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया श्रम सार्थक होगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिल सकता है।
मकर : महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी या पारिवारिक मुखिया का सान्निध्य रहेगा।
कुंभ : आर्थिक मामलों में सुधार होगा। विरोधी परास्त होंगे। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे।
मीन : संतान या शिक्षा के कारण चिंतित रहेंगे। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं।

वर्ग पहेली-3060

1		■	2		3	■	4		5
	■	■		■	6			■	
7	8	■		■		■	■	■	■
■		■	■	9		■	10		11
12			13	■	■	14	■	■	
	■	■		■	■	15		16	
17			■	18		■	■		■
■	■	■	■		■	19	■	20	21
22	■	23			■		■	■	
24			■	25			■	26	

© Bird Features & Writing Agency

बाएं से दाएं :
1 पराया (2) । 2 पीब, पस (3) ।
4 स्थान, पद (3) । 6. घर्षण, परिश्रम (3) । 7 अंधेरा, अज्ञान (2) ।
9 डूबा हुआ, छिपा हुआ (2) ।
10 प्रकाश (3) । 12 अन्न त्याग (4) ।
15 पुकारा जाना, संदेश भेजना (4) ।
17 विशाल (3) । 18 बगैर, अतिरिक्त, (2) । 20 वर्ष का बारहवां भाग (2) ।
23 दाग, धब्बा (3) । 24 काठ, ईंधन (3) । 25 सिखों के पहले गुरु (3) ।
26 आ पहुंचना, आगमन (2) ।

ऊपर से नीचे :
1 तह, स्तर (3) । 2 सोचना, विचार करना (3) ।
3 प्रार्थना पत्र, निवेदन (4) ।
4. वृक्ष का जमीन के नीचे का भाग (2) ।
5. खेत जोतने का यंत्र (2) ।
8. कोमल, बारीक, पतला (3) ।
11. कार्य में लगना (3) ।
12. उत्तर-पूर्वी एक भारतीय राज्य (3) ।
13. लाभ, फायदा (2) ।
14. अवसर की प्रतीक्षा, घात (2) ।
16. अरुणता, ललाई (3) ।
18. भड़कना, फटना, घायल होना (4) ।
19. आंख के ऊपर का पतला आवरण (3) ।
21. भरना, अंटना (3) ।
22. नैतिक आचरण और व्यवहार (2) ।
23. जंजीर, कठिनाई, मुसीबत (2) ।

कल का हल

■	का[1]	प[2]	ना	■	उ[3]	जा[4]	ड़	ना	■
सु[5]	■	ह	■	■	म[6]	त	■	■	अ[7]
कु	■	ला[8]	वा	रि[9]	स	■	श[10]	प	थ
मा[11]	ली[12]	■	■	या	■	■	ह	■	क
र[13]	ह	न[14]	■	स[15]	ह[16]	ला	ना	■	■
■	■	सी[17]	मां	त	क	■	ई[18]	शी[19]	न[20]
वि[21]	■	ह	■	■	ला	■	■	ह[22]	क
रा[23]	ह	त	■	अ[24]	ना	चा	र[25]	■	च
ट	■	■	आ[26]	ज्ञा	■	■	क्ष	■	ढ़ा
■	स[27]	मा	धा	न	■	प[28]	क	ड़	■

जागरण सुडोकू-3060

	9			3		5	6	
	1			9	8		7	
7		5	2					4
3			1			6		8
	4	1			6		9	
9				5	2			3
			9					
	2	9		1			3	7
5	7			2	4		1	9

कल का हल

7	1	2	9	6	4	3	8	5
9	8	4	1	3	5	2	7	6
3	6	5	2	7	8	9	4	1
6	9	3	8	5	1	7	2	4
5	7	8	4	2	6	1	9	3
4	2	1	3	9	7	5	6	8
1	3	6	7	4	9	8	5	2
2	5	7	6	8	3	4	1	9
8	4	9	5	1	2	6	3	7

राष्ट्रीय फलक

असम की फिल्म अभिनेत्री हिट एंड रन मामले में गिरफ्तार

गुवाहाटी, प्रेट्र : असमिया फिल्म अभिनेत्री नंदिनी कश्यप को बुधवार को हिट एंड रन मामले में गिरफ्तार किया गया। दुर्घटना में एक 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई। गुवाहाटी पुलिस उपायुक्त (यातायात) जयंत सारथी बोरा ने बताया कि अभिनेत्री को मंगलवार को हिरासत में लिए जाने के बाद देर रात करीब 1.30 बजे गिरफ्तार किया गया। हमने उन्हें अदालत में पेश किया और पांच दिनों की रिमांड मांगी। अदालत के आदेश का इंतजार कर रहे हैं।

दुर्घटना शुक्रवार तड़के दक्खिनगांव इलाके में हुई, जब कथित तौर पर अभिनेत्री द्वारा चलाई जा रही एक एसयूवी से एक दोपहिया वाहन को टक्कर लग गई। दोपहिया चालक समीउल हक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें गुवाहाटी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल ले जाया गया। वहां से अपोलो अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, उनकी मृत्यु हो गई। डीसीपी ने कहा कि प्रारंभिक एफआइआर में अभिनेत्री का नाम नहीं था। पहले की धाराएं जमानती थीं। हालांकि, पीड़ित की मौत के बाद गैर-जमानती धाराएं जोड़ दीं और गिरफ्तार कर लिया।

राजस्थान के खास लाल पत्थर से तैयार होगा पुनौराधाम में मां जानकी मंदिर

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना

अयोध्या में श्रीराम मंदिर की तर्ज पर बिहार में सीतामढ़ी जिला अंतर्गत पुनौराधाम में मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूरे मंदिर का निर्माण खास किस्म के सैंड स्टोन (बलूआ पत्थर) से होगा। इन पत्थरों का रंग लाल होगा। सभी पत्थर राजस्थान के वंशी पहाड़पुर से मंगाए जा रहे हैं। इससे पूरे मंदिर का स्वरूप एक समान दिखेगा। पर्यटन विभाग के स्तर से टेंडर निकालकर इसके निर्माण से संबंधित गतिविधि शुरू कर दी गई है। मंदिर के करीब 11 महीने में तैयार हो जाने की संभावना है। पहले से मौजूद पौराणिक मंदिर के पास ही 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर नए मंदिर परिसर का निर्माण कराया जाएगा। इस विशाल परिसर में 151 फीट ऊंचाई का भव्य मंदिर तैयार होगा।

इस अद्भुत मंदिर के निर्माण पर 882 करोड़ 87 लाख रुपये की लागत आने की संभावना है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम पर इसके देखरेख की पूरी जिम्मेदारी है। मौजूदा कार्ययोजना के मुताबिक, मंदिर की वर्तमान संरचना पर भी 137 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च होगा।

882 करोड़ की लागत से 67 एकड़ भूमि में तैयार होगा 151 फीट ऊंचा भव्य मंदिर

परकोटा और यज्ञ मंडप भी

मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा पथ का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा परकोटा व यज्ञ मंडप का निर्माण होगा। संग्रहालय, कैफेटेरिया, धर्मशाला, सीता वाटिका, मार्ग प्रदर्शनी केंद्र समेत अन्य सुविधाओं का निर्माण कराया जाएगा। पुनौराधाम हिन्दुओं और सनातनियों के पवित्र तीर्थ स्थलों में एक है। मिथिला के राजा जनक की बेटी और भगवान श्रीराम की पत्नी माता सीता का जन्म स्थल के तौर पर यह विख्यात है।

महिला चिकित्सक की याद में 'अभया' रखा जाएगा लद्दाख की चोटी का नाम

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता: पर्वतारोहियों, विज्ञानियों और चिकित्सकों की एक टीम लद्दाख के लेह जिले के सुदूर त्सो-मोरीरी क्षेत्र में एक अभियान के तहत एक अनाम चोटी पर चढ़ाई करेगी। 6,105 मीटर ऊंची इस चोटी का नाम प्रतीकात्मक तौर पर 'अभया' रखा जाएगा। पिछले साल कोलकाता स्थित आरजी कर अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला चिकित्सका की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। टीम ने इस चोटी का नाम महिला चिकित्सक की याद में रखने का फैसला किया है। प्रोजेक्ट सीमा नामक इस अभियान का उद्देश्य पर्वत खोज को सामाजिक, वैज्ञानिक और विकासात्मक पहल से जोड़ना है। यह समूह हिमालय के चुनौतीपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में ग्लेशियरों, नदियों, झीलों, कृषि और जलवायु परिवर्तन पर भी अध्ययन करेगा। वरिष्ठ पर्वतारोही देबाशीष बिस्वास का कहना है कि महिला चिकित्सक की मौत ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया।

****

78 साल पुराने उर्दू में लिखे मृत्यु प्रमाणपत्र की जांच करेगी सीबीआइ

रवि अटवाल • जागरण

▸ भारत-पाक बंटवारा पीड़ित परिवार की 100 बीघा जमीन के विवाद में नया मोड़

चंडीगढ़: 1947 में भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बाद से चल रहे एक जमीन विवाद का मामला अब सीबीआइ तक पहुंच गया है। सीबीआइ को 78 साल पहले बने एक मृत्यु प्रमाणपत्र की जांच करनी है। इस संबंध में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। यह प्रमाणपत्र मलेरकोटला में बना था और उर्दू में लिखा गया है। पंजाब सरकार का दावा है कि यह प्रमाणपत्र फर्जी है और इसमें छेड़छाड़ की गई है। वहीं, इसी प्रमाणपत्र के आधार पर जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार के हक में फैसला सुनाया है।

देश के बंटवारे के समय हजारों मुस्लिम परिवार पाकिस्तान चले गए, लेकिन गुलाम मोहम्मद खान ने परिवार के साथ बसने का निर्णय लिया। पटियाला में उनकी करीब 100 बीघा जमीन को पंजाब सरकार ने एक्वायर कर लिया था। अब उनके कानूनी वारिस इस जमीन को वापस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से उन्हें जमीन या उसके बराबर मुआवजा देने के आदेश हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है।

विवाद में नया मोड़ तब आया जब पंजाब सरकार ने गुलाम मोहम्मद खान के मृत्यु प्रमाणपत्र को फर्जी करार दिया। पंजाब सरकार ने 2 नवंबर, 1947 को बने इस प्रमाणपत्र की हाल ही में मोहाली स्थित फारेंसिक लैबोरेट्री के निदेशक से जांच कराई थी। फारेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि इस प्रमाणपत्र पर ओवरराइटिंग हुई है, यानी इससे छेड़छाड़ की गई है। अब सीबीआइ जांच करेगी कि यह छेड़छाड़ किसने की है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआइ ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है।

काशी : गंगा में बनेगा फ्लोटिंग पूजा स्थल व चेंजिंग रूम

जागरण संवाददाता, वाराणसी: धर्म नगरी काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ व गंगा से है। देश-विदेश से श्रद्धालु काशी में गंगा स्नान और बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। स्नान पर्व पर यहां के दशाश्वमेध, पंचगंगा, असि, केदार, प्रयाग समेत अन्य घाटों पर विशेष भीड़ होती है। अब गंगा में पूजन-अर्चन के लिए फ्लोटिंग जेटी (एक ऐसा प्लेटफार्म है, जो पानी पर तैरता है) लगाई जाएगी। इसमें पास में ही चेंजिंग रूम भी होगा। नगर निगम पहले चरण में गंगा में चार फ्लोटिंग चेंजिंग रूम व पूजा स्थल का निर्माण कराने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो अगस्त को इसका शिलान्यास करेंगे। इस पर 1.87 करोड़ रुपये खर्च कर चार माह में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

फ्लोटिंग चेंजिंग रूम व पूजा स्थल को 73 वर्ग मीटर में डिजाइन किया जाएगा ताकि यह गंगा के जल स्तर में उतार-चढ़ाव के बावजूद स्थिर बना रहे। इससे पहले वाराणसी स्मार्ट सिटी दशाश्वमेध घाट पर फ्लोटिंग चेंजिंग रूम बना चुकी है।

रोगों से लड़ने को अमेरिका में जीन थेरेपी को मिली मंजूरी

1990 में आज ही अमेरिका में शरीर की कोशिकाओं में नए जीन डालने से संबंधित जीन थेरेपी को मंजूरी दी गई थी। इसे एडेनोसिन डेमिनेज की कमी (एक आनुवंशिक रोग जो प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है) और कैंसर के इलाज के लिए शुरू किया गया था।

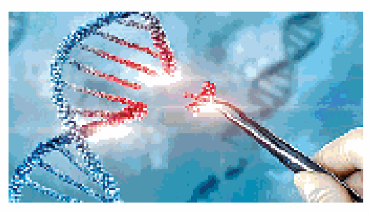

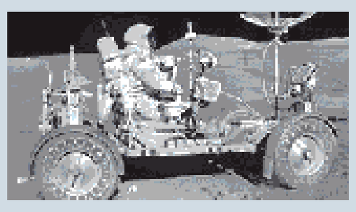

चंद्रमा पर वाहन चलाने वाले पहले व्यक्ति बने डेव स्काट

1971 में आज ही डेव स्काट चंद्रमा पर वाहन चलाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। अपोलो 15 मिशन के दौरान उन्होंने बैट्री से चलने वाला लूनर रोवर वाहन चलाया था। रोवर ने 28 किमी यात्रा की और वापसी के लिए लगभग 76 किलोग्राम चंद्र सामग्री एकत्र की।

राजनीतिक कार्टून के जनक माने जाते हैं केशव शंकर

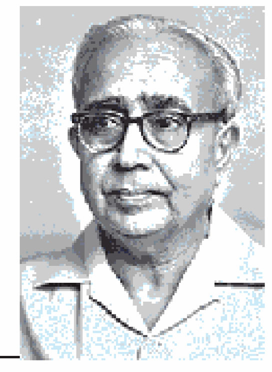

केशव शंकर पिल्लई का जन्म 1902 में आज ही केरल में हुआ। 1932 में बतौर कार्टूनिस्ट करियर की शुरुआत की और विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर हास्यप्रद कार्टून बनाकर लोकप्रियता हासिल की। 1948 में शंकर्स वीकली की स्थापना कर सामाजिक-राजनीतिक टिप्पणियों के लिए मंच तैयार किया। बच्चों के प्रति विशेष लगाव के कारण, 1949 में अंतरराष्ट्रीय बाल-चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। 1957 में चिल्ड्रेंस बुक ट्रस्ट की स्थापना की। दिल्ली में उनके द्वारा स्थापित अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय बच्चों के प्रति उनके लगाव का ही प्रतीक है।

जागरण विशेष

अब जैविक पट्टी से आसानी से जोड़ी जा सकेंगी टूटी हड्डियां

मृत्युंजय मिश्र • जागरण

विज्ञानियों ने अंडे की सफेदी, मछली के जिलेटिन व धान की भूसी से बनाया विशेष मिश्रण बीईएसजी

प्रयागराज: अंडे की सफेदी और मछली की हड्डियों से निकला जिलेटिन और धान की भूसी का उपयोग करके अब मनुष्य की हड्डियों को जोड़ा जा सकेगा। इस प्रक्रिया में न केवल उपचार का समय कम होगा, बल्कि मरीजों की परेशानी भी घटेगी। यह खोज विशेष रूप से उन मरीजों के लिए लाभकारी होगी जो फ्रैक्चर, डेंटल इम्प्लांट या आस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और नैनो माइक्रोबायोलाजिस्ट डा. अमित दुबे तथा इवि के जैव रसायन विभाग की शोध छात्रा आयशा तुफैल के नेतृत्व में विज्ञानियों की टीम ने यह विशेष जैविक मिश्रण तैयार किया है। इसे बायोएक्टिव बाईफेसिक कैल्शियम फास्फेट-एग व्हाइट-नैनोसिलिका-जिलेटिन कंपोजिट्स (बीईएसजी) नाम दिया गया है। शोध का प्रकाशन प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिका 'एसीएस एप्लाइड इंजीनियरिंग मैटेरियल्स' में हुआ है।

चेन्नई में कार्यरत डा. अमित दुबे ने बताया कि यह नई सामग्री 'जैविक पट्टी' के रूप में टूटी हुई हड्डी के स्थान पर लगाई जाएगी, जिससे यह शरीर की प्राकृतिक कोशिकाओं को बढ़ने और नई हड्डी बनाने में सहायता करेगी। जैसे बेल को चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, यह सामग्री हड्डी की कोशिकाओं को विकसित होने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। इसकी स्पंजी और छिद्रयुक्त बनावट कोशिकाओं और पोषक तत्वों को आसानी से फैलने की अनुमति देती है, जिससे उपचार की प्रक्रिया तेज होती है। समय के साथ यह सामग्री शरीर में घुलकर नई मजबूत हड्डी बना देती है। कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता।

इस जैविक पदार्थ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बेकार मानी जाने वाली चीजों का उपयोग किया गया है, जिससे यह न केवल सस्ता बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी बनता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इससे हड्डी के इलाज की लागत में कमी आएगी और यह तकनीक देश के दूरदराज इलाकों में भी उपलब्ध कराई जा सकेगी। कंप्यूटर माडलिंग विश्लेषण में इसे गैर विषाक्त और पूरी तरह जैव-संगत पाया गया है, जो भविष्य के क्लिनिकल उपयोग के लिए एक बड़ी आशा है।

हड्डी कमजोर करने वाली बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए उपयोगी

डा. अमित दुबे कहते हैं कि सामग्री को जैविक प्रभावों की कसौटी पर भी परखा गया और इसके परिणाम बेहद उत्साहजनक रहे। चूहे की अस्थि मज्जा कोशिकाओं पर हुए प्रयोगों में यह सामग्री कोशिका वृद्धि, चयापचय और हड्डी निर्माण में असाधारण रूप से प्रभावी साबित हुई। अल्कलाइन फास्फेटेस गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो हड्डी निर्माण का एक मुख्य सूचक है। इसकी संपीड़न शक्ति 4.51 मेगापास्कल रही और 66 प्रतिशत से अधिक छिद्रता इसे हड्डी की प्राकृतिक बनावट जैसा बनाती है। इस जैविक पट्टी को लगाने से कोशिकाएं तेजी से बढ़ने के साथ शरीर खुद-ब-खुद हड्डी की मरम्मत करने लगा। यह तकनीक खासकर उन मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो फ्रैक्चर या दुर्घटना के शिकार हैं। डेंटल इम्प्लांट करवा रहे हैं या फिर आस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डी कमजोर करने वाली बीमारी से जूझ रहे हैं।

प्रयोगशाला में काम करते डा. अमित दुबे • सौ. स्वयं

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

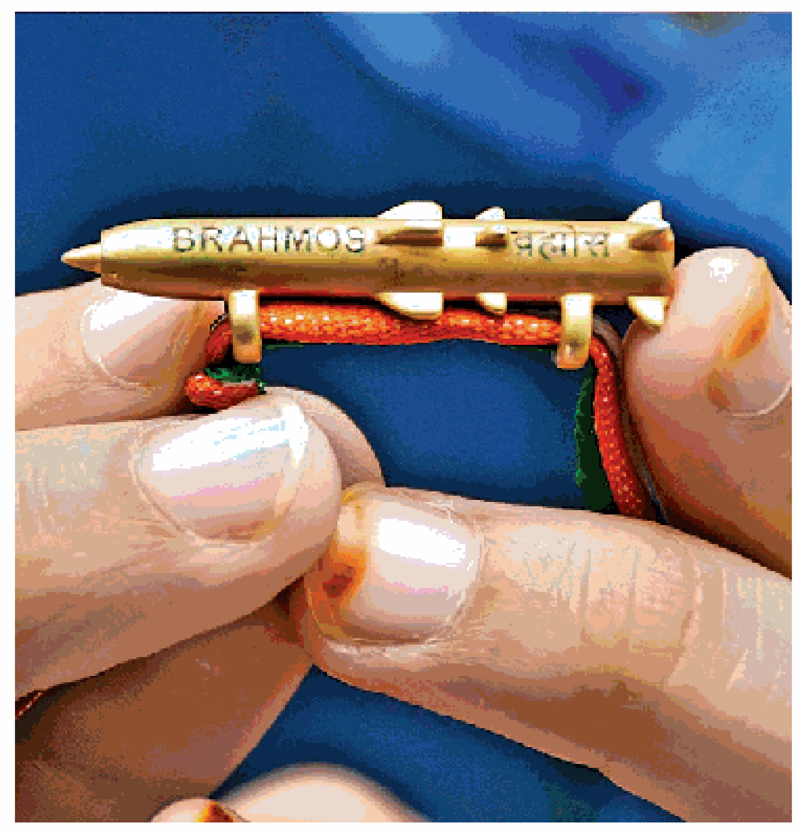

ब्रह्मोस राखी

रक्षाबंधन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और बाजारों में एक से बढ़कर एक राखियां दिखने लगी हैं। सूरत में एक दुकान में सोने से बनी हुई यह राखी काफी चर्चा बटोर रही है क्योंकि यह ब्रह्मोस मिसाइल के आकार में है। एएनआइ

इधर-उधर की

संपत्ति के लिए लड़ रहे थे, निकले गोद लिए हुए

बीजिंग, एजेंसी: चीन में एक व्यक्ति और उसकी बहन के बीच पैतृक संपत्ति विवाद ने उस समय नाटकीय मोड़ ले लिया जब उन्हें पता चला कि वे दोनों ही गोद लिए हुए हैं। परिवार के मुखिया, सन ने मार्च में निधन से पहले अपनी 3.6 करोड़ रुपये (30 लाख युआन) की संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दी थी। बेटी ने कोर्ट में फैसले को चुनौती दी। इसी बीच बहन के हाथ परिवार से जुड़ा एक दस्तावेज लग गया जिसमें उसके भाई के नाम के आगे गोद लिया गया लिखा था। दरअसल सन ने दोनों बच्चों को गोद लिया था लेकिन केवल बेटी के गोद लेने की बात को ही सार्वजनिक किया था। कोर्ट में खुलासे को सुनकर भाई रो पड़ा और बहन को उचित राशि देने को तैयार हो गया।

बहन से सच सुनकर कोर्ट में रो पड़ा भाई। इंटरनेट मीडिया

जलवायु परिवर्तन बढ़ा सकता है दस्त का खतरा

अध्ययन ▶ आठ एशियाई देशों के सर्वेक्षण से तीन मिलियन से अधिक बच्चों के डाटा का किया विश्लेषण

अधिक तापमान और वर्षा की कमी जैसे जलवायु संबंधित कारकों का देखा गया प्रभाव

नई दिल्ली, प्रेट्र : जलवायु परिवर्तन पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दस्त के खतरे को बढ़ा सकता है। यह जानकारी आस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं की ओर से किए गए एक अध्ययन के बाद सामने आई है। शोधकर्ताओं ने इस दौरान बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे आठ एशियाई देशों के राष्ट्रीय सर्वेक्षणों से तीन मिलियन से अधिक बच्चों के डाटा का विश्लेषण किया जिसमें भारत में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दस्त की प्रचलन दर लगभग 8 प्रतिशत पाई गई।

पर्यावरण अनुसंधान पत्रिका में प्रकाशित निष्कर्षों में तापमान की चरम सीमाओं और वर्षा में कमी को बच्चों में दस्त के उच्च जोखिम के दो मुख्य जलवायु-संबंधित कारकों के रूप में उजागर किया गया है। अधिक तापमान (30 से 40 डिग्री सेल्सियस) के दौरान बच्चों में दस्त के जोखिम में 39 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई जबकि सामान्य से कम वर्षा (600 मिलीमीटर से कम) ने जोखिम को लगभग 30 प्रतिशत बढ़ा दिया। इसके अलावा, जिन माताओं की शिक्षा आठ वर्ष से कम थी, उनके बच्चों को दस्त का 18 प्रतिशत अधिक जोखिम था। प्रमुख शोधकर्ता सैयदा हीरा फातिमा ने कहा कि शिक्षा माताओं को अपने बच्चों के बीमार होने पर जल्दी कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाती है जो जीवन बचा सकती है। वहीं सह-लेखक कोरी ब्रैडशा ने बताया कि दस्त के कारण होने वाली 88 प्रतिशत मौतें अस्वच्छ परिस्थितियों से जुड़ी हैं जिसमें असुरक्षित पेयजल भी शामिल है। आगे जोड़ा कि पेयजल तक बेहतर पहुंच दस्त के जोखिम को 52 प्रतिशत तक कम कर सकती है जबकि बेहतर स्वच्छता सुविधाएं जोखिम को 24 प्रतिशत तक घटा सकती हैं।

लेखकों ने यह भी कहा कि गरीबी दस्त के जोखिम को बढ़ाती है क्योंकि यह पोषण, स्वच्छ पानी और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को सीमित करती है जबकि ऐसे वातावरण को भी बढ़ावा देती है जहां दस्त के रोगाणु पनपते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन खाद्य आपूर्ति को भी प्रभावित कर सकता है जिससे कुपोषण और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली हो सकती है। लिहाजा बच्चे दस्त जैसी बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और सही होने में समय लगता है।

▶ पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में पाई गई लगभग 8 प्रतिशत दस्त की प्रचलन दर

▶ 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के दौरान दस्त के जोखिम में देखी गई 39 प्रतिशत की वृद्धि

प्रतीकात्मक

नशे की लत जैसा है चिप्स, कुकीज और कोल्ड ड्रिंक का सेवन

अनुसंधान

आजकल चिप्स, कुकीज जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। एक अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि इनका सेवन नशे की लत वाले व्यवहार को जन्म दे सकता है। शोधकर्ताओं ने तर्क दिया कि निदान प्रणालियों में इसकी पहचान न करना एक खतरनाक चूक है जिसके वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम होंगे। अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रोफेसर और प्रमुख लेखक एशले गियरहार्ट ने कहा कि लोग सेब या ब्राउन राइस के आदी नहीं हो रहे। लोग ऐसे औद्योगिक उत्पादों से जूझ रहे हैं जिन्हें विशेष रूप से मस्तिष्क पर दवा की तरह तेजी से और बार-बार असर डालने के लिए तैयार किया गया है। यह शोध जर्नल नेचर मेडिसीन में प्रकाशित किया गया है। इसके लिए 36 देशों में लगभग 300 अध्ययनों से साक्ष्य संकलित किए गए। उनके निष्कर्षों से यह पता चला कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स मस्तिष्क के पुरस्कार प्रणाली को हाइजैक कर सकते हैं, जिससे क्रेविंग, नियंत्रण न कर पाना और हानिकारक परिणामों के बावजूद निरंतर उपयोग करना जारी रखा जाता है, जो लत के प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा न्यूरोइमेजिंग अध्ययनों से पता चलता है कि इन खाद्य पदार्थों का लगातार उपयोग करने वाले व्यक्तियों के मस्तिष्क सर्किट में व्यवधान दिखाई देता है जो शराब और कोकीन की लत के समान ही होता है। दोनों ही स्थितियों को नियंत्रित करने वाली दवाएं भी एक समान पाई गईं। (आइएएनएस)

स्क्रीन शाट

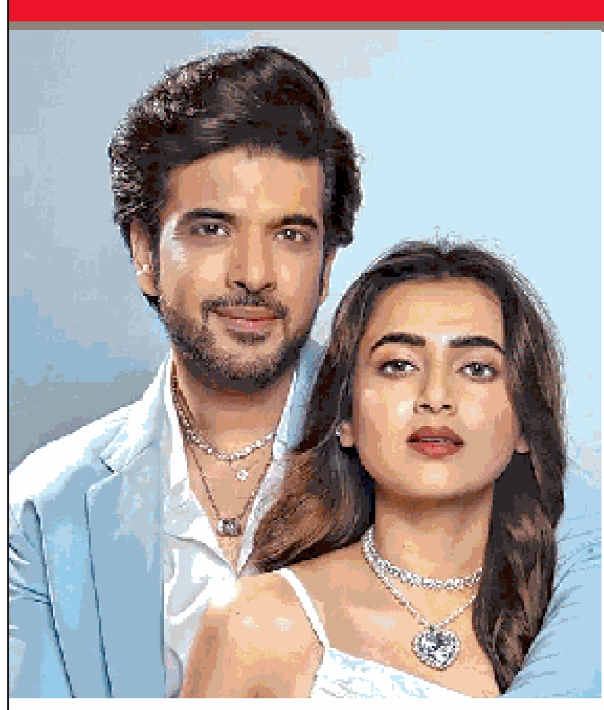
करण और तेजस्वी की है लोकप्रिय टीवी जोड़ी। फाइल

करण से शादी पर बोली तेजस्वी

कब क्या कहना है क्या नहीं, इन चीजों से सितारे बखूबी वाकिफ होते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि यह कला उनके परिवार वालों को आती हो। कई बार उनसे जब सवाल कर लिया जाता है तो वह घुमा फिराकर उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। ऐसा ही कुछ कह दिया था टीवी अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश की मम्मी ने रियलिटी शो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ इंडिया में। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी और उनके ब्वायफ्रेंड व अभिनेता करण कुंद्रा इस साल शादी कर सकते हैं। अब इस पर चुप्पी तोड़ते हुए तेजस्वी ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि शादी की बात करने के लिए उन्हें शो के क्रिएटिव से जुड़े लोगों ने कहा था। जब मैंने मां से पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा, इतना सीधा बयान देने की वजह पूछी तो उन्होंने बोला कि क्रिएटिव वालों ने बोलने के लिए कहा था इसलिए मैंने कह दिया। मैंने उन्हें कहा कि ऐसा नहीं कह सकती हो। जब मां ने ऐसा शो पर कहा तो मैंने उनकी तरफ देखकर सोचा कि हमारी तो इस बारे में कोई बात भी नहीं हुई थी। मैंने कहा कि ठीक है, फिर से ऐसे मत बोलना। मुझे लगा था कि वह छोटी सी बात है, एपिसोड में आकर निकल जाएगी लेकिन लोगों ने तो उसी बात को उठा दिया। फिर मुझे लगा कि ऐसा तो कुछ सोचा ही नही है।

अब बड़े स्तर की फिल्म निर्देशित करने की तैयारी कर रहे हैं अनुपम खेर

साल 2002 में फिल्म ओम जय जगदीश का निर्देशन करने के करीब 23 साल बाद अभिनेता अनुपम खेर ने हालिया प्रदर्शित फिल्म तन्वी द ग्रेट निर्देशित की। हालांकि, इसके बाद उनका इरादा एक बड़े स्तर की फिल्म निर्देशित करने का है। बुधवार को उन्होंने मुंबई में अपनी चौथी किताब डिफरेंट बट नो लेस लांच किया। यह किताब फिल्म तन्वी द ग्रेट बनने की राह में आई चुनौतियों और विभिन्न पड़ावों पर आधारित है। इस दौरान बतौर निर्देशक अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर अनुपम ने कहा, 'कुछ कहानियों पर पहले से ही काम चल रहा है। मैंने बतौर अभिनेता दो-तीन फिल्में पूरी कर ली है। अगले साल मैं एक बड़े स्तर की फिल्म के बारे में विचार कर रहा हूं। उसका कैनवस बड़ा होगा, कहानी बड़ी होगी।' इस दौरान अनुपम ने हालीवुड अभिनेता राबर्ट डी नीरो से अपनी फिल्म के लिए मिली प्रशंसा की भी बात की। उन्हें भारत बुलाने के सवाल पर अनुपम ने कहा कि कुछ भी हो सकता है। अपनी किताब के बारे में अनुपम ने बताया कि इस किताब को लिखने में छह-सात महीनों से ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि इस फिल्म को बनाने के साथ-साथ ही हम इस किताब को लिखने का भी काम कर रहे थे। मैं यह किताब फिल्म रिलीज होने से एक महीने पहले ही लाना चाहता था लेकिन फिर उसमें विलंब हो गया। बीच में कुछ स्क्रीनिंग आ गई फिर कुछ तस्वीरों की समस्या आ गई।

अनुपम ने लांच की अपनी किताब डिफरेंट बट नो लेस। फाइल

आठ साल की डांसर आध्याश्री को याद आती है असम की हरियाली

अपना शहर छोड़कर कई बार अपने सपनों को पूरा करने के लिये दूसरे शहर जाना पड़ता है लेकिन अपनी शहर की कुछ बातें अक्सर याद आती रहती हैं। आठ साल की आध्याश्री उपाध्याय भी असम की हरियाली को मुंबई में बहुत याद करती हैं। सोनी टीवी के डांस रियलिटी शो सुपर डांसर 5 में शिल्पा शेट्टी की चहेती आध्याश्री को मुंबई पसंद है लेकिन असम भी खूब याद आता है। इस छोटी सी उम्र में बड़ी-बड़ी बातें करने वाली आध्याश्री कहती हैं कि असम में मैं हरियाली के बीच पली-बढ़ी हूं। वहां टी गार्डन है, हर तरफ हरियाली है। मुंबई मुझे पसंद है लेकिन अगर वो हरियाली यहां होती तो यह मेरी सबसे पसंदीदा जगह बन जाती। जब कई बार आते-जाते देखती हूं कि लोग पेड़ काट रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अगर कभी पेड़ की छांव में बैठने का मन हुआ तो यहां तो पेड़ ही नहीं हैं। आगे अपने डांस से जजेस का दिल जीतने वाली आध्याश्री शो जीतने के सवाल पर कहती हैं कि मैं अपने गांव से यहां तक पहुंची हूं, वही बहुत बड़ी बात है। इस शो में मैं आगे तक जाना चाहती हूं। बाकी जहां तक जीत या हार की बात है तो मैं यही मानती हूं कि जो होता है, अच्छे के लिए होता है। कभी नर्वस होती हूं तो मम्मी यही कहती हैं कि हारने से भी सीख मिलती है कि जहां गलती हो, उसे सुधारो। फिर आगे अच्छा होगा।

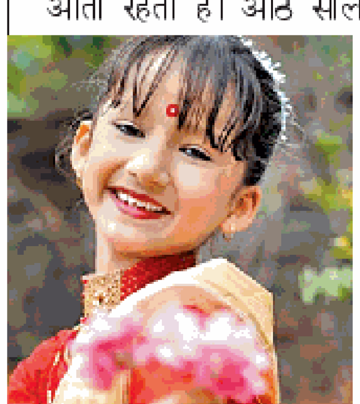
असम से हैं आध्याश्री। फाइल

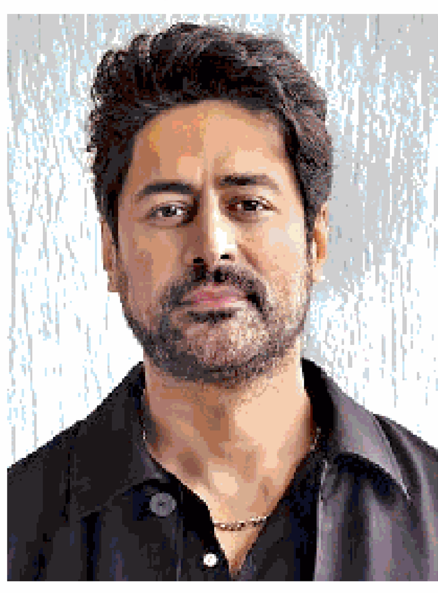
शाट में गड़बड़ हो जाए तो अपनी बात कहने से नहीं चूकते हैं मोहित। फाइल

होटल जाने के बाद जब बेचैन हो गए थे मोहित रैना

निर्देशक को प्रोजेक्ट का कप्तान माना जाता है। निर्देशक के निर्देशों के अनुसार, सेट पर लोगों को काम करना होता है। कहानी को लेकर उनका अपना विजन होता है। यूं तो कलाकार निर्देशक के काम में दखलअंदाजी नहीं करते है लेकिन अगर खुद के सीन में कमी लगे तो कहना सही होता है। इसलिए अभिनेता मोहित रैना अपनी बात रखने से बिल्कुल नहीं सोचते हैं। किसी डायलाग या शूटिंग करते समय अगर स्क्रिप्ट में उन्हें दिक्कत महसूस हुई है तो उन्होंने उसमें बदलाव करवाए हैं। मोहित कहते हैं कि मैं बोल देता हूं, जब लगता है कि बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दी है जो बहुत कम होता है लेकिन जरूर बोलता हूं। जैसे कनखजूरा वेब सीरीज के लिए हम गोवा में शूटिंग कर रहे थे, मेरा पहला ही दिन काफी कठिन सीन था, पैकअप हो गया। होटल जाकर महसूस हुआ कि गड़बड़ हो गई है। मैंने निवेदन किया कि फुटेज देख सकता हूं तब देखने के बाद समझ आ गया कि कहां गलती हुई है। जिस बंगले में हम शूटिंग कर रहे थे, वह बंगला हमारे पास सात-आठ दिन के लिए उपलब्ध था तो मैंने निर्देशक से निवेदन किया कि सीन को बेहतर कर सकते हैं। वह समझ गए थे। किसी भी पात्र में कलाकार को जाने के लिए तीन-चार दिन का समय लग जाता है। मैं निर्देशक से खुलकर बोल देता हूं। अगर संभव होता है तो दोबारा शूट भी कर लेते हैं लेकिन जहां संभव नहीं है वहां आपको संतोष करके रह जाना होता है।

@iamsunnydeol

फिर एक्शन फिल्म करने की तैयारी में सनी देओल

फिल्म का निर्देशन बालाजी करेंगे। वह कई तमिल फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम कर चुके हैं

इस साल फिल्म जाट में नजर आए अभिनेता सनी देओल फिर एक्शन फिल्म करने की तैयारी में हैं। खबरें हैं कि फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ सनी एक्शन थ्रिलर फिल्म करने जा रहे हैं। सिनेमाई गलियारों की खबरों के मुताबिक सनी पहली बार एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ एक्शन फिल्म के लिए काम कर रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन बालाजी करेंगे, जो निर्देशन में पदार्पण कर रहे हैं। वह इससे पहले कई तमिल सुपरहिट फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम कर चुके हैं। बताया जाता है कि सनी और प्रोडक्शन हाउस के बीच बातचीत चल रही थी और अब दोनों पक्ष आधिकारिक तौर पर सहमत हो गए हैं। फिल्म का शीर्षक फिलहाल तय नहीं है। सनी को स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है।

सुष्मिता से जुड़ना पसंद है: रोमान

कई बार प्यार का रिश्ता जब नहीं चलता, तो वह दोस्ती की शक्ल ले लेता है। ऐसा ही कुछ अभिनेत्री सुष्मिता सेन और अभिनेता रोमान शाल के बीच भी हुआ था। दोनों कुछ समय तक प्यार के रिश्ते में रहे, फिर दोनों अलग हो गए। हालांकि रोमान और सुष्मिता की दोस्ती बरकरार रही। हाल ही में रोमान ने अपने और सुष्मिता की दोस्ती के सात साल पूरे होने पर सुष्मिता के साथ अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा की थी और लिखा कि हमारे बीच जो प्यार था और जो दोस्ती है, वह बनी रही। इस पर एक यूजर ने रोमान को लिखा कि आप फ्रेंड जोन में हैं। इससे बाहर निकलिए और खुद को संभालिए। आप अकेले मिस यूनिवर्स की परछाई बनकर जीने से कहीं ज्यादा कर सकते हैं। इसका जवाब देते हुए रोमान ने लिखा, 'किसी असाधारण व्यक्ति के साथ जुड़ना, मुझे कम नहीं करता, बल्कि यह दर्शाता है कि मैं किस तरह के लोगों के साथ चलना पसंद करता हूं। गैलेक्सी (आकाशगंगाएं) परछाई नहीं डालती, वो एक साथ चमकती हैं। बहुत सारा प्यार।'

@rohmanshawl

सेट पर बच्चे की तरह रहते हैं बिग बी

हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन की सक्रियता और जिज्ञासा युवा कलाकारों के लिए प्रेरणा का विषय है। फिल्मकार विकास बहल ने उन्हें वर्ष 2022 में फिल्म गुडबाय में निर्देशित किया था। उसके बाद विकास ने हाल ही में गेम शो केबीसी 17 के कैंपेन जहां अकल वहां अकड़ में भी बिग बी को निर्देशित किया। वह कहते हैं, 'अमिताभ जी सेट पर उसी बच्चे की तरह रहते हैं जो खुद सीखना और हमेशा अपना कुछ योगदान देना चाहता है। उनके साथ आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वह 50 साल से ज्यादा समय से इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। हर प्रोजेक्ट उनके लिए एक-सा महत्वपूर्ण रहता है। हर बार वह उतनी ही तैयारी और रिहर्सल के साथ, उतने ही नर्वस होते हैं जितना कोई कलाकार पहली बार सेट पर कदम रखते समय होता है।'

टीम विकास बहल

@thejohnabraham

रोहित के साथ पांच एक्शन सीन करेंगे जान

गोलमाल और सिंघम जैसी फिल्मों में एक्शन व स्टंट में अपनी जबरदस्त पकड़ दिखा चुके फिल्मकार रोहित शेट्टी अब मुंबई के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया की बायोपिक बना रहे हैं। फिल्म में अभिनेता जान अब्राहम राकेश मारिया की भूमिका में हैं। एक्शन की तरह रोहित इस फिल्म में ड्रामा और इमोशन के मामले में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते हैं। फिल्म में पांच एक्शन सीन भी होंगे। रोहित और जान ने अप्रैल में इस फिल्म की शूटिंग शुरू की थी। फिल्म के आउटडोर दृश्यों की शूटिंग लगभग खत्म हो चुकी है और अब बारी है ड्रामा और पूछताछ वाले दृश्यों की। सूत्रों के अनुसार, फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग मुंबई से सटे मीरा रोड के एक स्टूडियों में की जा रही है। स्टूडियो में इसके लिए पुलिस स्टेशन का एक सेट भी स्थापित किया गया है। इस शेड्यूल में विभिन्न अपराधियों से राकेश मारिया द्वारा की गई पूछताछ से संबंधी दृश्य शूट किए जाएंगे। उन्होंने आतंकी अजमल कसाब से भी पूछताछ की थी। एक्शन सीन की शूटिंग अगस्त के अंत तक की जाएगी।

मनोरंजन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

****